फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 01:52 उपरांत द्वितीया विक्रम संवत 2082

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

अमृत विचार

बरेली

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

लखनऊ बरेली कानपुर मुरादाबाद अयोध्या हल्द्वानी

सोमवार, 2 फरवरी 2026, वर्ष 7, अंक 69, पृष्ठ 14+4 ■ मूल्य 6 रुपये

आम बजट 2026-27

अहम बातें

एमएसएमई : ग्रोथ फंड बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एलान

ट्रेडिंग : वायदा पर एसटीटी 0.02 से 0.05 फीसदी होगी

17 कैंसर की दवाएं व 7 दुर्लभ बीमारी की दवाएं होंगी सस्ती

नए संस्थान, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी टाउनशिप

नौकरियां, कौशल और बेहतर अस्पताल को मिलेगा बढ़ावा

किसानों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें टेक सपोर्ट देगी सरकार

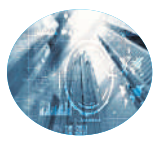

बैंकिंग और निवेश में सुधार पर फोकस

इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

7,84,678 रक्षा	2,77,830 रेलवे	1,39,289 शिक्षा	1,06,530 स्वास्थ्य	2,55,233 गृह मंत्रालय
				सभी राशि करोड़ रुपये में

टैक्स वही, सोच नई

53.5 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने 2026-27 के लिए किया पेश

बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किसानों और युवाओं पर फोकस

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने के साथ मेगा टैक्सटाइल पार्क किए जाएंगे विकसित

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ाया 2047 तक ग्लोबल लीडर बनने का लक्ष्य

85 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिखलाई भविष्य की झलक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित पांच प्रमुख राज्यों में चुनाव करीब होने के बाद भी उन्होंने लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज रखा। साथ ही सुधार एक्सप्रेस को जारी रखते हुए वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट और कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने संसद में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। छोटे उद्यमों एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अब तक के सर्वाधिक 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ इस बजट को बढ़ते वैश्विक जोखिमों के बीच वृद्धि को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा के रूप में देखा जा रहा है। सीतारमण ने छूट को युक्तिसंगत बनाकर सीमा शुल्क व्यवस्था को सरल बनाया है। इसके तहत 17 कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। बैगेज नियमों में ढील के साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

यह हुआ महंगा

- छाते और उनके पार्ट्स पर 10 प्रतिशत या 25 रुपये प्रति किलो (जो भी ज्यादा हो) ड्यूटी लगेगी
- शराब, मिनरल्स और स्क्रैप की बिक्री पर टीसीएस अब 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2% की
- क्रैनबेरी पर ड्यूटी 5 प्रतिशत और ब्लूबेरी पर 10 प्रतिशत कर दी गई है
- चबाने वाला तंबाकू, जर्दा और गुटखा पर एनसीसीडी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 कर दिया

ये हुआ सस्ता

- माइक्रोवेव ओवन के खास पार्ट्स पर अब बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं, सोलर ग्लास में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम ड्यूटी हटी
- चमड़े के निर्यात में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास इनपुट्स को ड्यूटी-फ्री आयात की सुविधा, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आयात किए जाने वाले सामान पर 2035 तक कस्टम ड्यूटी माफ
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी माफ एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ
- एविएशन सेक्टर के पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी माफ, विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस की दर घटाकर 2% कर की गई
- कपड़ा, शुगर की दवाएं, बायोगैस मिक्स्ड सीएनजी ये सारी चीजें सस्ती होंगी, मिक्स्ड गैस सीएनजी इत्यादि सस्ते होंगे।

राजकोषीय घाटा 4.3% रहने का अनुमान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 प्रतिशत रहेगा जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 4.4 % से कम है। सरकार अगले वित्त वर्ष में राज्यों को कर हस्तांतरण राशि के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये प्रदान करेगी जबकि शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है।

विस्तृत कवरेज पेज-2, 3, 4, 5, 6, 7 पर पढ़ें

छोटे उद्योगों के साथ कृषि-पर्यटन पर जोर

नई दिल्ली। निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए वैश्विक अनिश्चितता के बीच बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर को बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया जो पिछले वित्त वर्ष में 11.2 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि सरकार सात क्षेत्रों औषधि, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ-खनिज चुंबक, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और खेल सामग्री में विनिर्माण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देगी। साथ ही, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर भी जोर दिया जाएगा।

बजट में पशुधन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए भी कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई। वहीं भारत को जैव-औषधि विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कपड़ा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्गों के विकास के साथ-साथ 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास का भी प्रस्ताव किया गया। लघु उद्यमों को बढ़ावा देने और भविष्य के 'चैंपियन' तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई वृद्धि कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करने की बात कही गयी है। बजट में घोषित उपाय पिछले वर्ष आयकर में छूट और जीएसटी कटौती के पूरक हैं। इन उपायों ने बुनियादी ढांचे पर खर्च, श्रम कानून में सुधार और रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती के साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत के शुल्क का सामना करने में मदद की है। इनकम टैक्स में गलत जानकारी देना पर टैक्स की रकम के 100% के बराबर पेनल्टी के अलावा चल संपत्ति का खुलासा न करना: अब इस पर पेनल्टी लगेगी।

कांजीवरम साड़ी में वित्त मंत्री ने पेश किया बजट।

वित्त मंत्री ने बताए 3 कर्तव्य

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सरकार का विकास रोडमैप सामने रखा। उन्होंने तीन मूल कर्तव्यों गिनाए।

- **आर्थिक ग्रोथ :** सरकार का पहला कर्तव्य है भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज रखना। वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार का लक्ष्य है कि वृद्धि दर को लगातार ऊंचा रखा जाए।
- **जनता की उम्मीद :** दूसरा कर्तव्य है जनता की उम्मीदों और उनके भरोसे पर खरा उतरना। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, युवाओं के अवसर, महिला सशक्तिकरण और रोजगार ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार बजट के जरिए सीधे राहत देने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।
- **सबका साथ, सबका विकास :** सरकार का तीसरा कर्तव्य है विकास को सबके लिए समान और सुलभ बनाना। सीतारमण ने कहा कि किसी भी नीति या योजना का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे।

140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं वाला बजट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है तथा विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। मोदी ने कहा कि बजट में अवसरों की अपार संभावनाएं हैं। बजट में देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। सीतारमण ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा की नींव है। इस वर्ष का बजट भारत की सुधार एक्सप्रेस को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। भारत केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं है और यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है।

विकसित भारत के निर्माण का प्रेरणादायी संकल्प-पत्र

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह विकसित भारत के निर्माण का एक प्रेरणादायी संकल्प पत्र है। यह बजट युवाओं को अवसर, किसानों को सुरक्षा, उद्यमियों को प्रोत्साहन, मध्यम वर्ग को राहत और श्रमिकों को सम्मान प्रदान करेगा। यह बजट नवाचार, विनिर्माण और रोजगार को नई गति देने के साथ ही कृषि, ग्रामीण विकास, अवसंरचना, पर्यटन, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को सशक्त बनाते हुए 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एमएसएमई, स्टार्टअप और स्वदेशी उत्पादन को समर्थन देकर 'आत्मनिर्भर भारत' की नींव को और सुदृढ़ किया गया है।

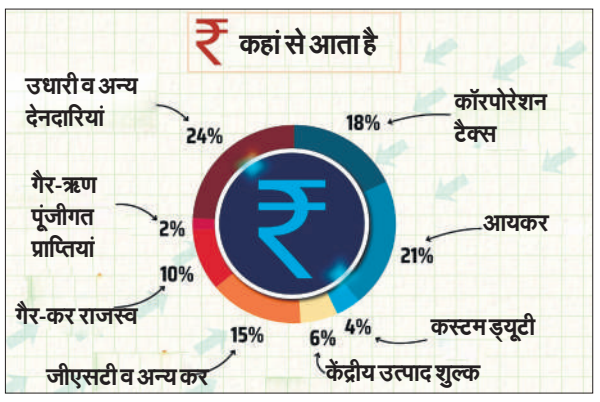

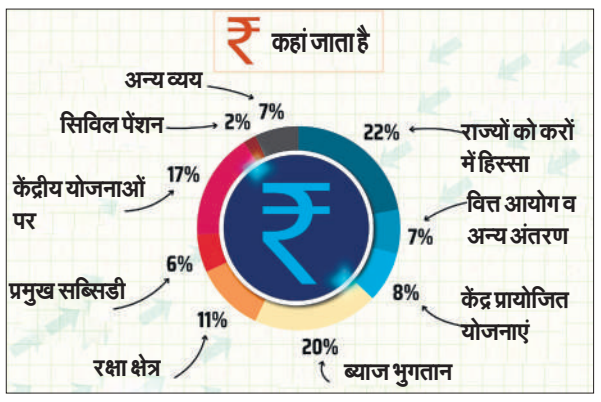

एसटीटी बढ़ोतरी से शेयर बाजार धराशायी सेंसेक्स 1,547 अंक टूटा, 9 लाख करोड़ डूबे

मुंबई। वायदा सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने की केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद रविवार को घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,547 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी 495 अंक टूटकर बंद हुआ। मार्केट में भारी बिकवाली के दबाव में निवेशकों के 9.40 लाख करोड़ रुपये डूब गए।

विश्लेषकों के मुताबिक, वित्त मंत्री का बजट भाषण में एफएंडओ खंड में सौदों पर एसटीटी को बढ़ाने का ऐलान बाजार को पसंद नहीं आया और यह बहुत तेजी से नीचे चला गया। सेंसेक्स शुरुआती बढ़त गंवाते हुए दोपहर में 80,000 अंक के अहम स्तर से भी नीचे फिसलकर 79,899.42 अंक पर खिसक गया था।

आयकर में नहीं मिली राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले जैसा

अमृत विचार, बजट डेस्क

केंद्रीय बजट में आमजन की टैक्स से जुड़ी उम्मीदों के मुताबिक, कोई ऐलान नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। लोगों को आशा थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया था। इसके मुताबिक 12 लाख रुपये सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना था। यही सीमा अब 2026-27 में भी लागू रहेगी। इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पूर्व की भांति 75 हजार ही रहेगा। ऐसे में मिडिल क्लास के हाथ खाली रह गए।

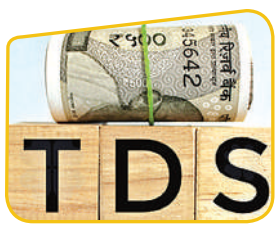

टैक्स में कुछ इन छूट का भी ऐलान

- वित्त मंत्री की बजट घोषणा के अनुसार अब किसी मोटर एक्सीडेंट क्लेम के तहत तय ब्याज को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। इस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। लेबर सर्विस को टीडीएस के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया है और इन सेवाओं पर 1 से 2 फीसदी की टीडीएस कटौती हो सकती है।

छोटे करदाताओं को राहत

वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है. अब आईटीआर फाइल करने पर कम या जीरो टैक्स कटौती सर्टिफिकेट ले सकेंगे। इसके अलावा, अलग-अलग कंपनियों के शेयर रखने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए डिपोजिट्री, निवेशक के फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच स्वीकार करने और इसे सीधे उन कंपनियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।

विदेश में घूमना, इलाज और पढ़ाई अब पहले से सस्ती

- सरकार ने विदेश घूमने वालों के लिए बड़ी राहत दी है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले टीसीएस जो पहले 5-20 फीसदी लगता था, को घटाकर सिर्फ 2 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह विदेश में मेडिकल और पढ़ाई पर होने वाले खर्च को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने टीसीएस के तहत खर्च पर ब्याज दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया है, यानी आप विदेश में अपना पैसा खर्च करते हैं तो कम ब्याज देना होगा। हालांकि, यह सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल खर्च के लिए ही मान्य होगा। इससे विदेश में पढ़ाई और इलाज अब सस्ता हो जाएगा।

आईटीआर के लिए नई डेडलाइन

अब आईटीआर-1 और 2 को भरने के लिए डेडलाइन 31 जुलाई है। नॉन-ऑडिटेड बिजनेस को आईटीआर भरने की डेडाइन 31 अगस्त तय की गई है। वहीं एनआरआई के लिए टैन की जरूरत अब समाप्त कर दी गई है। अब अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने पर निवासी खरीदार के पैन पर चालान के जरिए टीडीएस जमा किया जा सकता है।

एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि आयकर अधिनियम 2025 को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। यह छह दशक पुराने आयकर कानून का स्थान लेगा। आयकर अधिनियम-2025 के नियम तथा 'टैक्स रिटर्न' फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे, ताकि करदाताओं को इसकी आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

63,500- करोड़ रुपये बजट में किसान सम्मान निधि के लिए जारी किए गए हैं। पिछली बार भी इस योजना के लिए इतनी ही धनराशि का आवंटन किया गया था। इस तरह 6000 रुपये सालाना की किसान सम्मान निधि योजना जारी रहेगी।

वित्त मंत्री ने बजट में किया स्मार्ट फार्मिंग एआई टूल 'भारत विस्तार' का एलान

खेती में एआई क्रांति से किसान होंगे मालामाल

अमृत विचार, बजट डेस्क

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ का प्रस्ताव और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें कृषि क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एआई टूल 'भारत-विस्तार' (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज) को माना जा रहा है। यह एक बहुभाषीय एआई टूल होगा जो एग्रीस्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संसाधनों को एआई प्रणाली से जोड़ेगा। इसका मकसद किसानों को उनकी अपनी भाषा में खास सलाह देना, खेती के जोखिमों को कम करना और पैदावार बढ़ाकर बेहतर फैसला लेने में मदद करना है। इससे किसान आसानी से अपनी आय में इजाफा कर सकेंगे। एग्रीस्टैक भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसे भारत सरकार ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए एक संपूर्ण डेटाबेस बनाना है जिसमें उनकी पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास शामिल है। यह खेतों से प्राप्त डेटा और सरकारी एपीआई से मिली जानकारी का उपयोग करता है। एग्रीस्टैक के अंतर्गत विभिन्न डिजिटल उपकरणों और सेवाओं को शामिल किया जाता है। 'भारत विस्तार' का ऐलान सबका साथ विकास कर्तव्य का हिस्सा है। इसके अंतर्गत फसल चयन, मिट्टी स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, बीज-खाद और कीटनाशक की सलाह के अलावा सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन तथा ट्रैकिंग जैसी सारी जानकारी एक ही इंटरफेस पर किसान को उसकी अपनी भाषा में मिलेगी। इस तरह यह प्लेटफार्म फसल की उत्पादकता बढ़ाएगा, किसानों के बेहतर निर्णय में मदद करेगा तथा कस्टमाइज्ड एडवाइजरी से जोखिम कम करेगा।

यूनिफाइड सिस्टम और एआई चैटबॉट

भारत विस्तार एआई टूल किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई आधारित सिस्टम है, जो मौसम, फसल स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन और बाजार कीमतों की सटीक जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान करेगा। इसके तहत किसानों को एआई चैट बॉट, यूनिफाइड सिस्टम और टेस्टिंग की जानकारी दी जाएगी। कृषि साथी एआई चैटबॉट के जरिए किसान वॉयस चैटिंग कर सकेंगे और अपनी खेती संबंधित सवाल और समस्याओं के बारे में पूछ सकेंगे।इसमें वे वीडियो के जरिए भी समाधान हासिल कर सकेंगे।

कोकोनट प्रोत्साहन योजना से एक करोड़ किसानों को लाभ

भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है। एक करोड़ किसानों सहित लगभग तीन करोड़ लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल संवर्धन योजना के माध्यम से नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पुराने और कम पैदावार देने वाले पेड़ों को नए पौधों और किस्मों से बदलने का काम किया जाएगा।

20 हजार से अधिक पशु चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ेगी

पशुपालन ग्रामीण कृषि आय का करीब 16 प्रतिशत योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत किसानों की आमदनी भी शामिल है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री ने 20,000 से अधिक पशु-चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऋण-सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी योजना पेश की है। यह योजना पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, निजी कॉलेज, डायग्नोस्टिक लैब और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देगी।

पशुपालन क्षेत्र को मदद मिलने से बढ़ेगी किसान की आमदनी

1,62,671
रुपये कृषि क्षेत्र के लिए कुल आवंटन

7%
अधिक है यह राशि पिछले साल के बजट आवंटन से

पशुपालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। दुग्ध, पोल्ट्री और पशु व्यवसायों का आधुनिकीकरण होगा तथा वैल्यू चेन में किसान संगठनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार पशुधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण करके डेयरी और मुर्गीपालन के लिए संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सृजन को संवर्धित करके और पशुधन कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन देगी। बजट में रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना तैयार करने की बात भी कही गयी। इससे रेशम किसानों, भेड़ पालक किसानों और जूट की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास

- मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। इससे अंतर्देशीय मत्स्य पालन मजबूत होगा, तटीय क्षेत्रों में वैल्यू चेन विकसित होगी और स्टार्टअप, महिला समूहों तथा फिश फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों के जरिए बाजार से जुड़ाव बढ़ेगा।

कृषि से रोजगार

काजू और कोको 2030 तक बनेगा प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड

- भारत को कच्चे काजू और कोको की पैदावार व प्रसंस्करण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा निर्यात बेहतर करने के उपायों पर जोर देते हुए बजट में भारतीय काजू और भारतीय कोको को वर्ष 2030 तक प्रीमियम वैश्विक ब्रांड में मशहूर करने के लिए एक खास कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की

- बजट में केसीसी के तहत सब्सिडी वाले अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे करोड़ों किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को आसानी से सस्ता ऋण मिलने का रास्ता साफ होने से खेती-किसानी में निवेश बढ़ेगा।

सस्ती खाद को 1.71 करोड़ बनेंगे सब्जी उत्पादन क्लस्टर

- किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए 1.71 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रमुख खपत केंद्रों के पास सब्जियों के बड़े उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे ताकि आपूर्ति श्रृंखला बेहतर हो सके।

उच्च मूल्य वाली फसलों पर जोर

- सरकार ने पारंपरिक फसलों के बजाय उच्च मूल्य वाली फसलों पर जोर दिया है। इसमें नारियल प्रोत्साहन योजना, तटीय क्षेत्रों में काजू, कोको और चंदन की खेती को बढ़ावा। पहाड़ी क्षेत्रों में अखरोट, बादाम और पाइन नट्स के बागानों का आधुनिकीकरण। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों की खेती को प्रोत्साहन शामिल है।

किसानों का कल्याण केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में किसान को केंद्र में रखकर ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। कोकोनट प्रोत्साहन योजना से उत्पादन बढ़ेगा और 1 करोड़ किसानों सहित लगभग 3 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकारों के साथ मिलकर इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम के गौरव को पुनर्स्थापित किया जाएगा। कृषि संसाधनों तक किसानों की आसान पहुँच के लिए 'भारत विस्तार' नाम से एक बहुभाषी एआई आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी।

उद्योग जगत इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के निर्माण को 40 हजार करोड़ तो कंटेनर के वैश्विक इकोसिस्टम के लिए 10 हजार करोड़ रुपये

मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई बनेंगे विकसित भारत की राह में गेम चेंजर

नई दिल्ली, बजट डेस्क

केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत में मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाकर 'विकसित भारत' के लक्ष्य को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। सरकार ने 7 रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को गति देने का प्रस्ताव किया है। इसमें बायोफार्मा में अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 'बायोफार्मा शक्ति' योजना शुरू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण की योजना का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत उपकरणों और आईपी डिजाइन पर विशेष जोर दिया गया है। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीक के जरिए पुनर्जीवित किया जाएगा।ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर (रेयर अर्थ कॉरिडोर) और 3 समर्पित केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) से घरेलू बाजार में बिक्री के लिए रियायती शुल्क की सुविधा। कंटेनर विनिर्माण का अगले 5 वर्षों में वैश्विक इकोसिस्टम बनाने के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। टेक्सटाइल क्षेत्र में प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर के लिए नेशनल फाइबर मिशन और में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है।

'कॉरपोरेट मित्रों' का दस्ता एमएसएमई की करेगा मदद: सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता के लिए मझोले (श्रेणी-दो) और छोटे (श्रेणी-तीन) शहरों में 'कॉरपोरेट मित्रों' का एक दस्ता तैयार करेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' स्थायी समिति का गठन करेगी। 'कॉरपोरेट मित्रों' का यह दस्ता एमएसएमई को किफायती लागत पर अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। सरकार इस दस्ते को तैयार करने के लिए आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई जैसे संस्थानों को मॉड्यूल पाठ्यक्रम और व्यावहारिक टूल डिजाइन करने में सहयोग देगा।

एमएसएमई को 'चैंपियन' बनाने के लिए 10,000 करोड़ का कोष

200
पुराने औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे आधुनिक

10
हजार करोड़ की 'बायोफार्मा शक्ति' योजना

नयी दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को 'चैंपियन' बनाने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपना रही है जिसमें 10,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष भी शामिल है। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने इक्विटी समर्थन, नगदी समर्थन और पेशेवर समर्थन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इक्विटी समर्थन के तहत 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास कोष के माध्यम से चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- उन्होंने कहा कि एमएसएमई को तरलता समर्थन के लिए ट्रेड्स मंच की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा सभी एमएसएमई खरीदारी का लेनदेन ट्रेड्स मंच पर करना, सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी प्रदान करना और जीईएम को कारोबार के साथ जोड़कर वित्तपोषण को तेज और सस्ता बनाना शामिल है। इसके साथ ही सीतारमण ने 2021 में गठित 'आत्मनिर्भर भारत कोष' में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि डालने की घोषणा की ताकि सूक्ष्म उद्यमों को जोखिम पूंजी उपलब्ध रहे।

"भविष्य के लिए तैयार भारत" का बजट

- **नयी दिल्ली।** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय बजट को "भविष्य के लिए तैयार भारत" का बजट बताया है। उनके मुताबिक इस बजट का मकसद निर्यात और घरेलू विनिर्माण को मजबूती देना है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, महिलाएं, शिक्षा, कौशल विकास, मछुआरे, पशुपालन और नई तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। गोयल ने कहा कि अब तक करीब 350 सुधार किए जा चुके हैं और लगातार नई पहलों के जरिए सुधार की रफ्तार तेज हो रही है। बजट में डेटा सेंटर्स को अभूतपूर्व लाभ देने और 2047 तक टैक्स छूट का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे भारत को एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक हब बनाने की दिशा में सरकार की मंशा साफ झलकती है।

उद्योग जगत ने बताया दूरदर्शी और भरोसा बढ़ाने वाला बजट

- **नयी दिल्ली।** केंद्रीय बजट को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने दूरदर्शी और भरोसा बढ़ाने वाला बताया है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बजट भारत की विकास यात्रा को स्थिर और मजबूत दिशा देता है। बजट में सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र, खेल सामग्री, महत्वपूर्ण खनिज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

बजट कर अवकाश

नयी दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक 'कर अवकाश' का प्रस्ताव रखा, जो देश में स्थित डेटा सेंटर का उपयोग करके दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। यह कर अवकाश संबंधित संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन दिया जाएगा। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा, ''मैं किसी भी ऐसी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर अवकाश देने का प्रस्ताव करती हूं, जो भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्वस्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है।'' इस कर अवकाश का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को एक भारतीय पुनर्विक्रेता इकाई के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देनी होंगी।

भारत के डेटा सेंटर का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर अवकाश का प्रस्ताव

एक लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने और आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणाएं इस बार आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खास हैं। इसी के साथ भारत को चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में राज्यों को सहायता देने के लिए योजना शुरू करने की घोषणा भी देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को काफी भायी है।

स्वस्थ भारत

• स्वास्थ्य मंत्रालय को 1,06,530 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

10% पिछली बार से ज्यादा

निजी क्षेत्र की साझेदारी में बनेंगे पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 2026-27 के बजट में 1,06,530.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2025-26 के बजट के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने भारत को एक प्रमुख चिकित्सा पर्यटन गंतव्य के तौर पर बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनाने में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ये हब एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परिसर के तौर पर काम करेंगे, जिनमें चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय दूर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, बजट आवंटन को 45 करोड़ रुपये से कुछ बढ़ाकर 51 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 350 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। स्वायत्त इकाइयों के लिए बजट आवंटन 2024-25 में 21,901.98 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 22,343.97 करोड़ रुपये हो गया है।

नई दिल्ली स्थित एम्स के लिए आवंटन 5,238.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,500.92 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि आईसीएमआर के लिए 4,821.21 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए हैं, जो लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि है।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन 37,100.07 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 39,390 करोड़ रुपये किया

530.42 करोड़ रुपये में से 1,01,709.21 करोड़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा 4,821.21 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए

आयुष्मान भारत का बजट 5.6% बढ़ा

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटन 8,995 करोड़ से बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अगले पांच साल में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

नई दिल्ली। बजट में अगले पांच वर्षों में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम से देश के दवा उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 'बायोफार्मास्युटिकल्स' या 'बायोलॉजिक्स' ऐसे जटिल औषधीय उत्पाद होते हैं, जिन्हें रासायनिक संश्लेषण के बजाय जीवों, कोशिकाओं या ऊतकों से तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री ने विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा समेत छह प्रमुख क्षेत्रों के लिए ठोस पहल करने का प्रस्ताव रखा।

दस क्षेत्रों में जोड़े जाएंगे एक लाख स्वास्थ्य पेशेवर

नई दिल्ली। अगले पांच सालों में ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और एप्लाइड साइकोलॉजी समेत अलग-अलग क्षेत्रों में करीब एक लाख सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों (एएचपी) को जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि एएचपी के लिए मौजूदा संस्थानों को उन्नत किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्र में नए एएचपी संस्थान बनाए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के युवाओं के लिए कौशल वाले रोजगारों के नए रास्ते बनेंगे। इसमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, एप्लाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी सेहत समेत 10 चुने हुए क्षेत्र शामिल होंगे।

कैंसर के साथ सात अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं की कीमतें होंगी कम

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में कैंसर के साथ सात और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए रियायतों की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर की 17 दवाओं पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी यानी इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा सात और दुर्लभ बीमारियों के उपचार में काम आने वाली दवाओं के आयात शुल्क में भारी छूट दी गई है। मूलभूत सीमा शुल्क वह टैक्स है जो भारत सरकार विदेशों से आयात किए जाने वाले सामान पर लगाती है और यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत लिया जाता है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर कैंसर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के काम में आने वाली दवाओं की कीमत पर पड़ेगा।

- बुजुर्गों और सहायक देखभाल सेवाओं के लिए एक मजबूत देखभाल प्रणाली बनाई जाएगी।

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

नई दिल्ली। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और दवाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद आयुर्वेद को दुनिया भर में पहचान और मान्यता मिली। अच्छी गुणवत्ता के आयुर्वेद उत्पाद जड़ी-बूटियों की पैदावार करने वाले किसानों और इनका प्रसंस्करण करने वाले युवाओं की मदद करते हैं।

वित्त मंत्री ने बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, प्रमाणन तंत्र के लिए आयुष फार्मेसी और दवा जांच प्रयोगशालाओं को उच्च मानकों पर पहुंचाने और अधिक कुशल लोग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा, प्राचीन भारतीय योग, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही सम्मान है, को तब बड़े पैमाने पर वैश्विक पहचान मिली जब प्रधानमंत्री इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद, आयुर्वेद को भी वैसी ही वैश्विक पहचान मिली। वित्त मंत्री ने जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र को उन्नत करने का भी प्रस्ताव रखा ताकि पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

निमहांस 2.0 के साथ रांची मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरेगा

रांची। अपने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जानी जाने वाली झारखंड की राजधानी रांची को इसका पहला निमहांस मिलने जा रहा है, जो उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रांची में दूसरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस 2.0) की स्थापना की घोषणा की।

पहला निमहांस बेंगलुरु में स्थित है। शहर के दो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक केंद्र द्वारा संचालित रांची तांत्रिका और मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान 100 से अधिक वर्षों से मनोरोग देखभाल, अनुसंधान और पुनर्वास के प्रमुख केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीआईपी अधिकारियों ने कहा कि वे संस्थान को निमहांस की तर्ज पर उन्नत करने की मांग कर रहे थे। इस संस्थान की स्थापना अंग्रेजों ने 17 मई 1918 को रांची यूरोपियन लुनेटिक असाइलम के नाम से की थी। सीतारमण ने कहा, उत्तर भारत में कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं हैं। इसलिए, हम निमहांस 2.0 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नत करेंगे।

शिक्षित भारत

8.27% से ज्यादा वृद्धि

शिक्षा के क्षेत्र के लिए आम बजट 2026-27 में 1.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए 55,727 करोड़ रुपये शामिल

प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टक केंद्रों के पास देश में बनेंगी 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप

नई दिल्ली, एजेंसी

युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का उद्देश्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने में राज्यों को सहयोग देगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, 'इन प्रस्तावित शैक्षणिक क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे।

केंद्र सरकार ने बजट में शिक्षा को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखते हुए इस वर्ष 8.27 प्रतिशत से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में कुल 128650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। बजट में उच्च शिक्षा और खासतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (एसटीईएम) को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल 700 से ज्यादा जिले हैं पूरे देश में

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास (गर्ल्स हॉस्टल) स्थापित करने की घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं। सीतारमण ने पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं के लिए ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना का भी प्रस्ताव रखा। मंत्री ने आयुष औषधालयों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन तथा गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रमुख औद्योगिक ''लॉजिस्टिक'' केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।

शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता पर उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन

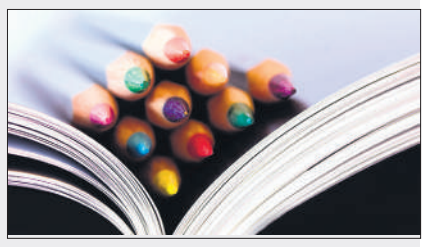

नई दिल्ली। देश को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सरकार ''शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता'' पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री ने रविवार को बजट पेश करते हुए कहा, मैं ''शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता'' पर एक उच्चस्तरीय स्थाई समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूं, जो विकसित भारत के प्रमुख प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, ताकि वर्ष 2047 तक वैश्विक सेवाओं में हमारी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत हो सके। यह समिति विकास, रोज़गार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करेगी। साथ ही, एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर आवश्यक उपायों का सुझाव देगी।

15,000 स्कूलों, 500 कॉलेजों में स्थापित की जाएंगी 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब'

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज' के तत्वावधान में 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है।

एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये

सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक उभरता हुआ उद्योग है, जिसके लिए 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा, मैं 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। केंद्रीय बजट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 4,551.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसमें से एक बड़ी राशि भारत के सार्वजनिक प्रसारक 'प्रसार भारती' के साथ-साथ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभा विकास और सामुदायिक रेडियो के विस्तार को समर्थन देने के लिए निर्धारित की गई है। एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके माध्यम से सरकार देश के युवाओं को कंटेंट क्रिएशन में अग्रणी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बजट, शिक्षा के प्रति सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है : प्रधान

नई दिल्ली, एजेंसी

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रविवार को पेश केंद्रीय बजट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में शिक्षा के बजट को बढ़ाया गया है जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।

प्रधान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बजट में नवजात शिशु से लेकर युवा तक का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी, स्कूल शिक्षा, स्किलिंग, नर्चरिंग इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप और शोध इस बजट के बड़े संकेत है। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने के लिए बजट में कई कल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में शिक्षा में बजट बढ़ाया गया है। पिछली बार की तुलना में इस बार बजट 8.27 प्रतिशत अधिक है जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।

इस बजट में भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने की कल्पना

प्रधान ने कहा कि भारत की लड़कियां विज्ञान, तकनीक और गणित की शिक्षा में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। सरकार ने इसमें और गति देने के लिए हर जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाए जाएंगे जिसमें शोध,नवाचार और ज्ञान का एक इकोसिस्टम बनेगा। अर्थ नीति को बढ़ाने के लिए उसे ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है। देश से बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों को पहले पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था उसे दो प्रतिशत किया गया जिससे छात्रों को देश के बाहर शोध करने के लिए जाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि बजट में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीआरटी) के बजट में चौदह प्रतिशत की बढोत्तरी की गई है।

2.77 लाख करोड़ में रेलवे करेगा विकास

नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ-साथ होंगे कई अन्य कार्य

नई दिल्ली, एजेंसी

- 2025-26 में 2,52 लाख करोड़ थे आवंटित वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 10.25% ज्यादा
- रेलवे की कमाई 3,85,733.33 करोड़ और खर्च 3,82,186.01 करोड़ होने का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजी व्यय के लिए रेल मंत्रालय को 2,77,830 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। बजट आवंटन में नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ अन्य कार्य शामिल हैं। मंत्रालय को वित्त वर्ष 2025-26 में 2,52,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। आने वाले वित्त वर्ष के लिए यह आवंटन 10.25 प्रतिशत ज्यादा है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इसके अलावा, मंत्रालय को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

बजट दस्तावेज के मुताबिक, रेलवे की कुल कमाई 3,85,733.33 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि खर्च 3,82,186.01 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष के आखिर में 3,547.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि क्योंकि रेलवे की कमाई इतनी कम है कि वह परिसंपत्ति बनाने और नए कामों का समर्थन नहीं कर सकती, इसलिए उसे सरकार से धन मिलता है। इसलिए, मंत्रालय को नई लाइन बिछाने, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने और सिंगल-लाइन वाले मार्गों पर डबल लाइन बनाने जैसे कार्यों के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजट दस्तावेज में विभिन्न निर्माण कार्यों और संपत्ति निर्माण परियोजनाओं के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। इनमें नई लाइन के लिए 36,721.55 करोड़ रुपये, गेज परिवर्तन के लिए 4,600 करोड़ रुपये, लाइन दोहरीकरण के लिए 37,750 करोड़ रुपये, रोलिंग स्टॉक (लोकोमोटिव, वैगन आदि) के लिए 52,108.73 करोड़ रुपये, और सिग्नलिंग तथा दूरसंचार के लिए 7,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस दस्तावेज में 2024-25 में रेलवे की वास्तविक कमाई और खर्च का ब्यौरा भी दिया गया है। साल के दौरान, रेलवे ने 3,35,757.09 करोड़ रुपये कमाए और 3,32,440.64 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे 3,316.45 करोड़ रुपये की आय हुई। उस साल के लिए बजट में 2,51,946.56 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

एक अधिकारी ने कहा कि जहां तक वित्त वर्ष 2025-26 की बात है, कमाई और खर्च के असल आंकड़े वित्त वर्ष खत्म होने के बाद ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकतर कमाई और खर्च मामूली बदलावों के साथ उम्मीद के मुताबिक ही हैं। रेलवे के कुल खर्च में से सबसे बड़ा हिस्सा उसके कर्मचारियों को पेंशन देने में जाता है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, 2024-25 में पेंशन पर खर्च 58,844.07 करोड़ रुपये था, जिसके 2026-27 में बढ़कर 74,500 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

सात हाई-स्पीड, एक फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 के केंद्रीय बजट में अलग-अलग शहरों के बीच सात हाई-स्पीड कॉरिडोर और पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत के बीच एक नए विशेष फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि पर्यावरण अनुकूल यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक, ये प्रस्तावित गलियारे मुंबई और पुणे, पुणे और हैदराबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, चेन्नई और बेंगलुरु, दिल्ली और वाराणसी तथा वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच विकसित किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि मालवहन के लिए पर्यावरण अनुकूल सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, वह पूर्वी क्षेत्र में डंकुनी को पश्चिमी हिस्से के सूरत से जोड़ने वाला एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रख रही हैं। अभी, अहमदाबाद और मुंबई के बीच एक हाई-स्पीड कॉरिडोर पर काम जारी है। इसी तरह, कई राज्यों और जिलों में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर - ईस्टर्न और वेस्टर्न का काम जारी है।

राजकोषीय घाटे की भरपाई को 17.2 लाख करोड़ का कर्ज लेगी सरकार

सरकार अगले वित्त वर्ष में 4.3% के अनुमानित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए कुल 17.2 लाख करोड़ रुपये उधार ले सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 14.80 लाख करोड़ रुपये के सकल कर्ज का अनुमान लगाया था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचत और अन्य स्रोतों से किये जाने की उम्मीद है। सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। कर्ज की राशि अधिक होने के प्रश्न पर, आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि शुद्ध बाजार उधारी 11.73 लाख करोड़ रुपये के आसपास है, जो कुछ वर्षों के आंकड़ों के करीब है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी संख्या इसलिए है क्योंकि हमें इस साल 5.5 लाख करोड़ रुपये चुकाने हैं। इसलिए, उस लिहाज से हमें यह कोई बड़ी संख्या नहीं लगती। ठाकुर ने कहा कि प्रतिभूति पुनर्खरीद और अदला-बदली का मुख्य उद्देश्य सरकार पर ऋण चुकाने का बोझ कम करना, एक साथ कई ऋण के जमा होने के प्रभाव को कम करना और लागत को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि हमने इस साल उच्च ब्याज वाली प्रतिभूतियों की महत्वपूर्ण अदला-बदली की है। अगले साल इस 5.5 लाख करोड़ रुपये को चुकाना होगा। जैसे-जैसे ये प्रतिभूतियां आती रहेंगी, हम निर्णय लेते रहेंगे। बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने कहा कि केंद्र राज्यों से उनके राजकोषीय प्रबंधन के बारे में बात कर रहा है और उनके ऋणों पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र अनुच्छेद 293(3) के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है कि राज्यों के कर्ज पर भी नजर रखी जाए। हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उनके वित्तीय प्रबंधन अधिनियम से ऊपर जाने पर हम उस पर गौर कर सकते हैं।

बजट में राजकोषीय मजबूती, पूंजीगत व्यय बढ़ने से वृद्धि को मिलेगा प्रोत्साहन

नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने बजट 2026-27 में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा की। कांत ने एक्स पर कहा कि सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को प्रभावशाली ढंग से घटाकर जीडीपी का 4.3 प्रतिशत किया है, जो 2020-21 के 9.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से एक बड़ी कमी है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन के वादे को सफलतापूर्वक निभाने के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई! इस उपलब्धि ने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था में भरोसे को मजबूत किया है, बल्कि निजी क्षेत्र को कर्ज लेने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण भी तैयार किया है। कांत ने कहा कि इस राजकोषीय मजबूती को पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ जोड़ा गया है, जिससे प्रभावी पूंजीगत व्यय अब जीडीपी का 4.4 प्रतिशत हो गया है।

लड़ाकू दक्षता बढ़ाने के लिए सेना को मिले 7.85 लाख करोड़

- रक्षा बजट में 15 प्रतिशत का इजाफा, पूंजीगत व्यय में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7,84,678 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो पिछले वर्ष के आवंटन 6.81 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। सरकार का ध्यान खासकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने पर है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के परिप्रेक्ष्य में पूंजीगत खरीद के बजट समेत रक्षा आवंटन में की गई यह वृद्धि हमारी सेना को और अधिक मजबूत बनाने के संकल्प को प्रबल बनाएगी। कुल आवंटन में से 2,19,306 करोड़ रुपये सशस्त्र बलों के पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदना शामिल है। यह पूंजीगत व्यय 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में 21.84 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय के तहत, 63,733 करोड़ रुपये विमान और एयरो इंजन के लिए और 25,023 करोड़ रुपये नौसेना बेड़े के लिए आवंटित किए गए हैं। कुल पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान 1.80 लाख करोड़ रुपये से 39,000 करोड़ रुपये अधिक है। 2025-26 का संशोधित पूंजीगत व्यय 1,86,454 करोड़ रुपये अनुमानित था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 1.39 लाख करोड़ रुपये (पूंजीगत खरीद बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा) वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान घरेलू उद्योगों के माध्यम से खरीद के लिए निर्धारित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा आवंटन अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दो प्रतिशत है और यह 2025-26 के बजट अनुमान (बीई) की तुलना में 15.19 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।

1.85 लाख करोड़ में सेनाओं के आधुनिकीकरण का प्रावधान

1.71 लाख करोड़ रुपये पेंशन के लिए व्यय करने का प्रावधान

17,250 करोड़ अनुसंधान व विकास पर होगा खर्च

12,100 करोड़ भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना के लिए

खरीदे जाएंगे 114 राफेल

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश किए गए बजट में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की रक्षा तैयारियों को आगे बढ़ाने और सेनाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। बजट में वायु सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मद्देनजर पूंजीगत बजट में अच्छी खासी बढोतरी की गयी है जो 2.19 लाख करोड़ रुपये है। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है। पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ दिए गए है जबकि पिछली बार 1.60 लाख करोड़ रुपये था। अनुसंधान और विकास के लिए भी 17250 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो पिछली बार 14923 करोड़ रुपये था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आए बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मज़बूत बनाने के सरकार के संकल्प को और सुदृढ़ किया है।

डीआरडीओ के लिए बजट कभी बाधा नहीं रहा : संयुक्त निदेशक

कोलकाता। डीआरडीओ के संयुक्त निदेशक बिनॉय दास ने कहा कि अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और हथियार प्रणालियों के डिजाइन और विकास में लगे प्रमुख सरकारी अनुसंधान संगठन के लिए बजट कभी भी बाधा नहीं रहा है। दास ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हमेशा से भरपूर सहयोग मिलता रहा है। सरकार ने हमेशा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को बिना शर्त सहयोग दिया है और बजट हमारे लिए कभी बाधा नहीं रहा है। दास के मुताबिक, डीआरडीओ से अगली पीढ़ी की ऐसी तकनीक पर काम करने के लिए कहा गया है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। उन्होंने साइंस सिटी सभागार में कहा कि हमें ऐसे उपकरणों पर काम करना होगा, जिनका हमारे सशस्त्र बल सपना देख रहे हैं। हम ऐसे उपकरणों के आयात का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आज की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और युद्ध के परिदृश्यों में समीकरण बदल गए हैं। दास को विज्ञान और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान के लिए जेआईएस महा सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि यह बजट हमें उन प्रणालियों को साकार करने और सशक्त बनाने में मदद करेगा, जिन्हें हम विकसित करते हैं। यह निर्यात के माध्यम से आर्थिक महाशक्ति बनने में सहायक होगा। पहले भारत को रक्षा प्रौद्योगिकियों के आयात से वंचित रखा गया था और आज हम आयात से इन्कार कर रहे हैं। भारत ने गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करके सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त की हैं और पूर्णत: आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में काम हो रहा है।

5000 करोड़ में सात सीईआर होंगे स्थापित

सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु, सूरत और वाराणसी सहित सात शहरी आर्थिक क्षेत्र (सीईआर) स्थापित किए हैं। इनके लिए पांच साल में प्रति क्षेत्र 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। सीतारमण ने शहरों को भारत के विकास, नवोन्मेष और अवसरों का इंजन बताते हुए कहा कि यह नई पहल मझोली और छोटे शहरों (टियर दो और तीन) के साथ-साथ मंदिर नगरों पर केंद्रित होगी, जिन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। सरकार ने बजट में दो नई योजनाओं- शहरी आर्थिक क्षेत्रों और क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों के लिए 2,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव रखा है। यह आवंटन सात शहरी आर्थिक क्षेत्रों बेंगलुरु, भुवनेश्वर-पुरी-कटक त्रिपक्षीय क्षेत्र, कोयंबटूर-ईरोड-तिरुप्पुर, पुणे, सूरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम के लिए प्रस्तावित किया गया है।

विधि मंत्रालय को ईपीआईसी के लिए मिले 250 करोड़

मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बीच बजट में विधि मंत्रालय को मतदाता पहचान पत्रों के लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव से संबंधित खर्चों के लिए 500 करोड़ अलग से दिए गए हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्रों (ईपीआईसी) पर होने वाला खर्च केंद्र और राज्यों के बीच बराबर बांटा जाता है। प्रत्येक राज्य मतदाताओं की संख्या के अनुपात में राशि का भुगतान करता है। भारत में मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 99 करोड़ है। निर्वाचन आयोग, चुनाव कानूनों, संबंधित नियमों और निर्वाचन आयोग की नियुक्तियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाले विधि मंत्रालय को 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के लिए 500 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं।

ई-अदालत परियोजना को मिला 1,200 करोड़

सभी अधीनस्थ अदालतों के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से विधि मंत्रालय की ई-अदालत परियोजना के तृतीय चरण के लिए केंद्रीय बजट में 1,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना को अनुमान के 1,500 करोड़ के मुकाबले 1,200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सितंबर 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ के वित्तीय व्यय के साथ केंद्रीय योजना के रूप में परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी थी, जिसे चार साल में लागू किया जाना है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत भारतीय न्यायपालिका को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में सक्षम बनाने के लिए 2007 से ई-अदालत परियोजना क्रियान्वयन में है। परियोजना का दूसरा चरण 2023 में खत्म हुआ।

2.5 लाख करोड़ में खुफिया तंत्र और मजबूत करेगा केंद्रीय गृह मंत्रालय

कुल धनराशि का 68% हिस्सा यानी 1.73 लाख करोड़ पुलिस मद के लिए किए गए निर्धारित

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि निर्धारित की गई है, जो 2025-26 के बजट अनुमान 2.33 लाख करोड़ की तुलना में 9.44 प्रतिशत अधिक है। बजट में गृह मंत्रालय के लिए कुल धनराशि का 68 प्रतिशत हिस्सा यानी 1.73 लाख करोड़ रुपये पुलिस मद के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें खुफिया ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, सीमा विकास कार्यक्रम, तथा दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के पुलिस बलों के लिए निधि शामिल है। केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये (बजट अनुमान) आवंटित किए गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में जम्मू-कश्मीर के लिए 43,290.29 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 1,348.0 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आंतरिक खुफिया एजेंसी आईबी को 2026-27 में 6,782.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आईबी के आवंटन में पिछले बजट की तुलना में 63 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले बजट में आईबी के लिए 4,159.1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बजट दस्तावेज में कहा गया है, यह प्रावधान खुफिया ब्यूरो के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए है, जो आंतरिक खतरों, आतंकवादी गतिविधियों और संभावित सुरक्षा जोखिमों की जानकारी एकत्रित करके और उनकी पड़ताल करके राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बजट में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 6,680.94 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ के लिए 5,720.17 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के लिए 2,832.70 करोड़ रुपये, लद्दाख के लिए 4,869.31 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप के लिए 1,682.35 करोड़ रुपये और पुडुचेरी के लिए 3,517.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए भी 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका पहला चरण एक अप्रैल से शुरू होगा।

एफएंडओ में एसटीटी वृद्धि से रोकेंगे सट्टेबाजी

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने का मकसद उच्च जोखिम वाली सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन भोले-भाले निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए किया गया, जो डेरिवेटिव बाजार में बड़ी मात्रा में पैसा गंवा रहे थे। बजट में वायदा अनुबंधों पर एसटीटी को 0.02 से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, विकल्प सौदों पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है। अब तक एसटीटी विकल्प प्रीमियम पर 0.1% और विकल्प कारोबार पर 0.125% था।

बजट के बाद सीतारमण ने कहा कि सरकार वायदा-विकल्प कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि भारी नुकसान का सामना कर रहे छोटे निवेशक सट्टेबाजी वाले एफएंडओ बाजार से दूर रहें। सीतारमण ने कहा कि यह मामूली वृद्धि पूरी तरह से सट्टेबाजी को लक्षित है। इसलिए, एफएंडओ पर एसटीटी में यह वृद्धि ऐसे निवेश को रोकने के लिए है। सेबी के अध्ययनों के अनुसार, एफएंडओ खंड में 90% से अधिक खुदरा निवेशकों को नुकसान होता है। बाजार नियामक ने इस खंड में कारोबार कम करने के लिए पहले भी कम कदम उठाए हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अत्यधिक सट्टेबाजी की गतिविधियों को हतोत्साहित करने और अधिक संतुलित बाजार संरचना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। हालांकि, कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि यह निकट अवधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी को प्रभावित कर सकता है।

12.22 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय जीडीपी का 4.4%

सीतारमण ने कहा कि 2026-27 के लिए घोषित 12.22 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4% है और अब तक का सर्वाधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2025-26 में घोषित 11.11 लाख करोड़ के बजटीय पूंजीगत व्यय से 10% अधिक है। उन्होंने कहा कि हमने घोषणा की है कि 12.22 लाख करोड़ का सार्वजनिक व्यय किया जाएगा। इस बार यह जीडीपी का 4.4% है। यह कम से कम पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है और यदि आप पिछली अवधि के आंकड़ों को भी देखें तो यह संभवत: सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.5% और 2024-25 में 4.0% था। वित्त वर्ष 2015-16 में सरकार का पूंजीगत व्यय 2.35 लाख करोड़ रुपये था। सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.3% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य यथार्थवादी है।

सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने को एसटीटी बढ़ाया : राजस्व सचिव

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि एफएंडओ खंड में एसटीटी बढ़ाने का मकसद सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना और प्रणालीगत जोखिम को संभालना है। एफएंडओ में सट्टेबाजी से छोटे और खुदरा निवेशकों को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना है, और यही वजह है कि दर में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि यह मुख्य रूप से वायदा-विकल्प बाजारों में प्रणालीगत जोखिम को संभालने के लिए है। श्रीवास्तव ने कहा कि इस वृद्धि के बाद भी एसटीटी की दरें होने वाले लेनदेन की मात्रा की तुलना में मामूली रहेंगी।

मौजूदा कीमतों पर 10% वृद्धि का अनुमान यथार्थपूर्ण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2026-27 के लिए जीडीपी में मौजूदा कीमतों पर 10% की वृद्धि का अनुमान यथार्थपूर्ण है। बजट दस्तावेज के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि को वास्तविक संदर्भ में 393 लाख करोड़ आंका गया है। वित्त मंत्री ने कहा, भारत में मुद्रास्फीति कम है और कुछ समय तक इसी स्तर पर बनी रहेगी। मुद्रास्फीति अकेला मूल्य संशोधन कारक नहीं है, लेकिन काफी हद तक आप इसी पर निर्भर करते हैं। इसलिए मौजूदा कीमतों पर जीडीपी का अनुमान यथार्थपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह 10% वृद्धि का अनुमान जीडीपी के मौजूदा आधार वर्ष और उपयोग की गई गणना पद्धति पर ही तय किया गया है। सरकार फरवरी में कई वृहद-आर्थिक संकेतकों, जैसे जीडीपी और खुदरा मुद्रास्फीति की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने जा रही है।

एसटीटी वृद्धि से पूंजी बाजार पर बढ़ेगा दबाव, विशेषज्ञों ने जताई चिंता

नई दिल्ली/मुंबई। केंद्रीय बजट 2026-27 में वायदा और विकल्प (एफएंडओ) खंड में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने पर विशेषज्ञों ने कहा कि यह कदम अल्पकालिक रूप से बाजार के लिए दबाव पैदा कर सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक धीरज रेल्ली ने कहा कि एफएंडओ में एसटीटी वृद्धि अल्पकालिक रूप से पूंजी बाजार संस्थाओं के लिए दबाव डाल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह सकारात्मक हो सकती है। एसटीटी वृद्धि को बजट भाषण के बाद शेयर बाजार में आई तेज गिरावट का कारण बताया गया। कोटक सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीपल शाह ने कहा कि एसटीटी में यह तीव्र वृद्धि व्यापारियों, जोखिम प्रबंधकों के लिए लागत बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। इसका उद्देश्य आमदनी अधिकतम करने से अधिक लेन-देन की मात्रा को नियंत्रित करना प्रतीत होता है, क्योंकि संभावित आय लाभ को वायदा विकल्पों की कम मात्रा से संतुलित किया जा सकता है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म सैमको सिक्योरिटीज ने कहा कि उच्च लेन-देन लागत से लेन-देन की मात्रा घटने, अल्पकालिक गति कमजोर होने और सक्रिय बाजार प्रतिभागियों के लिए लाभप्रदता कम हो सकती है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी अनुसंधान प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि इक्विटी एफएंडओ पर एसटीटी में वृद्धि से अल्पकालिक बाजार में असुविधा उत्पन्न हो सकती है। पुनर्खरीद (बायबैक) को पूंजीगत लाभ के रूप में मानने से एक सार्थक क्षतिपूर्ति मिलती है और दीर्घकालिक निवेशक विश्वास मजबूत होता है। एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीषकुमार चौहान ने कहा कि बजट सट्टेबाजी पर रोक के लिए वायदा और विकल्प पर उच्च एसटीटी जैसे सुनियोजित उपायों से वित्तीय बाजारों को सुदृढ़ बनाता है। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के सीईओ फेरोज अजीज ने कहा कि एसटीटी में वृद्धि से डेरिवेटिव व्यापारियों के लेन-देन की लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी जिससे उनकी रणनीतियों पर प्रभाव पड़ेगा। यह बाजार में डेरिवेटिव लेन-देन की मात्रा कम कर सकता है और निकट भविष्य में अस्थिरता ला सकता है।

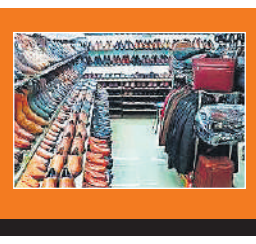

यूपी के विकास को मिलेगी रफ्तार, मिलेंगे 4 लाख करोड़ रुपये

● इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाई-स्पीड रेल, पर्यटन व सिटी इकोनॉमिक रीजन से टियर-2 व टियर-3 शहरों को मिलेगी मजबूती ● टेक्सटाइल व एआई आधारित कृषि पर फोकस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

बजट -2026

● भाजपा जहां बजट को ऐतिहासिक बता रही, वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है

अमृत विचार: आम बजट से प्रदेश को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सौगात मिलने की उम्मीद है, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर फोकस से सरकार उत्साहित है। हाई-स्पीड रेल, जल परिवहन और सिटी इकोनॉमिक रीजन से तस्वीर बदलने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को जमकर सराहा है। भाजपा जहां इसे ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। आम आदमी और नौकरीपेशा वर्ग को प्रत्यक्ष राहत कम नजर आई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों से उत्तर प्रदेश के हिस्से में 2.69 लाख करोड़ रुपये आएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में राज्य को कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये मिलने हैं। पूंजीगत निवेश (विकास कार्यों) के लिए राज्यों को ब्याजमुक्त ऋण योजना से 22 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में करीब 18 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान है। इसी प्रकार केंद्र सहायतित योजनाओं के मद में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग ने केंद्रीय योजनाओं से भी 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिलने का अनुमान लगाया है। इन मदों से वर्ष 2026-27 में राज्य को करीब 4.18 करोड़ रुपये मिलेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इन मदों से राज्य को 3.92 करोड़ रुपये मिलने हैं। अब केंद्र से मिलने वाले इस धनराशि के आधार पर राज्य सरकार अपना बजट तैयार करेगी।

बजट में किसान, महिला, युवा, कारीगर व छोटे उद्यमियों को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से पूर्वांचल, काशी क्षेत्र, बुंदेलखंड और टियर-2 व टियर-3 शहरों के लिए ये योजनाएं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार, निवेश व आर्थिक गतिविधियों को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी-सिलीगुड़ी और दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया, जिससे यूपी को कुल 1500 किमी हाई-स्पीड रेल मिली। इसके अतिरिक्त, सभी 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का विशेष बजट, नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क और तीर्थ स्थलों के विकास की घोषणा की गई। ये परियोजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देंगी। केंद्र सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। इससे दूर-दराज़ इलाकों से उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की व्यवस्था मिलेगी।

बजट में यूपी को मिले प्रमुख तोहफे

- वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम
- बुंदेलखंड में होगा आईआईटी का निर्माण, पश्चिमी यूपी में खुलेगा एम्स
- सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना से टियर-2 व टियर-3 शहरों का कायाकल्प
- 12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स से सड़क, रेल व लॉजिस्टिक्स को मजबूती
- खेल, एमएसएमई, खादी, हथकरघा व टेक्सटाइल सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन की घोषणा
- एआई आधारित 'भारत-विस्तार' से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक
- 'शी-मार्ट' से ग्रामीण महिलाओं को नया बाजार और उद्यमिता का अवसर
- सोलर, बैटरी व ई-मोबिलिटी को बढ़ावा, पीएम सूर्य घर योजना को गति
- हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल और जिला अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार
- 10,000 करोड़ का कंटेनर निर्माण विशेष बजट
- नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क, तीर्थ स्थलों का समग्र विकास

इस धनराशि से तय होगा यूपी के आम बजट का आकार

- केंद्रीय करों से हिस्सा (2026-27) : 2.69 लाख करोड़ (2025-26 में 2.55 लाख करोड़)
- पूंजीगत निवेश के लिए ब्याजमुक्त ऋण : 22,000 करोड़ (चालू वर्ष में 18,000 करोड़)
- केंद्र सहायतित योजनाएं : 1 लाख करोड़ से अधिक
- वित्त आयोग की सिफारिशों से : 10,000-12,000 करोड़
- केंद्रीय योजनाओं से अनुमानित राशि : 15,000 करोड़ से अधिक
- कुल अनुमानित केंद्रीय सहायता (2026-27) : लगभग 4.18 लाख करोड़
- (2025-26 में लगभग 3.92 लाख करोड़)

आपात-स्थिति में सस्ता और प्रभावी इलाज

गरीबों व निम्न आयवर्ग के लोगों को आपात-स्थिति में सस्ता व प्रभावी इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में सभी जिला अस्पतालों की इमरजेंसी सुविधाएं बढ़ाने तथा ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे समय पर उपचार मिलने से जान बचाने की संभावनाएं बढ़ेंगी और जिला अस्पतालों की क्षमता में भी वृद्धि होगी। इन दोनों पहलों से यूपी में न केवल स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सहायक कर्मियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

कनेक्टिविटी से लेकर रोजगार तक बदलेगा यूपी का परिदृश्य

अमृत विचार, लखनऊ : केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के लिए विकास का व्यापक खाका लेकर आया है। हाई-स्पीड रेल, जल परिवहन, सिटी इकोनॉमिक रीजन और 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्रदेश की कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही किसान, महिला, युवा, एमएसएमई, पर्यटन और टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष ध्यान देकर रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित करने की दिशा तय की गई है।

हाई-स्पीड रेल से बदलेगी कनेक्टिविटी की तस्वीर

केंद्रीय बजट में घोषित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जिनमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजधानी दिल्ली से काशी, पूर्वांचल और आगे पूर्वी भारत तक की रेलयात्रा तेज, सुरक्षित, सुविधाजनक तरीके से संपन्न होगी। आधुनिक तकनीक से लैस रेल नेटवर्क प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। हाई-स्पीड रेल से लंबी दूरी की यात्रा का समय काफी कम होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश व पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। काशी, पूर्वांचल व सीमावर्ती जिलों में उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

वाराणसी को मिलेगा जल परिवहन में नया आयाम

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जल परिवहन को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय बजट में वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह पहल गंगा नदी पर विकसित हो रहे जलमार्ग आधारित परिवहन तंत्र को तकनीकी व व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाएगी। शिप रिपेयर इकोसिस्टम के स्थापित होने से मालवाहक जहाजों और जलपोतों के रखरखाव व मरम्मत की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी, जिससे समय और लागत दोनों में कमी आएगी। इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलने के साथ जल परिवहन, एक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में प्रभावी होगा।

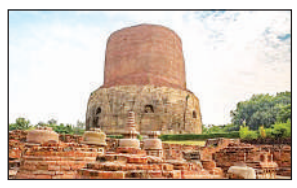

पर्यटन व धार्मिक स्थलों को नई पहचान, संरक्षण को विशेष महत्व

केंद्रीय बजट में पर्यटन व सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। इसी क्रम में भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ तथा हस्तिनापुर को देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे न केवल यूपी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर नई मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। इससे धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल, होम-स्टे, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और अन्य सहयोगी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

सिटी इकोनॉमिक रीजन से शहरों का होगा समग्र विकास

केंद्रीय बजट 2026-27 में टियर-2 और टियर-3 शहरों को विकास की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सिटी इकोनॉमिक रीजन (सीईआर) योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत बड़े महानगरों पर निर्भरता कम करते हुए पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले अन्य शहरों में बुनियादी ढांचे व आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी जैसे प्रमुख शहरों को इस योजना का सीधा लाभ मिल सकता है। आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए लगभग 5000 करोड़ तक का चरणबद्ध निवेश प्रस्तावित है।

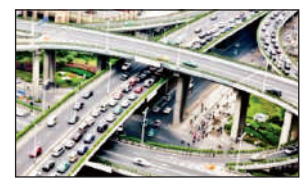

इन्फ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश की घोषणा मिलेगा सीधा लाभ

केंद्रीय बजट में देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) की घोषणा की गई है, जिसका सीधा व अप्रत्यक्ष लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। केंद्र सरकार के इस कैपेक्स का उद्देश्य आर्थिक विकास को रफ्तार देना, रोजगार सृजन करना और भारत को वैश्विक निवेश का आकर्षक केंद्र बनाना है। उत्तर प्रदेश में इस निवेश से सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक हब के विस्तार को नई गति मिलेगी। राज्य का पहले से मजबूत होता एक्सप्रेसवे नेटवर्क (पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा और लिंक एक्सप्रेसवे) औद्योगिक कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा।

सोलर, बैटरी और ई-मोबिलिटी क्षेत्र में रियायत बनेगी गेम चेंजर

अमृत विचार, लखनऊ : केंद्रीय बजट 2026 में सोलर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और ई-मोबिलिटी से जुड़े कस्टम ड्यूटी व आयात शुल्क में दी गई रियायतों को उत्तर प्रदेश के लिए गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। इन फैसलों को प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना और राज्य में तेजी से उभरते ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम से जोड़कर आंका जा रहा है। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि बजट के ये प्रावधान रूफटॉप सोलर विस्तार, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा संतुलन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी- इन चारों क्षेत्रों को एक साझा दिशा में आगे बढ़ाएंगे। बजट 2026 में लिथियम-आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल- कोबाल्ट पाउडर, बैटरी स्क्रैप और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। सोलर सेक्टर के लिए बजट में एक अहम प्रावधान करते हुए सोलर ग्लास निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल सोडियम एंटीमोनेट को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। उद्योग जगत का मानना है कि इन रियायतों से डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (डीसीआर) आधारित सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। इनपुट्स सस्ते होने से घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। इसका असर उत्तर प्रदेश में सोलर वैल्यू चेन के विस्तार के रूप में सामने आ सकता है। बजट प्रावधानों के बाद नोएडा, लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल के औद्योगिक क्षेत्रों में नई सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के साथ-साथ ईवी कंपोनेंट्स, बैटरी पैक असेंबली और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश बढ़ने की संभावना है।

एमएसएमई, खादी और वस्त्र क्षेत्र को मिलेगी गति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों के लिए नए अवसर
- एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम, ग्रोथ फंड और ग्रामीण उद्योगों पर फोकस

अमृत विचार: केंद्रीय बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग को सशक्त बनाने के लिए कई अहम और दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। वस्त्र क्षेत्र के लिए एक व्यापक, एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल और समर्थ 2.0 जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन और निर्यात को गति देना है। मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

इन प्रावधानों से प्रदेश के एमएसएमई, खादी, हथकरघा, रेशम और वस्त्रोद्योग से जुड़े लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। रोजगार बढ़ेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी। छोटे उद्यमों की कार्यशील पूंजी की समस्या कम करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम के दायरे का विस्तार किया जाएगा।

कॉरपोरेट मित्र और विरासत औद्योगिक क्लस्टर का प्रस्ताव

'कॉरपोरेट मित्र' व्यवस्था के जरिए एमएसएमई को व्यावसायिक मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और बाजार से जोड़ने की पहल की गई है। इसके साथ ही देशभर में 200 विरासत इंडस्ट्रियल क्लस्टरों के कायाकल्प का प्रस्ताव है, जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टर भी शामिल होंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूते के ऊपरी हिस्सों के शुल्क-मुक्त आयात का विस्तार और चमड़ा व वस्त्र परिधान निर्यात की समय-सीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं। इनसे वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिलेगी।

किसानों, महिलाओं व युवाओं पर विशेष ध्यान

केंद्रीय बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारत-विस्तार योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इससे राज्य के अन्नदाता किसानों को मौसम, मिट्टी, फसल चक्र और बाजार की मांग के अनुरूप सटीक कृषि सलाह उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे फसल जोखिम कम होगा और राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि संभव होगी। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा, जो परंपरागत खेती पर निर्भर हैं। बजट में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शी-मार्ट्स की शुरुआत की गई है। कृषि-तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और उद्यमिता से जुड़े नए अवसर सृजित होंगे।

स्वास्थ्य व शिक्षा में सशक्त कदम

केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण व दूर-दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इससे उच्च शिक्षा, मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास सुविधा मिल सकेगी। बजट में प्रस्तावित स्टेम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथ्स) संस्थानों से प्रदेश में पहले से जारी स्किल डेवलपमेंट अभियान को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है बजट

अमृत विचार, लखनऊ : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जिन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प इसमें स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी दृष्टि, दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त घोषणापत्र है। राज्यपाल ने कहा कि करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, राजकोषीय अनुशासन, नियंत्रित घाटा और संतुलित कर्ज-जीडीपी अनुपात इस बात का प्रमाण है कि भारत की विकास यात्रा सुदृढ़ नींव पर आगे बढ़ रही है।

बजट पर विभिन्न दलों के नेताओं का कहना...

ऐतिहासिक बजट : केशव प्रसाद मौर्य

अमृत विचार : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। अपार अवसरों का राजमार्ग है। 2047 के विकसित भारत की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है।

बजट में यूपी का रखा ध्यान : पाठक

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश का पूरा ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित हर क्षेत्र को बजट में समाहित किया गया है

विकसित भारत को लेकर जनोन्मुखी बजट: पंकज

अमृत विचार : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला जनोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। हाई-स्पीड रेल, आयुष, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, कृषि और एमएसएमई पर जोर से रोजगार, निवेश और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

समझ से बाहर है बजट : अखिलेश

अमृत विचार : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बजट-2026 में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है और यह पूरी तरह समझ से बाहर है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पीतल को लोहे पर चढ़ाकर गहने बनाने पड़ेंगे, यह बजट उसी सोच को दिखाता है। आरोप लगाया कि बजट कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है।

विश्लेषण बजट तात्कालिक वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए रचा गया वक्तव्य : प्रो. अजय द्विवेदी

बजट संख्या नहीं संकेत : देश की आर्थिक चेतना का निर्णायक क्षण

प्रो. अजय द्विवेदी
पूर्व डीन, प्रबंधन संकाय
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

अमृत विचार: भारत का आम बजट तब तक अधूरा रहता है, जब तक उसे केवल आय-व्यय के गणित की तरह पढ़ा जाता है। उसका वास्तविक अर्थ तब खुलता है, जब उसे समाज की मनःस्थिति, राष्ट्र की दिशा और सत्ता की मानसिकता के साथ जोड़कर देखा जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट एक ऐसे दस्तावेज़ के रूप में सामने आता है, जो शोर नहीं करता, संकेत देता है। यह बजट उत्सव का नहीं, निर्णय का बजट है। तात्कालिक वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरे उतरने के लिए रचा गया वक्तव्य।

हर बजट अपने साथ अपेक्षाओं की एक लंबी कतार लेकर आता है। मध्यम वर्ग कर राहत की प्रतीक्षा करता है। किसान स्थिर आय और सुरक्षा की उम्मीद करता है। युवा रोजगार के ठोस संकेत खोजते हैं। उद्योग नीति स्थिरता और निवेश अनुकूल वातावरण चाहता है। सामाजिक क्षेत्र अधिक संसाधनों की आकांक्षा रखता है। ऐसे में प्रश्न यह नहीं कि क्या यह बजट सबको खुश करता है, बल्कि यह है कि यह बजट किस दिशा में देश को ले जाना चाहता है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट भावनात्मक संतोष का साधन नहीं बनता। प्रत्यक्ष करों में बड़े और आकर्षक बदलावों का अभाव पहली दृष्टि में निराशा पैदा कर सकता है। पर इसके भीतर छिपा संदेश अधिक गहरा है। सरकार यह संकेत देती है कि अस्थिर अर्थव्यवस्था में दी गई त्वरित राहत अंततः उसी वर्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। महंगाई नियंत्रण, निवेश निरंतरता और वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देना यह दर्शाता है कि मध्यम वर्ग को उपभोक्ता नहीं, बल्कि आर्थिक भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। यह दृष्टि लोकप्रिय नहीं, पर जिम्मेदार है। कृषि और ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट करुणा से अधिक रणनीति की भाषा बोलता है। किसान को सहायता का पात्र नहीं, बल्कि आर्थिक संरचना का आधार मानने की सोच इस बजट को लोकलुभावन परंपरा से अलग करती है। ग्रामीण रोजगार, कृषि अवसंरचना और मूल्य संवर्धन पर निरंतर जोर यह स्पष्ट करता है कि सरकार जानती है कि गांव कमजोर हुआ तो शहर की प्रगति टिकाऊ नहीं रह सकती। यहां राहत बांटने से अधिक जड़ों को मजबूत करने का प्रयास दिखाई देता है। युवा वर्ग के लिए यह बजट सबसे अधिक बहस को जन्म देता है। सीधे रोजगार के बड़े वादे नहीं हैं, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं जिसे पोस्टर पर उकेरा जा सके। पर कौशल, तकनीक, स्टार्टअप और अवसंरचना के माध्यम से अवसर निर्माण की जो संरचना प्रस्तुत की गई है, वह यह संकेत देती है कि सरकार नौकरी देने की नहीं, रोजगार अर्थव्यवस्था बनाने की सोच पर आगे बढ़ रही है। यह दृष्टि धैर्य मांगती है, पर दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता की ठोस जमीन तैयार करती है।

उद्योग और व्यापार जगत के लिए यह बजट राहत की सांस जैसा है। करों में अप्रत्याशित झटकों का अभाव, नीति की निरंतरता और अवसंरचना निवेश का स्पष्ट संकेत यह दर्शाता है कि सरकार उद्योग को संदेह की दृष्टि से नहीं, साझेदार के रूप में देखती है। यह बजट उद्योग से यह नहीं कहता कि सरकार सब कुछ करेगी, बल्कि यह भरोसा देता है कि रास्ता स्थिर और स्पष्ट रहेगा, चलना उद्योग को स्वयं होगा। सामाजिक क्षेत्र में यह बजट भावनात्मक घोषणाओं से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को नारों के रूप में नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो इस बजट को गंभीर बनाता है। यह स्वीकार किया गया है कि मानव संसाधन पर किया गया निवेश तत्काल राजनीतिक लाभ नहीं देता, पर दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण का यही आधार होता है। इस पूरे बजट की रीढ़ उसका वित्तीय अनुशासन है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का संकल्प यह स्पष्ट करता है कि सरकार विकास की कीमत पर लापरवाही नहीं करना चाहती। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में यह संयम भारत को एक जिम्मेदार और परिपक्व अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। अवसंरचना पर निरंतर निवेश के साथ यह अनुशासन यह दर्शाता है कि सरकार विकास को गति देना चाहती है, पर संतुलन खोकर नहीं।

मायावती ने बजट पर उठाए सवाल

अमृत विचार : केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बजट में कई योजनाओं, परियोजनाओं और आश्वासनों का जिक्र है, लेकिन इनके वास्तविक असर का आकलन जमीन पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, इन पर सही नीयत से अमल होना जरूरी है। सलाह देते हुए कहा कि बजट गरीब और बहुजन हितैषी होना चाहिए, न कि केवल पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों का पक्ष लेने वाला।

बजट जवाब देने से भागने वाला : संजय

अमृत विचार : केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बजट सवालों से भागने वाला बजट है और सरकार को अब देश की जनता को जवाब देना ही होगा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ ली थी, तब उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि बजट में बेरोज़गारी पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।

आत्मनिर्भरता के संकल्प को ऊर्जा देगा बजट: अनिल

अमृत विचार : बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने कहा कि यह विकसित भारत का बजट है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह बजट विशेष कर अन्नदाताओं, नौजवानों, महिलाओं और शोषित वंचित उत्थान के लिए समर्पित है और किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण बुनियाद को मजबूत करने का काम करेगा।

ब्रीफ न्यूज

आरबीआई को बैंकों से 3.16 लाख करोड़ का लाभांश मिलेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थानों से लाभांश और अधिशेष के रूप में 3 .16 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 3 .75 प्रतिशत अधिक है। संसद में प्रस्तुत संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को लगभग 3 .05 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, जो फरवरी, 2025 में पेश किए गए आम बजट में 2 .56 लाख करोड़ रुपये था। बजट दस्तावेजों में यह भी बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और अन्य निवेश से मिलने वाला लाभांश 75,000 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो चालू वित्त वर्ष के बजट में 71,000 करोड़ रुपये था।

बजट समावेशी, वृद्धि और रोजगार बढ़ाने वाला: महेंद्र देव

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन एस महेंद्र देव ने रविवार को कहा कि बजट 2026-27 समावेशी है और वृद्धि तथा रोजगार को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट कारोबारी सुगमता के साथ ही रहन-सहन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। देव ने लिंक्डइन पर पोस्ट किया, बजट 2026-27 विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अगला कदम है। यह वृद्धि, समावेश और रोजगार की दिशा में बढ़ने वाला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों, वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट, और कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की।

आवास ऋण के ब्याज पर छूट में अब ब्याज भी शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के मामले में आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाली दो लाख रुपये तक की आयकर कटौती में अब संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से पहले दिया गया ब्याज भी शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22(2) में संशोधन करेगी। इससे एक अप्रैल 2026 से लागू नए कर कानून के तहत गृह ऋण लेने वाले करदाताओं को राहत जारी रहेगी। बजट दस्तावेज के अनुसार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22 गृह संपत्ति से होने वाली आय के मामले में मिलने वाली कटौतियों से संबंधित है।

युवा शक्ति साधने को खेलकूद का विकास

खेलो इंडिया मिशन की हुई शुरूआत

युवा और खेल मंत्रालय के लिए बजट में 1,133 करोड़ की वृद्धि, एथलीट को प्रोत्साहन

नई दिल्ली, एंजेंसी

वर्ष 2025-26 में 3,346 करोड़
वर्ष 2026-27 में 4,479.88 करोड़

- **भारत 2036 तक टॉप 10 व 2047 तक टॉप 5 देशों में शामिल होगा**
- **स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने को 500 करोड़ मिलेंगे**
- **स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने को 500 करोड़ मिलेंगे**

यूनियन बजट 2026-27 में भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार पैदा करने पर फोकस किया गया है। इससे युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका मकसद अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। डेवलपमेंट सेक्टर के तौर पर स्पोर्ट्स की बढ़ती अहमियत पर जोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, स्पोर्ट्स सेक्टर रोज़गार, स्किलिंग और नौकरी के कई मौके देता है।

खेलो इंडिया प्रोग्राम के जरिए स्पोर्ट्स टैलेंट को सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाने की शुरुआत करते हुए, मैं अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। यूनियन बजट में, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। खेलो इंडिया मिशन पूरे देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बड़ा तरीका अपनाएगा। इस मिशन का मकसद एथलीट के लिए सही रास्ते बनाना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करना और सभी लेवल पर परफॉर्मेंस के नतीजों को बेहतर बनाना है। बजट में युवाओं पर केंद्रित नेचर पर जोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रस्ताव युवाओं को जोड़ने की कोशिशों से निकले आइडिया और उम्मीदों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में, हमारे प्रधानमंत्री के साथ कई नए आइडिया शेयर किए गए, जिनसे कई प्रस्तावों को प्रेरणा मिली, जिससे यह एक अनोखा युवा शक्ति पर आधारित बजट बन गया। ग्लोबल स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भारत की क्षमता को पहचानते हुए, बजट में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक खास पहल का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहाः केंद्रीय बजट 2026-27, युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ताकि 2036 तक भारत को टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक टॉप 5 में जगह दिलाने का विज़न पूरा हो सके। मंत्रालय के लिए आवंटन 2025-26 में 3,346 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 4,479.88 करोड़ रुपये हो गया है। बढ़ा हुआ आवंटन केंद्र द्वारा चलाए जा रहे खेल और युवा विकास योजनाओं को लागू करने को मजबूत करेगा, जिसमें एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, युवा जुड़ाव की पहल, कोचिंग और सपोर्ट सिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस इंटीग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं। बढ़ा हुआ एलोकेशन भारत के युवाओं को मज़बूत बनाएगा।

पीएफ ट्रस्ट में नियोक्ता योगदान को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को भविष्य निधि या पीएफ ट्रस्ट के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके तहत नियोक्ता के योगदान पर समानता और प्रतिशत आधारित सीमाओं की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।

इस पहल का मकसद कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों में नियोक्ताओं के योगदान को सरल बनाकर कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है। इस समय कुछ ऐसे पीएफ ट्रस्ट हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति निधि संभालने वाली संस्था ईपीएफओ और आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त है। इन ट्रस्ट के नियोक्ता कुछ सीमाओं के तहत पीएफ खातों में अपने कर्मचारियों के योगदान की तुलना में कम या अधिक राशि का योगदान करते थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाना और इन पीएफ ट्रस्ट को नियंत्रित करने के लिए एकल नियामक स्थापित करना है।

भारत बनेगा बड़ा एआई हब

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बजट पेश होने के बाद रेल भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि भारत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हब के रूप में उभरने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने डिजिटल और तकनीकी विकास को बजट की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल बताया और कहा कि भारत का एआई-पारिस्थितिकी तंत्र आज पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित, निवेश-अनुकूल बन चुका है। श्री वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमीकॉन 2.0 और सेमीकॉन 1.0 की सफलता के आधार पर आगे बढ़ रहा है, जो सेमीकंडक्टर के उपकरणों, सामग्री का घेरलू विनिर्माण और डिज़ाइन और प्रतिभा पारिस्थितकी तंत्र को मज़बूत करने पर फोकस करता है। उन्होंने मंत्रालय के तहत आईटी सेवाओं में बड़े सुधारों की भी घोषणा की। जिसमें टैक्स और लागू करने को आसान बनाना, और एआई डेटा सेंटर्स के लिए मज़बूत समर्थन शामिल है-जिसे 8.25 लाख करोड़ रुपये (90 बिलियन डॉलर) तक के निवेश और 2047 तक टैक्स हॉलिडे का सपोर्ट मिला है।-जो भारत को वैश्विक एआई हब के में स्थापित करेगा।

- **आईटी मंत्रालय सेमीकॉन 2.0 और सेमीकॉन 1.0 की सफलता के आधार पर आगे बढ़ रहा**
- **एआई डेटा सेंटर्स बनाने के लिए 8.25 लाख करोड़ तक का निवेश होगा**

रियल एस्टेट और शहरी विकास को प्रोत्साहन

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय बजट पर राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने रविवार को कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बजट उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है।

श्री जैन ने बजट में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सभी क्षेत्रों व सेक्टरों तक अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है, जो "सबका साथ, सबका विकास" की भावना को मजबूती देता है। श्री जैन ने शहरी संतुलित विकास के लिए पूंजीगत व्यय को वित्त वर्ष 2026-27 में 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किए जाने के निर्णय को दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर विशेष फोकस से टियर-2 और टियर-3 शहरों में रियल एस्टेट गतिविधियों को नई गति मिलेगी और मेट्रो शहरों से परे संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर लोहिया वर्ल्डस्पेस के निदेशक पीयूष लोहिया ने कहा कि यह बजट आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्थिरता व दीर्घकालिक विकास का मजबूत आधार तैयार करता है।

- **राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा**

बैंकों के लिए उच्चस्तरीय समिति की हुई घोषणा

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ''विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की। यह समिति बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करेगी और इसे भारत की वृद्धि के अगले चरण के लिए तैयार करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत बही-खाते, लाभप्रदता के ऐतिहासिक उच्चस्तर, बेहतर संपत्ति गुणवत्ता और देश के 98 प्रतिशत से अधिक गांवों को शामिल करने वाली पहुंच से लैस है।

उन्होंने आगे कहा, हम इस मोड़

पर इस क्षेत्र की सुधार आधारित वृद्धि जारी रखने के लिए आवश्यक उपायों का मूल्यांकन करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण देते हुए कहा, मैं वित्तीय स्थिरता, समावेश और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित रखते हुए इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने और इसे भारत की वृद्धि के अगले चरण के साथ जोड़ने के लिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के नजरिये को ऋण वितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के स्पष्ट लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी में पैमाना हासिल करने और दक्षता में सुधार करने के लिए उन्होंने कहा कि पहले कदम के रूप में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, मैं भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन और उपयोगकर्ता के अनुकूल ढांचा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियमों की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रस्ताव से देश के बैंकिंग क्षेत्र को लाभ मिल सकेगा।

- **बजट में इस प्रस्ताव से होगा बही खाता सुधार, बैंकों की गांवों की ओर पहुंच और तेजी से बढ़ेगी**
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियमों की हो सकेगी व्यापक समीक्षा**

विदेश में रहने वालों को भारत में निवेश की अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी

पीआरओआई निवेश

- **भारतीय कंपनियों में अब इक्विटी निवेश कर सकेंगे**

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत व्यक्ति (पीआरओआई) अब पोर्टफोलियो निवेश योजना के जरिये सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी निवेश कर सकेंगे। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि पीआरओआई के लिए निवेश सीमा को भी अब पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट बॉन्ड सूचकांक पर कोष एवं डेरिवेटिव्स तक उपयुक्त पहुंच के लिए एक ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान देना जारी रखेगी।

उन्होंने कहा कि गुजरात के जामनगर में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र अद्यतन किया जाएगा।

- **20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड के कौशल उन्नयन के लिए पायलट योजना शुरू होगी**
- **निवेश सीमा पांच से बढ़ाकर 10 प्रतिशत रहेगी**

साथ ही देश की दूरबीन और खगोल विज्ञान अवसंरचना को भी उन्नत करने का प्रस्ताव है।

बजट के मुताबिक, पर्यटन एवं कौशल विकास क्षेत्र में सरकार 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड के कौशल उन्नयन के लिए पायलट योजना शुरू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में पर्वतारोहण में विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने की क्षमता मौजूद है। इसके अलावा केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन मार्ग भी विकसित करेगी।

सुधार बजट में प्रशासनिक सुधारों को 65 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव ई-गवर्नेंस को बढ़ावा

कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर 299 करोड़ रुपये होंगे खर्च

नई दिल्ली, एजेंसी

देश और विदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 299 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।

रविवार को पेश बजट के अनुसार, इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस प्रावधान में सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजना, प्रशासनिक सुधारों पर पायलट परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सुशासन को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए एक व्यापक प्रणाली शामिल है। आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल 299 करोड़ रुपये के परिव्यय में से, 120.8 करोड़ रुपये प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा लाल

बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के लिए स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए, 52.2 करोड़ रुपये प्रशिक्षण योजनाओं के लिए और 126 करोड़ रुपये केंद्र के महत्वाकांक्षी ''मिशन कर्मयोगी'' या सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को निर्धारित की गई है। मिशन कर्मयोगी को सबसे बड़ी नौकरशाही सुधार पहल कहा जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाना है। बजट दस्तावेज में कार्मिक मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधानों का विवरण देते हुए कहा गया कि 120.8 करोड़ रुपये के प्रावधान में दिल्ली स्थित आईएसटीएम, मसूरी स्थित एलबीएसएनएए और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग से संबंधित स्थापना व्यय शामिल हैं।

स्थापना संबंधी व्यय को 166.42 करोड़ रुपये आवंटित

बजट दस्तावेज में कहा गया कि 52 .2 करोड़ रुपये के आवंटन में सभी के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है। अगले वित्त वर्ष में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए 3 .5 करोड़ रुपये का कोष अलग रखा गया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) को लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामलों के निवारण का दायित्व सौंपा गया है। इसको आगामी वित्त वर्ष के लिए स्थापना संबंधी व्यय को 166 .42 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। बजट दस्तावेज में कहा गया कि इसमें सीएटी की विभिन्न पीठों के लिए भूमि की खरीद एवं भवनों के निर्माण का प्रावधान भी शामिल है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 52 .07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है।

म्यूचुअल फंड ब्याज खर्चों पर कटौती खत्म करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने रविवार को लाभांश और म्यूचुअल फंड आय से संबंधित ब्याज खर्चों पर मिलने वाली कटौती को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रस्ताव से वह मौजूदा प्रावधान खत्म हो जाएगा, जिसके तहत लाभांश या म्यूचुअल फंड आय के 20 प्रतिशत तक के ब्याज खर्चों पर कटौती की अनुमति मिलती थी।

आम बजट 2026-27 के अनुसार, यह प्रस्ताव है कि लाभांश आय या म्यूचुअल फंड की इकाइयों से होने वाली आय के संबंध में किए गए किसी भी ब्याज व्यय पर कोई कटौती नहीं दी जाएगी। साथ ही, एक तय सीमा तक ऐसी कटौती की अनुमति देने वाले मौजूदा प्रावधान को हटाने का भी प्रस्ताव है। यह बदलाव आयकर अधिनियम, 2025 का हिस्सा है, जो एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

दुर्घटना दावे से मिला हर्जाना अब आयकर से मुक्त होगा

नई दिल्ली, एजेंसी

- **कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगा इसका लाभ**
- **एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन**

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा।

बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है।

दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हादसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली किसी भी आय पर व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को छूट दी जाएगी।

यह संशोधन एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 तथा उसके बाद के कर वर्षों के संबंध में लागू होगा। इसमें यह भी कहा गया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई मुआवजे की राशि पर मिलने वाले ब्याज के संबंध में स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी।

विपक्ष के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं : भाजपा

नई दिल्ली, एजेंसी

विपक्षी दलों के बजट को खोखला बताने पर पलटवार, कहा- जनता को मोदी पर भरोसा

भाजपा ने रविवार को केंद्रीय बजट को भारत को विकसित बनाने की दिशा में अगला कदम बताते हुए इसकी सराहना की तथा विपक्षी दलों की ओर से इसे फीका और खोखला बताने पर पलटवार भी किया। भाजपा ने कहा कि सरकार को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भरोसा करती है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल हर बजट के बाद वही पुरानी बातें दोहराने लगते हैं। संसद भवन परिसर में पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने कहा, इसमें क्या गलत है, क्या वे हमारे लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की प्रगति, देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में काम करने वालों के उज्ज्वल भविष्य, नए रोजगार, कौशल विकास नहीं चाहते। उनकी समस्या क्या है। गोयल ने कहा, मैं इस बजट को भविष्य के लिए तैयार भारत का बजट कहूंगा। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में एक ऐसा बजट है जो भारत को 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की नींव रखता है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि बजट का मुख्य उद्देश्य विकास और प्रगति है। उन्होंने विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, सभी प्रावधान आम जनता के लिए बनाए गए हैं। अगर विपक्ष के लोग खुद को आम जनता नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं।

इस बजट में सबका साथ-सबका विकास: नवीन

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि संसद में पेश केंद्रीय बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक अगला कदम है, साथ ही गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं समेत समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करता है। नवीन ने कहा, यह बजट पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों के अटूट भरोसे को दिखाता है। प्रधानमंत्री का 'सबका साथ, सबका विकास' का सिद्धांत इस बजट के हर पहलू में साफ दिखता है। उन्होंने कहा कि 2026-27 का बजट भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की नीतियों और सुशासन की निरंतरता को साफ तौर पर दिखाता है।

थकी सरकार का बजट, कसौटी पर खरा नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी

राहुल गांधी ने कहा- देश के सामने मौजूद वास्तविक संकट से मूंद ली गईं आंखें

कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को थकी और रिटायर हो चुकी सरकार का बजट करार दिया। आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण तथा बजट, आर्थिक रणनीति और आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं, इसके साथ आसन्न वैश्विक झटकों समेत सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कटाक्ष किया कि सीतारमण ने या तो आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं पढ़ा या फिर उसे जानबूझकर दरकिनार कर दिया। चिदंबरम ने कहा, आज संसद में वित्त मंत्री के भाषण में जो कुछ सुनने को मिला, उससे अर्थशास्त्र का हर छात्र अवश्य ही स्तब्ध रह गया होगा। बजट केवल वार्षिक राजस्व और व्यय का बयान भर नहीं होता। मौजूदा परिस्थितियों में बजट भाषण को उन प्रमुख चुनौतियों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण पेश करना चाहिए, जिनका जिक्र कुछ दिन पहले जारी आर्थिक समीक्षा 2025-26 में किया गया था।

यह सुधार एक्सप्रेस कहीं भी नहीं रुकती: खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस सरकार के पास नीति, दृष्टि, समाधान और राजनीतिक इच्छा-शक्ति नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वंचित वर्गों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई और किसानों की भी उपेक्षा हुई है। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, मोदी सरकार के पास अब नए विचारों की कमी दिखती है। बजट-2026 भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता। 'मिशन मोड' अब 'चैलेंज रूट' बन गया है। 'सुधार एक्सप्रेस' शायद ही कभी किसी 'सुधार जंक्शन' पर रुकती है। उन्होंने दावा किया कि अब कोई नीति-दृष्टि नहीं है और कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति भी नहीं है।

रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को भाया रक्षा आवंटन और कर रियायत

नई दिल्ली। रक्षा क्षेत्र की देशी-विदेशी दिग्गज कंपनियों ने रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि का स्वागत करते हुए कहा कि यह भू-रणनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप है और इससे सेना की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। पूंजी बजट में 22 प्रतिशत की वृद्धि और सरकार द्वारा नागरिक एवं अन्य विमानों के उत्पादन के लिए घटकों एवं पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क को समाप्त किये जाने को उद्योग जगत महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रहा है। थेल्स के भारत परिचालन के उपाध्यक्ष अंकुर कनागलेकर ने कहा कि रक्षा आवंटन का उद्देश्य सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। 'रोल्स-रॉयस इंडिया' के कार्यकारी उपाध्यक्ष शशि मुकुंदन ने कहा कि रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण सेवाओं में सहायक कल-पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट विमानन क्षेत्र को मदद करेगी। भारत फोर्ज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान को दर्शाता है, जो नीतिगत निरंतरता, राजकोषीय अनुशासन और दीर्घकालिक राष्ट्रीय क्षमताओं के निर्माण पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर आधारित है।

आम लोगों का बजट नहीं

चूक गईं और स्टंप हो गईं वित्त मंत्री : थरूर

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बजट को निराशाजनक करार दिया और वित्त मंत्री पर किक्रेट शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कटाक्ष किया कि वह गेंद खेलने से चूक गईं और स्टंप हो गईं। कांग्रेस सासंद ने कहा कि सीतारमण के बजट में विशेष बातें कम थीं और इसमें समग्र दृष्टिकोण का अभाव था। इस बजट में खुश होने लायक कुछ भी नहीं है।

सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न अब भी रोजगार का है, और बजट में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि रोजगार कैसे पैदा होगा। थरूर से पूछा गया कि क्या वित्त मंत्री ने शॉट लगाया है या चूक गईं और स्टंप हो गईं, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह स्टंप हुई हैं या नहीं, लेकिन लगता है कि वह गेंद चूक गई हैं। एक-दो जगहों पर बल्ले का किनारा लगा हो सकता है, लेकिन मुझे अब तक यह पक्का नहीं लग रहा है कि बल्ले के बीच से कोई शॉट लगा हो। बड़े मुद्दों पर, हमें बजट में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी सुनने को नहीं मिला। राज्यों के लिए भी कुछ नहीं था।

बजट बंगाल विरोधी, झूठ का पुलिंदा : ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को भेदभाव करने वाला और झूठ का पुलिंदा बताते हुए पश्चिम बंगाल को उसके हक से वंचित करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने बजट को आम लोगों या सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल के खिलाफ राजनीतिक भेदभाव बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों के लिए कुछ नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। वे बंगाल में हारेंगे। राजनीतिक रूप से वे यहां कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए पश्चिम बंगाल को वंचित किया जा रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार धन नहीं दे रही है क्योंकि उसे राज्य में चुनावी हार का डर है। बनर्जी ने जीएसटी व्यवस्था की आलोचना करते हुए दावा किया कि सारा राजस्व केंद्र इकट्ठा कर रही है जबकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को उसके सही हिस्से से वंचित किया जा रहा है।

ये बजट पांच प्रतिशत लोगों के लिए: अखिलेश

लखनऊ। केंद्रीय बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बजट से क्या होगी। अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा कि आ गया भाजपाई बजट का परिणाम, शेयर मार्केट हुआ धड़ाम। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था - सवाल ये नहीं है कि शेयर बाज़ार रविवार को खुलेगा, सवाल ये है कि और कितना गिरेगा। हम तो भाजपा के हर बजट को 1/20 का बजट मानते हैं क्योंकि वो पांच प्रतिशत लोगों के लिए होता है। भाजपा का बजट, कमीशन और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने वाला होता है। भाजपा का बजट, भाजपाई भ्रष्टाचार का अदृश्य खाता-बही होता है। इस बजट में न जनता का ज़िक्र है, न फ़िक्र और महंगाई बढ़ने पर भी कर में छूट न देना, टैक्स-शोषण है। अमीरों के काम-कारोबार और घूमने-फिरने पर दस तरह की छूटें दी गईं हैं लेकिन बेकारी-बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली, खाली है। यह निराशाजनक, निंदनीय बजट है।

पूंजीवादी सोच से प्रभावित बजट: मायावती

लखनऊ। बसपा की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बजट में योजनाओं, परियोजनाओं और वादों के नाम भले ही बड़े हों, लेकिन असली कसौटी यह है कि उनका लाभ जमीन स्तर पर आम लोगों तक कितना पहुंचता है। कहा, सर्वसमाज के हित में केवल बातें करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें सही नीयत के साथ अमल में लाना भी जरूरी है। मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र का बजट पूंजीवादी सोच से प्रभावित प्रतीत होता है, जिसमें बड़े उद्योगपतियों और धनाढ्य वर्ग को प्राथमिकता मिलती दिखती है, जबकि गरीब, दलित और बहुजन समाज की अपेक्षाएं पीछे छूट जाती हैं। सरकार की नीयत का आकलन इससे होना चाहिए कि गरीबों के जीवन में कितना बदलाव आया है।

सबका साथ-सबका विकास

विकसित भारत के निर्माण की कल्पना : शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना बताते हुए इसे हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट करार दिया है। शाह ने एक्स पर लिखा कि बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का नारा हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि यह बजट एक ऐसे भारत के निर्माण की परिकल्पना है, जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो। शाह ने कहा कि बजट में विनिर्माण ,आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य ,पर्यटन तक, ग्रामीण क्षेत्रों, एआई , खेल क्षेत्र हर गाँव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं तथा किसानों के सपनों को शक्ति देकर उन्हें पूरा करने की बात कही गयी है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण और 25 वर्षों के रोडमैप को दर्शाने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का हर भारतवासी की तरफ से अभिनंदन किया गया है।

रक्षा और आत्मनिर्भरता का आधार : राजनाथ

लखनऊ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को देश की सुरक्षा को सशक्त करने वाला और विकसित भारत की दिशा में निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रस्तुत किया गया बजट जन-भावनाओं और जन-आकांक्षाओं पर खरा उतरता है। रविवार को सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में रक्षा मंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए इसमें संतुलित और दूरदर्शी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आया यह बजट देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के संकल्प को दृढ़ करता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करने वाला है और आने वाले वर्षों में भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

भारत को सशक्त करने वाला बजट : नड्डा

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बजट को लोक-कल्याणकारी, सर्वसमावेशी और विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति संकल्पित देश के आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में स्थापित करने में एक सशक्त कदम है और देश की युवा शक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। नड्डा ने कहा कि सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता इससे स्पष्ट होती है कि 12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 176 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नड्डा ने बजट में मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान दिए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि रांची और तेजपुर स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थानों के उन्नयन तथा उत्तर भारत में निमहंस की स्थापना का निर्णय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेगा। जामनगर में डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना भारत के लिए गर्व का विषय है, जो पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक पहचान दिलाएगा।

बजट में विकसित भारत की यात्रा : गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसंरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। गडकरी ने एक्स पर कहा कि संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना बनाने के लिए एक निर्णायक कदम रेखांकित किया गया है।

शेयर बाजार को रास नहीं आया बजट

मुंबई, एजेंसी

आम बजट में एसटीटी बढ़ाने की घोषणा का असर सेंसेक्स 1,547 अंक और निफ्टी 495 अंक टूटा

वायदा सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने की केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद रविवार को घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,547 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी 495 अंक टूटकर बंद हुआ। विश्लेषकों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में सौदों पर एसटीटी को बढ़ाने का ऐलान बाजार को पसंद नहीं आया और यह बहुत तेजी से नीचे चला गया।

बीएसई का सेंसेक्स शुरुआती बढ़त गंवाते हुए दोपहर में 2,370.36 अंक की भारी गिरावट के साथ 80,000 अंक से भी नीचे फिसलकर 79,899.42 अंक पर पहुंच गया था। बाद में थोड़े सुधार के साथ 1,546.84 अंक की गिरावट के साथ 80,722.94 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी 495.20 अंक गिरकर 24,825.45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 748.9 अंक तक लुढ़ककर 24,571.75 अंक तक चला गया। अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश किए जाने से रविवार होने के बावजूद शेयर बाजारों में विशेष कारोबारी सत्र आयोजित किया गया।

भारी बिकवाली से निवेशकों के 9.40 लाख करोड़ डूबे

नई दिल्ली। बजट के दिन रविवार को घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट आने से निवेशकों के करीब 9 .40 लाख करोड़ रुपये डूब गए। इस बड़ी गिरावट से बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 9,40,581 .75 करोड़ रुपये घटकर 4,50,61,658 .60 करोड़ रुपये (4 .90 लाख करोड़ डॉलर) रह गया। बीएसई पर सूचीबद्ध कुल 2,375 शेयरों में गिरावट का रुख रहा जबकि 1,759 शेयरों में तेजी रही और 175 अन्य अपरिवर्तित रहे।

बजट में एमएसएमई को अर्थव्यवस्था के दूसरे इंजन की मान्यता : लघु उद्योग भारती

जालंधर। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुसूदन दादू, उपाध्यक्ष अरविंद धूमल व महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने एक संयुक्त बयान में कहा कि बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे इंजन के रूप में मान्यता दी गई है। बजट में लघु उद्योग भारती के सुझावों को समुचित समर्थन मिला है।

दादू के अनुसार, एमएसएमई केंद्रित सुधारों और वैश्विक क्षमता निर्माण के प्रति दृष्टिकोण सराहनीय है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से संबंधित प्रतिबंधों एवं आदेशों से भारतीय एमएसएमई की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी तथा अनावश्यक अनुपालन बोझ कम होगा। धूमल ने कहा कि यह वैश्विक स्तर पर क्षमता निर्माण का बजट है, जहां सशक्त एमएसएमई देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।

बजट सकारात्मक और विकास केंद्रित रत्न-आभूषणों के लिए बाधाएं दूर

मुंबई। रत्न और आभूषण क्षेत्र ने रविवार को केंद्रीय बजट को सकारात्मक और विकास-केंद्रित बताते हुए इसका स्वागत किया, और कहा कि यह मुख्य बाधाओं को दूर करने के साथ उद्योग को नई गति प्रदान करता है। जीजेईपीसी के चेयरमैन किरित भंसाली ने कहा, हम एक सकारात्मक, विकास-केंद्रित बजट के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं जो मुख्य बाधाओं को दूर करता है और भारत के रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को नई गति प्रदान करता है।

उन्होंने कहा, यह बजट नकदी की स्थिति में सुधार करता है, विनिर्माण का समर्थन करता है और मूल्य श्रृंखला में निर्यात को मजबूत करता है। जीजेईपीसी ने केंद्रीय बजट के सीमा शुल्क सुधारों का स्वागत किया। भंसाली ने कहा, विश्वास-आधारित प्रक्रियाएं, डिजिटल मूल्यांकन, और सरलीकृत मंजूरी प्रक्रिया से देरी और लागत में कमी आएगी।

विकासोन्मुख, संतुलित और विकसित भारत के लक्ष्य वाला आम बजट

नई दिल्ली, एजेंसी

उद्योग जगत ने जताई उम्मीद, प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए मिलेगा भरोसेमंद रास्ता

उद्योग जगत ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को विकासोन्मुख, संतुलित और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के अध्यक्ष राजीव जुनेजा ने कहा कि बजट आर्थिक वृद्धि को तेज और स्थाई बनाने, लोगों की आकांक्षाओं को सशक्त साझेदारी में बदलने और विकास के अवसरों तक समावेशी पहुंच बनाने के तीन कर्तव्यों को पूरा करती है।

पीएचडीसीसीआई के सीईओ एवं महासचिव डॉ. रंजीत मेहता ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा को सेमीकंडक्टर निर्माण से जोड़ते हुए लिथियम-आयन सेल्स और सोलर ग्लास निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट तथा परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए छूट को 2035 तक बढ़ाना अहम कदम है। रक्षा क्षेत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएचडीसीसीआई रक्षा एवं एचएलएस समिति के चेयर अशोक अतलुरी ने कहा कि 7.85 लाख करोड़ रुपये का रक्षा आवंटन और 75 प्रतिशत घरेलू खरीद अनिवार्यता रणनीतिक स्वायत्तता का संकेत है।

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा, यह बजट संतुलित और भरोसेमंद है, जिसमें विकास, सबको साथ लेकर चलने और युवा शक्ति पर साफ फोकस है। फिक्की वित्त मंत्री की तारीफ करता है कि उन्होंने लगातार सुधारों, सार्वजनिक पूंजी खर्च में बढ़ोतरी, व्यापार करने में आसानी और विनिर्माण, एमएसएमई, कृषि और सेवा पर खास जोर देकर निरंतरता और स्थिरता बनाए रखी है।

भारतीय उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजीव मेमानी ने कहा कि यह वित्तीय अनुशासन, नीतिगत सुधारों और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लक्षित दखल के संतुलित मिश्रण के जरिए भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए भरोसेमंद रास्ता पेश करता है। यह बजट ऐसे समय में विश्वास को मजबूत करता है, जब वैश्विक आर्थिक हालात अनिश्चित बने हुए हैं और निवेश के फैसले तेजी से नीति की स्पष्टता और भविष्यवाणी पर आधारित होते जा रहे हैं।

राइस मिल में ढांग गिरी दो मजदूर दबे, मौत

मृतक के भाई की तहरीर पर मिल मालिक पर मुकदमा

संवाददाता, बहेड़ी /देवरनियां।

अमृत विचार : राइस मिल में धान की बोरियों की ढांग गिरने से बोरियों के नीचे दबे दो मज़दूरों की मौत हो गई। एक मृतक मज़दूर के भाई ने इस मामले में राइस मिल मलिक पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने राइस मिल मालिक के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है।

बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के गांव के सर्वेश कुमार और विनोद कुमार रिछा में स्थित मुस्कान राइस मिल में मज़दूरी करते थे। मिल में धान की बोरियों की ढांग से बोरियां निकालते वक्त ढांग गिर गई। इसमें सर्वेश और विनोद बोरियों के नीचे दब गए, और गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत भोजीपुरा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुँचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई।

सर्वेश के भाई पप्पू ने देवरनियां पुलिस को दिए शिकायती पत्र में

मृतक सर्वेश

मृतक विनोद

कहा कि उसका भाई सर्वेश और पड़ोस का रहने वाला विनोद राइस मिल में चावल निकालने वाली हौदिया में मज़दूरी करते थे। मिल मालिक उनसे धान की बोरियों का चट्टा लगवाने का काम कराते थे। दोनों ने मालिक से बोरियां ऊपर से उतारने की बात कही, जिस पर मिल मालिक उत्तेजित हो गया, और नीचे से बोरी निकालने को कहा।

उसका कहना है कि दोनों ने जब ऐसा करने से मना किया तो मालिक ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मज़दूरी न देने की बात कही। पप्पू का आरोप है कि मजबूर होकर दोनों ने नीचे से बोरी खीची,तभी टावर की धान की बोरी नीचे गिर

- नौ माह पहले हुई थी विनोद की शादी
- मृतक सर्वेश की दो बेटियां व एक बेटा है

गई, और दोनों उसके नीचे दब गए।उसका कहना है कि गांव के ही अनिल व रेशम सिंह वहां पहुँच गए। चीख -पुकार सुनकर और लोग वहां जमा हो गए। इन लोगों ने दोनों को बोरियों के नीचे से निकाला और अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। मृतक विनोद पुत्र माखन लाल की शादी 9 माह पहले हुई थी, जबकि सर्वेश की शादी 2019,में हुई थी, उसके दो बेटी व एक बेटा है। तहरीर में पप्पू ने कहा कि कहासुनी में मिल मालिक ने एलानिया कहा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस ने इस मामले में पप्पू की तहरीर पर मिल मालिक के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है।

नेपाली युवती का थाने में हंगामा

संवाददाता, नवाबगंज

अमृत विचार: कस्बे में एक युवती ने सात वर्षों तक चले लिव-इन रिश्ते के बाद खुद को ठगा हुआ बताते हुए युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि शादी का भरोसा देकर साथ रखने वाला युवक अब उसके कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो गया, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान है।

जानकारी के अनुसार नेपाल की रहने वाली युवती की पहचान कई वर्ष पहले नवाबगंज निवासी युवक से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। बातचीत आगे बढ़ी तो युवक उसे नवाबगंज ले आया। कुछ समय बाद दोनों मुंबई चले गए, जहां वे लिव-इन रिलेशन में रहने लगे। इस दौरान युवती होटल कैटरिंग के काम से जुड़ी रही।

कोतवाल नवाबगंज अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि युवक और युवती मुंबई में साथ रह रहे थे। युवक के मोबाइल और रुपये लेकर चले जाने की शिकायत मिली है। युवक से युवती की बातचीत भी हुई है। फिलहाल युवक मुंबई में है और युवती भी वहीं वापस जा रही है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

- सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता विवाद में बदला
- नवाबगंज निवासी युवक दोस्ती के बाद कई तक साल लिव इन में रहा
- मुंबई में दोनों रह रहे थे, व्यापार में घाटा भी हुआ, युवक मुबई में ही है

विहिप ने जताई नाराजगी

घटना की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष बाबूराम गंगवार कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

युवती का वीडियो वायरल करने की धमकी का भी आरोप

युवती ने पुलिस को दी तहरीर में यह भी आरोप लगाया कि युवक के पास उसकी निजी वीडियो हैं, जिन्हें वह सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है।इस कारण वह लगातार मानसिक तनाव में है।मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के घर जाकर जानकारी जुटाई, लेकिन युवक कस्बे में मौजूद नहीं मिला। पुलिस के अनुसार वह फिलहाल मुंबई में है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

रिश्ते के दौरान दोनों कुवैत भी गए

बताया गया कि रिश्ते के दौरान दोनों कुवैत भी गए, जहां एक निजी कंपनी में करीब दो साल तक नौकरी की। बाद में गोवा में दोनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू किया, लेकिन नुकसान होने पर उसे बंद करना पड़ा। इसके बाद युवती मुंबई लौटकर दोबारा होटल में काम करने लगी। इसी दौरान दोनों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए।युवती का आरोप है कि कुछ दिन पहले युवक उसके दो मोबाइल फोन और घर में रखे करीब 50 हजार रुपये लेकर अचानक गायब हो गया। परेशान होकर वह रविवार को नवाबगंज कोतवाली पहुंची और आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। युवती का आरोप है तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने मदद नहीं की और उसे मुंबई जाकर वहां के संबधित थाने में शिकायत करने को कहा। पुलिस को अंदाजा नहीं था कि युवती हंगामा भी कर सकती है। युवती ने रौद्र रुप दिखाया तो पुलिस उसे बुलाकर कोतवाली के अंदर ले गई। इसके बाद वहां मौजूद लोग भी मौके से हटने लगे।

तीन युवतियों को ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

अलीगंज, अमृत विचार : तीन सहेलियों को बहलाफुसला कर अपने साथ ले जाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

अलीगंज थाना प्रभारी जगत सिंह ने बताया की 28 दिसंबर को बिशारतगंज के गांव हरें की गौटिया का महेश पाल पुत्र गोकुल राम अलीगंज क्षेत्र के एक गांव की लड़की संगीता और उसकी दो नाबालिग सहेलियों को बहला फुसलाकर कर अपने साथ पंजाब ले गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पति ने जताया हत्या का शक, रिपोर्ट

संवाददाता, नवाबगंज

अमृत विचार : पति-पत्नी के आपसी विवाद ने अब गंभीर कानूनी रूप ले लिया है। नगर के एक परिषद कर्मी ने ससुराल पक्ष पर जान से मारने की धमकी देने और पत्नी पर हत्या कराने की आशंका जताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

नगर परिषद में चालक के पद पर कार्यरत आनंद उर्फ वण्टी का विवाह करीब पांच–छह वर्ष पूर्व क्योंलड़िया क्षेत्र के ग्राम नकटी नरायनपुर निवासी युवती से हुआ था। दंपती की दो बेटियां हैं। कुछ दिन पूर्व पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद पत्नी दोनों बेटियों को लेकर मायके चली गई थी।

आनंद का आरोप है कि इसके

- पत्नी पर हत्या कराने की जताई आंशका
- ससुराल पक्ष के भी शामिल होने पर पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा
- ससुर बोले-दामाद ने दहेज के वाद से बचने को लगाए गलत आरोप

बाद से उसका ससुर उसे व उसके परिवार को लगातार धमकियां दे रहा है। उसने आशंका जताई है कि उसकी पत्नी भी अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करा सकती है। युवक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ससुराल पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया है। ससुराल पक्ष के लोगों का कहना हैकि कस्बे में महिलाएं इतनी एडवांस नहीं है कि अपने ही पति को मारने की बात सोचे। महिला के लिए पति आज भी पहले स्थान पर होता है। वह उत्पीड़न सहकर भी ससुराल नहीं छोड़ती है और जुल्म सहती रहती है। दामाद द्वारा मारने के आरोप पर बताया कि पिछले दिनों इस तरह की केस सामने आने पर वह पैतरा चल रहे हैं। एक सरकारी विभाग में तैनात ससुर का कहना है कि दामाद के खिलाफ न्यायालय में दहेज उत्पीड़न का मामला विचाराधीन है और उसी से बचने के लिए यह आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी बेटी को पति के पास भेजने को तैयार हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

नो-केन से जूझ रही त्रिवटी नाथ चीनी मिल

बहेड़ी,अमृत विचार : पहले तकनीकी समस्याओं से जूझ रही बहादुरगंज में बनी त्रिवटी नाथ चीनी मिल अब नो -केन की समस्या से जूझ रही है। तीन दिन में मिल सिर्फ 16हज़ार कुंटल गन्ना ही पेराई कर पाई है। हालांकि मिल ने चीनी का पहला लॉट निकाल लिया है।

त्रिवटी नाथ चीनी मिल की पेराई क्षमता प्रतिदिन 25 हज़ार कुंटल की है। मिल को शासन से बहेड़ी और पीलीभीत गन्ना समितियों के 15 क्रय केंद्र आवंटित कर10लाख कुंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन आए दिन तकनीकी खराबियों से मिल चल ही नहीं पाई।ऐसे में सेंटर काटकर दूसरी मिलों को आवंटित कर दिए।

प्रबंधन ने मिल पेराई के लिए तैयार होने की बात कही तो शासन ने छह सेंटर आवंटित कर दिए। प्रबंधन ने अब मिल सुचारु रूप से चलने का दावा किया है, लेकिन अब गन्ना नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में मिल बार -बार बंद करना पड़ रही है। जीएम(केन) सुरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि मिल ने 3दिन में 16हज़ार कुंटल गन्ना पेराई किया है, और चीनी बनने लगी है।

6क्रय केंद्रों से मिल की पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ना नहीं मिल सकता। क्रय केंद्र शासन आवंटित करता है, और फिलहाल हमको 6सेंटर ही मिले हैं। वह कहते हैं कि किसानों को सप्लाई किए गन्ने का भुगतान किया जा रहा है।

फोन पर धर्म को लेकर गालियां, रिपोर्ट

बहेड़ी, अमृत विचार : एक शख्स ने फोन पर अज्ञात नम्बर से धर्म को लेकर गलियां देने की शिकायत पुलिस से की है।पुलिस ने इस मामले में मुकदमा कायम कर लिया है।

गांव जाम सावंत जनूबी के अंसार अहमद ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसके फोन पर अज्ञात नम्बर से फोन आया, और उसने उसके धर्म के साथ जाति को लेकर भी गलियां दीं, और नाम पूछने पर उसने और भद्दी -भद्दी गलियां दीं।पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

न्यूज डायरी

मेधावी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित

शेरगढ़, अमृत विचार : युवा मंडल विद्यालय शेरगढ़ में शान्तिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। जिसमें सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को शांतिकुंज से आए समन्वयक राजीव जौहरी द्वारा सम्मानित किया गया। परीक्षा में सम्मिलित सभी श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तकों के साथ-साथ प्रमाण पत्र वितरित किए गए। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में निहारिका प्रथम, संकेत राठौर द्वितीय, अमन राठौर तृतीय तथा पवित्र श्रीवास्तव, नैतिक बाबू, प्रतिज्ञा, प्रियंका देवल ने सांत्वना स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉ कल्याण राय श्रीवास्तव, उपप्रधानाचार्य शिव ओम सिंह, सौरभ गंगवार, मोनिका देवल, कौशिकी सिंह, कशिश चंद्रा, शिखा गंगवार, अलका गंगवार, सोनी देवल, प्रीति तोमर, ज्योति, ओम प्रकाश, प्रताप सिंह आदि समेत शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

दलित-पिछड़ा वर्ग ने निकाला समर्थन मार्च

नवाबगंज , अमृत विचार :रयूजीसी कानून के समर्थन में रविवार को नवाबगंज में दलित एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों ने संगठित होकर शक्ति प्रदर्शन किया। अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ समर्थन मार्च कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए तहसील परिसर तक पहुंचा, जहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। समर्थन मार्च अंबेडकर पार्क से कचहरी मार्ग और पटेल चौराहे तक पहुंचा। यहां प्रदर्शनकारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सामाजिक एकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम उदित पवार को ज्ञापन सौंपते हुए यूजीसी कानून को प्रभावी और शीघ्र लागू कराने की मांग की। प्रदर्शन में अनुज पटेल, सुरेश पटेल, नीरू सागर, श्रीपाल गंगवार, अर्जुन सिंह गंगवार, मोहन स्वरूप गंगवार, वीरेंद्र कुमार पटेल, सोनू गंगवार, सुरेंद्र गंगवार, शंकरलाल, अमित कुमार, विकल गौतम, झांजनलाल, भगवानदास, धर्मेंद्र कुमार वर्मा, हरिओम, रामकरन लाल, रश्मि, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र गंगवार, अंकित सागर, विनय कुमार, मोनू आदि रहे।

गोलू देवता मंदिर पर तीसरा वार्षिक महोत्सव संपन्न

भोजीपुरा, अमृत विचार : सुरला गांव स्थित गोलू देवता मंदिर पर तीसरा वार्षिक महोत्सव श्रद्धा और हर्षोल्लास उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन से शुरू हुई थी। दोपहर को विशाल भंडारा हुआ। इसमें आसपास के गांवों के साथ-साथ पर्वतीय समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में मंदिर के संस्थापक डॉ. महेंद्र कुमार सक्सेना एवं संस्थापिका कमलाचंद्र ने व्यवस्थाओं को संभाला। भंडारे में पहुंचे भोजीपुरा ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल ने कहा पिछले समय मंदिर तक पहुँचने के लिए रास्ता कच्चा था जिसके लिए लोगों की माँग पर उन्होंने इस बार उन्होंने मुख्य मार्ग से मंदिर तक खडन्जा डलवाया है। कार्यक्रम में भाजपा नेता अनिल कुमार एडवोकेट, कुमार पारस, प्रेमपाल, राम प्रजापति, सर्वेश कुमार प्रजापति, पंडित विनोद कुमार, हरपाल प्रजापति, संजय ठाकुर, बसंत कनौजिया, सनी ठाकुर, बीडीसी राजेश कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

सूचना

मैने अपनी पुत्री नाहिद बी पत्नी मोहम्मद तसलीम निवासी धौराटांडा को गलत चाल चलन व अभद्र व्यवहार करने के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति व अपने परिवार से बेदखल कर सम्बन्ध बिच्छेद कर लिए हैं। भविष्य में उसके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के कृत्यों, लेनदेन व मुकदमेबाजी आदि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगी। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य उपरोक्त के किसी भी कृत्य के लिए किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। **कुबरा पत्नी मोहम्मद अब्बास निवासी मोहल्ला लोधीपुरा, शेखपुर, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली।**

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पासपोर्ट सं. T5211436 में मेरा नाम भूलवश MOHAMMAD SOHAIL दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम MOHAMMAD SOHAIL KHAN है। आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी मेरा नाम MOHAMMAD SOHAIL KHAN ही दर्ज है। **मो. सोहेल खान पुत्र श्री मोईन मियां निवासी मो. मुनीर खां तह. व जिला पीलीभीत।**

वैधानिक सूचना :- समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन जैसे टावर सम्बन्धी, नौकरी सम्बन्धी, ऋण सम्बन्धी या अन्य किसी भी प्रकार के विज्ञापन में पाठकों को सावधान किया जाता है। विज्ञापनदाता द्वारा किये गये दावे या उल्लेख, समर्थन की पुष्टि समाचार पत्र नहीं करता है।

बरेली न्यूरो एण्ड स्पाईन सुपर स्पेशलिटी सेंटर

डा. मोहित गुप्ता

M.Ch., Neurosurgery (AIIMS)
Senior Consultant Neurosurgeon
मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ
Reg. No. UPMCI 65389
समय - प्रातः 10 से 12:30 बजे तक
एवं सायं 6 से 8:30 बजे तक
अब डॉ. मोहित गुप्ता रविवार को भी मिलेंगे प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक

सुविधायें
ब्रेन हैमरेज | स्लिप डिस्क
ब्रेन ट्यूमर | मिर्गी का दौरा
गर्दन दर्द (सर्वाइकल)
रीढ़ की चोट, टी.बी
सिर दर्द, माइग्रेन
कमर दर्द, कंधों में दर्द
पीठ दर्द, रीढ़ की गांठ
सिर की चोट (हेड इंजरी)
हाथ पैरों में झनझनाहट
फालिज (लकवा)
नसों का दर्द
सियाटिका (कमर में पैरों का दर्द)
दिमागी में पानी व खून जमना
दिमाग, रीढ़ एवं नस सम्बन्धित सभी बीमारियों का इलाज एवं ऑपरेशन

Bareilly Neuro and Spine Super Speciality Centre
Google Maps Location
सी-427, डिवाइन अस्पताल के सामने, के.के. अस्पताल रोड, राजेन्द्र नगर, बरेली
7417389433, 7017678157
9897287601, 8191879754

MEDICAL Lifelines OF BAREILLY
अमृत विचार
विज्ञापन हेतु सम्पर्क करें :- 8445507002

फोकस नेत्रालय
राजेन्द्र नगर, बरेली 731-098-7005

बरेली का सबसे बड़ा केवल आँखों के लिए समर्पित प्राइवेट अस्पताल ... नवीनतम AI तकनीक एवं NABH मान्यता के साथ

- 40,000 से अधिक सफल सर्जरी सम्पन्न
- बिना इंजेक्शन एनेस्थीसिया (केवल आई ड्राप्स द्वारा)
- आयुष्मान/सीजीएचएस/ईसीएचएस/सीएपीएफ सभी स्वास्थ्य बीमा मान्य
- कैशलेस ईलाज

ADITYA आदित्य आई एण्ड लेजर सेन्टर
उपलब्ध सुविधायें :-
बिना सुई बिना टांका आधुनिक लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा।
100000 से अधिक आंखों के आपरेशन का अनुभव
TPA कैशलेस सुविधा उपलब्ध
अल्ट्रासाउण्ड द्वारा पर्दे की जांच की सुविधा उपलब्ध
IOL Master 700 द्वारा लेंस का नम्बर
लेजर द्वारा आंख की झिल्ली हटाने की सुविधा उपलब्ध
बी स्कैन द्वारा पर्दे की जांच उपलब्ध
OCT द्वारा काला पानी एवं पर्दे की जांच व उपचार
8077344353
समय : प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फ्री आपरेशन की सुविधा

डॉ. आदित्य त्यागी
MBBS, DOMS, DNB, MNAMS
CARARACT REFRATIVE & GLAUCOMA SURGERON
ट्यूलिप ग्रांड के सामने, पीलीभीत बाईपास, बरेली

स्वास्थ्य जागरूकता अभियान
नि : शुल्क परामर्श
महीने के प्रत्येक रविवार को
समय : सुबह 10 से 5 बजे तक
कैम्प में समस्त ब्लड जाँचें, ई.सी.जी., एक्स-रे 50% के छूट पर किये जायेंगे।
रजिस्ट्रेशन शुल्क 20/-
डॉ. दीपक माहेश्वरी
MBBS., MD, Consultant Physucuan & Critical Care Specialist
ब्लड प्रेशर, हृदय रोग श्वांस रोग, गम्भीर रोग विशेषज्ञ
प्रेमलोक हॉस्पिटल
नरियावल अड्डा, शाहजहाँपुर रोड, बरेली।
9084307201, 9412244430
डॉ. नितिन अग्रवाल हृदय रोग विशेषज्ञ मो. 9457833777

डॉ. हारिस अंसारी
एम.एस., एम.सी.एच. (यूरोलॉजी)
Consultant Urologist & Andrologist
गुर्दा, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली की पथरी व कैंसर सर्जन
● प्रोस्टेट (गदूद का आपरेशन) (TURP) ● गुर्दे की पथरी का आपरेशन (PCNL) ● गुर्दे की नली (यूरेटस) की पथरी का ऑपरेशन (URSC) ● पेशाब के समस्त प्रकार के रोगों का इलाज
कैशलेस, इंश्योरेंस, TPA व ESI आयुष्मान से अनुबन्धित अस्पताल
डॉ. एम. खान हॉस्पिटल
मल्टी स्पेशलिटी व क्रिटिकल केयर सेन्टर स्टेडियम रोड, निकट सेंट फ्रांसिस स्कूल, बरेली
हेल्पलाईन 9897838286, 9837549348

अमृत विचार
क्लासीफाइड
विज्ञापन हेतु सम्पर्क करें
9756905552, 8445507002

न्यूज ब्रीफ

मंदिरों से घंटे चोरी करने के आरोपी दो भाई गिरफ्तार किए

बुलंदशहर, एजेंसी : जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस ने मंदिरों से घंटे चोरी करने के आरोपी दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) शंकर प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने मंदिरों से घंटे चोरी करने वाले दो अभियुक्तों अमित और उसके भाई सुमित को पकड़ा है। उन्होंने बताया कि इन दोनों के कब्जे से चोरी के 11 घंटे बरामद हुए हैं। आरोप है कि इन दोनों ने बुलंदशहर के कोतवाली देहात, खुर्जा नगर और चोला क्षेत्र तथा गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी थाना क्षेत्र के मंदिरों से घंटे चोरी किये हैं।

बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा

कुशीनगर, एजेंसी : कुशीनगर की एक अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता फूलबदन ने रविवार को बताया कि पांच मार्च 2024 को एक महिला ने रामकोला थाने में सूचना दी कि उसकी आठ वर्ष की बच्ची को गांव का ही मनोज कुमार उर्फ बिग्गू अगवा कर ले गया और दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) दिनेश कुमार द्वितीय की अदालत ने शनिवार को मनोज को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

50 लाख रुपये कीमत की अवैध शराब बरामद

झांसी, एजेंसी : जिले में पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से पश्चिम बंगाल भेजी जा रही शराब की पांच सौ से अधिक पेटियां बरामद की हैं। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि बरामद शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपये है और इस बाबत ट्रक मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक (नगर) लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि शनिवार मध्य रात्रि सीपरी बाजार पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्वालियर रोड स्थित एक होटल के पास एक ट्रक को रोका और गाड़ी की तलाशी के दौरान फोम की बोरियों के नीचे से अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुईं।

माघ पूर्णिमा स्नान

प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में माघ पूर्णिमा के अवसर पर लोग पवित्र स्नान करते हुए ● एजेंसी

वेंटुरा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर युवक से 14.17 लाख की ठगी

संवाददाता, लखीमपुर खीरी

● व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी ट्रेडिंग एप के जरिए 200 प्रतिशत मुनाफे का दिया लालच

अमृत विचार: वेंटुरा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी ट्रेडिंग एप के माध्यम से शेयर मार्केट व आईपीओ में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक युवक से 14 लाख 17 हजार 642 रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर थाना साइबर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शहर के मोहल्ला शिवपुरी निवासी पदुम कुमार ने बताया कि उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर वेंटुरा कंपनी के नाम से प्राइमरी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया गया। कंपनी का नाम ब्रांडेड होने के कारण उसे किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। ठगों ने 200 प्रतिशत मुनाफा होने पर 20 प्रतिशत सर्विस चार्ज लेने की बात कही और शेयर खरीदने-बेचने के लिए वेन शेक प्रो नामक ट्रेडिंग एप डाउनलोड कराया। शुरुआत में पीड़ित ने फोन-पे के जरिए अलग-अलग तिथियों में 50 हजार रुपये जमा किए। कुछ लाभ दिखाकर विश्वास जीतने के लिए पीड़ित को 2800 रुपये निकालने भी दिए गए। इसके बाद आईपीओ में निवेश के नाम पर पीड़ित से 3 लाख 6 हजार 300 रुपये आरटीजीएस के माध्यम से बंधन बैंक के खाते में जमा कराए गए। आईपीओ लिस्ट होने के बाद ग्रुप एडमिन वर्तिका आनंद ने 20 प्रतिशत सर्विस चार्ज जमा कराने पर कुल 14.17 लाख रुपये निकालने का झांसा दिया। इसके बाद पीड़ित से 2 लाख 17 हजार 993 रुपये आरटीजीएस कराए गए।

बागपत में वन विभाग ने सात शिकारियों को गिरफ्तार किया

बागपत, एजेंसी: जिले में वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी में लिप्त सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कई जानवरों के शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने आरोपियों के कब्जे से जंगली बिल्ली व सियार के तीन-तीन और एक जल मुर्गी समेत कई वन्यजीवों के शव बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान खन्ना नाथ, दुलीचंद, साजन नाथ, बाली नाथ, विकास, अर्जुन और रोहन कुमार के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त जाल, रस्सियां और धारदार हथियार भी जब्त किए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बागपत जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में अवैध रूप से वन्यजीवों का शिकार करते थे और बाद में इनके शवों की तस्करी हरियाणा के सोनीपत जिले में की जाती थी।

सांड़ के हमले से किसान की मौत

युवक को दौड़ाकर पटक दिया, जब तक मौत नहीं हो गई तब तक करता रहा हमला

मृतक करन के रोते बिलखते परिजन। ● अमृत विचार

कार्यालय संवाददाता, शाहजहांपुर

● सांड के हमले में आठ लोगों की जा चुकी है जान कई हो चुके घायल

करन सिंह।

अमृत विचार : खेत पर फसल की रखवाली करने गए युवक ने खेत से सांड को भगाने का प्रयास किया तो उसने हमला कर दिया। युवक को सांड ने पटक पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को आनन-फानन में जलालाबाद सीएचसी पर ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों का रो रोकर बुराहाल है।

जलालाबाद थाना क्षेत्र के गांव हथिनापुर निवासी करन सिंह (28) रविवार की सुबह छह बजे खेत पर फसल में घुसे छुट्टा पशुओं को भगाने के लिए गए। उसके खेत में पशुओं का झुंड फसल चर रहा थे। करन ने पशुओं को भगाने का प्रयास किया। इसी बीच एक सांड ने करन पर हमला कर दिया। करन ने भागकर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन सांड पीछे पड़ गया और टक्कर मारकर उसे जमीन पर गिरा लिया। इसके बाद करन को जमीन पर तब तक पटकता रहा।

गांव के लोग लाठी डंडा लेकर पहुंचे और सांड को किसी तरह भगाया। सांड के भाग जाने के बाद परिजन करन को जलालाबाद सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक करन सिंह की पत्नी विभा और दो बेटियों का रो-रोकर बुराहाल है। परिवार वालों ने जलालाबाद थाना पर सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह तोमर फोर्स के साथ गांव में गए और परिवार वालों से जानकारी की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर ग्रामीणों ने बताया कि गांव में छुट्टा पशुओं की संख्या बहुत है। पशु रात में फसल चर जाते है। सांड कई लोगों को घायल कर चुका है। कई बार प्रशासन पे अवारा पशुओं को पकड़वाए जाने की मांग कर चुके है।

जलालाबाद में सांड़ के हमले में हुई मौतें

- 16 जून 22 को खेड़ा चौराहे पर के निकट 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति पर सांड ने हमलाकर के मार डाला था, शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी।
- 23 जनवरी 23 को कुंडरा गांव में खेत पर सांड को भगाने रीना देवी गयी थी, सांड ने हमला करके उसे मार डाला था।
- 12 फरवरी 23 को गांव हथिनापुर से शादी से लौट रहे थाना कांट के गांव कुर्रिया कला के योगेश की बाइक सांड से टकरा गयी थी, उनकी सीएचसी पर मौत हो गयी थी।
- 24 दिसंबर 23 को रैपुरा निवासी साधुराम खेत पर फसल की रखवाल करने गए थे। उन्होंने सांड को भगाया तो सांड ने हमला करके उसे मारडाला।
- 06 मार्च 24 को खाईखेड़ा चौराहे के निकट बाइक सांड से टकरा गयी थी, जिससे बाइक सवार सुमोध निवासी चंदौरा बहादुरपुर थाना जलालाबाद की मौत हो गयी थी।

मिर्ची भेजने के मामले में कांग्रेस नेता को राहत

करनैलगंज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोंडा जिले के करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी त्रिलोकी नाथ तिवारी को बड़ी राहत दी है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि को मिर्च पाउडर और धमकी भरा पत्र भेजने के मामले में दर्ज मुकदमे की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने 2022 में दर्ज आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि एफआईआर में उठाया गया विवाद प्रथम दृष्टया दो उम्मीदवारों के बीच का आपसी मामला प्रतीत होता है। यह मुकदमा पूर्व सांसद के प्रतिनिधि सुशील सिंह की तहरीर पर नवाबगंज थाने में दर्ज किया गया था। आरोप है कि 18 फरवरी 2022 को स्पीड पोस्ट से भेजे गए एक लिफाफे में 500 ग्राम मिर्च पाउडर और एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिस पर भेजने वाले के रूप में त्रिलोकी नाथ तिवारी का नाम अंकित था। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि इस प्रकरण में संज्ञान केवल औपचारिक शिकायत के माध्यम से ही लिया जा सकता था।

फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाया, पांच गिरफ्तार

गाजियाबाद, एजेंसी

जिले में पुलिस ने फर्जी पतों का इस्तेमाल करके पासपोर्ट बनवाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उसके पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण क्षेत्र) सुरेंद्रनाथ तिवारी ने रविवार को बताया कि यह मामला तब सामने आया जब पिछले साल दिसंबर में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने पुलिस को एक पत्र लिखकर संदिग्ध आवेदनों के बारे में बताया, जिनमें एक ही पते पर कई पासपोर्ट जारी किए गए थे और एक ही मोबाइल नंबर का बार-बार इस्तेमाल किया गया था। तिवारी ने बताया कि जांच में पता चला कि आवेदक पासपोर्ट आवेदनों में बताए गए पतों पर नहीं रहते थे।

तिवारी ने बताया कि इस मामले में एक डाकिये और एक महिला सहित 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तिवारी ने बताया कि इस मामले में अब तक डाकिये अरुण कुमार समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अरुण कुमार इस गिरोह के साथ मिला हुआ था और दस्तावेजों को बताए गए पतों पर पहुंचाने के बजाय सीधे गैंग के सदस्यों को देने के लिए प्रति पासपोर्ट दो हजार रुपये लेता था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान अरुण कुमार ने पुलिस को बताया कि लगभग पांच महीने पहले प्रकाश सुब्बा और विवेक नाम के दो लोगों ने उससे संपर्क किया और कहा कि अगर वह उन्हें पासपोर्ट सौंपने के लिए सहमत होता है तो हर पासपोर्ट के लिए दो हजार रुपये मिलेंगे।

महिला को निवाला बनाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद

संवाददाता, बागेश्वर

अमृत विचार: बीते 7 जनवरी को बागेश्वर रेंज के अंतर्गत मनकोट में वृद्ध महिला को अपना शिकार बनाने वाला नरभक्षी गुलदार रविवार सुबह पिंजरे में कैद हो गया। इससे ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। वन अधिकारियों के अनुसार पकड़े गए गुलदार की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच है तथा उसका ऊपरी दांत नहीं है, जिस कारण वह नरभक्षी बना है। गुलदार को अल्मोड़ा चिड़ियाघर भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सात जनवरी की सायं छाती मनकोट निवासी 65 वर्षीय देवकी देवी पर उस समय हमला किया था जब वह जंगल में लगी आग को अपने घास के ढेर में आने से रोक रही थी। ग्रामीणों के काफी प्रयास के बाद मध्य रात्रि में महिला का शव बरामद हुआ था। इसके बाद ग्रामीणों व जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रभागीय वनाधिकारी का घेराव किया था तथा गुलदार को पकड़ने की मांग की थी। तब से वन विभाग द्वारा क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था परंतु गुलदार पिंजरे के बाहर चक्कर लगाकर चला गया था तथा रात में अन्य गांवों में दिखाई दे रहा था। जिस स्थान पर गुलदार कैमरे में कैद हुआ था शनिवार को विभाग ने उसी स्थान पर कैमरा लगाया और रविवार तड़के गुलदार पिंजरे में कैद हो गया।

मेरठ में रोडवेज बस की टक्कर से दो श्रद्धालुओं की मौत

मेरठ,एजेंसी: जिले में दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह तेज रफ्तार एक रोडवेज बस की टक्कर लगने से पैदल यात्रा कर रहे दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, खतौली के पुरानी शिवपुरी मोहल्ला निवासी हरिओम (42) अपनी पत्नी सरिता और पड़ोसी सरला (59) के साथ नंगली तीर्थ के लिए पदयात्रा पर निकले थे। पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे जब वे दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव के पास शिव ढाबा के सामने पहुंचे तभी देहरादून की ओर से आ रही तेज रफ्तार एक रोडवेज बस तीनों को टक्कर मारती हुई निकल गई।

लापता बच्चे का अधखाया शव मिला

संवाददाता, निघासन

कहीं तेंदुए ने तो नहीं बनाया निवाला

शव से 40 मीटर की दूरी पर मृतक बच्चे का शव पड़ा था। उसका खून गिरा हुआ था। ग्रामीण आशंका जता रहे हैं कि दूसरे के खेत से तेंदुआ को देखकर बालक भागा होगा और तार में फंसकर गिर गया। तेंदुए ने उसको मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद शव को घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। इसी बीच केले के खेत में पड़ी रस्सी उसके गर्दन में फंस गई थी। पूर्व प्रधान रमेश लोधी ने बताया कि गन्ना क्रय केंद्र पर तेंदुआ देखा गया है। उसकी एक तरफ की गर्दन कटी हुई थी। नीचे का हिस्सा खाया हुआ था।

अमृत विचार: क्षेत्र के गांव पचपेड़ी से करीब 400 मीटर दूर कब्रिस्तान के पास केले के खेत में एक बालक का अधखाया शव मिला। मृतक की पहचान शुक्रवार से लापता 10 वर्षीय गुलाम हुसैन उर्फ मुन्ना पुत्र मदारू के रूप में हुई।

मृतक गुलाम हुसैन।

गांव पचपेड़ी निवासी मदारू का पुत्र गुलाम हुसैन (10) शुक्रवार दोपहर करीब 12.30 बजे घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने कोतवाली निघासन में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई, तभी से पुलिस और परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। रविवार सुबह गांव की एक महिला खेतों की ओर गई थी। इस दौरान कब्रिस्तान के पास केले के खेत में उसे एक बच्चे का शव पड़ा दिखाई दिया। शव की हालत देखकर महिला घबरा गई और शोर मचाया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। बच्चे का शव अधखाया था। उसके गले में प्लास्टिक का फंदा पड़ा था। उसका टोपा और चप्पल भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की हत्या की गई है। उसके बाद जंगली जानवरों ने शव को खाया है। मृतक के पिता मदारू ने बताया कि शुक्रवार को गांव के ही एक व्यक्ति ने उनके बेटे को बीड़ी पीते हुए देख लिया था और इसकी शिकायत करने की बात कही थी। इसी डर से उनका पुत्र घर नहीं आया।

कार्यालय ग्राम पंचायत बसौमी विकास खण्ड आसफपुर बदायूँ

पत्रांक : मेमो/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/सामग्री आपूर्ति सूचना/2025-26 दिनांक : 02.01.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत समस्त फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बसौमी वि.खं. आसफपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित कार्य कराया जाना है :-

क्र.सं.	कार्य	अनु. लागत
1.	ग्राम पंचायत में जनसेवा केन्द्र (CSC) की स्थापना का कार्य	प्राक्कलन अनुसार

उपरोक्त कार्य हेतु प्राक्कलन में दी गई सामग्री/उपकरण क्रय किये जाने है। ग्राम पंचायत में सामग्री/उपकरण की आपूर्ति करने हेतु सील बन्द निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय में दिनांक 05.01.2026 तक आमंत्रित की जाती है। जो उक्त दिनांक को ग्राम पंचायत कार्यालय पर अपरान्ह 05:00 बजे खोली जायेंगी। प्राप्त निविदाओं में उल्लिखित दरों में वर्ष 2025-26 को कोई मूल प्रतिवर्तन नहीं होगा। प्रस्तुत निविदाओं में मानक के अनुसार ब्राण्डेड मार्का सामग्री की आपूर्ति का उल्लेख किया जायेगा। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

रूप किशोर-ग्राम प्रधान अंकित कुमार-सचिव

कार्यालय उपजिलाधिकारी सहसवान, बदायूं

पत्रांक : 17/उ.जि.अ./आपूर्ति-2026 दिनांक : 23.01.2026

प्रेस विज्ञप्ति

मा. अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) बदायूं के न्यायालय से निर्णीत वाद संख्या 4/2011-2012 सरकार बनाम वीरेन्द्र सिंह, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी2012127000177 अन्तर्गत धारा-essencial Act. उ.प्र. एवं निर्णीत वाद संख्या 1475/2017 सरकार बनाम टीकम सिंह, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी201712701475 अन्तर्गत धारा-6क, उ.प्र. आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2025 एवं मा. अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) महोदय बदायूं कि न्यायालय से निर्णीत वाद संख्या 18/2011-2012 सरकार बनाम वीरेन्द्र सिंह कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी2012127000569 अन्तर्गत धारा- essencial Act. उ.प्र. आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2025 जो कि एक ही प्रकरण से सम्बन्धित है, में राज्य सरकार के पक्ष में जब्त 10 कुन्तल अखाद्य गेहूँ, चावल जो श्री सुबोध कुमार उचित दर विक्रेता नगर क्षेत्र सहसवान की सुपुर्दगी में है, को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया है, जिसकी सार्वजनिक नीलामी/निविदा हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति समक्ष नीलामी प्रक्रिया पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। निविदादाता को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निम्न शर्ते पूर्ण की जानी है।

1. निविदादाता मण्डी समिति एवं व्यापार कर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. निविदादाता को पंजीयन के समय बोली में भाग लेने के लिये 500/- रूपये की अर्नेस्ट मनी उपजिलाधिकारी सहसवान (बदायूं) के पक्ष में जमा करनी होगी तथा जिसके पक्ष में बोली/नीलामी छूटेगी जिसकी अर्नेस्ट मनी जमा कर ली जायेगी,शेष अर्नेस्ट मनी बोली/नीलामी में भाग लेने वाले निविदादाताओं को वापस कर दी जायेगी।
3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा बनायी गयी कमेटी के समक्ष बोली/नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्त बोली/नीलामी में इच्छुक निविदादाता दिनांक 5.02.2026 समय अपरान 02:00 बजे कृषि उत्पादन मण्डी समिति सहसवान में उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते है।

उपजिलाधिकारी, सहसवान

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज, बरेली

पत्रांक : ध्वस्तीकरण/918-सी/2025-26 दिनांक : 31.01.2026

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय इण्टर कालेज, बरेली का वोकेशनल एजुकेशन भवन एवं काष्ट कला भवन जो जीण/शीर्ण एवं जर्जर हो चुके है, जिसका ध्वस्तीकरण/नीलामी शिक्षा निदेशक (मा.) उ.प्र. प्रयागराज की अनुमति पर किया जाना है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. बरेली द्वारा उक्त जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण सहित मलबे का न्यूनतम मूल्य रू. 5,39,130/- निर्धारित किया गया है। उक्त नीलामी/बोली दिनांक 10.02.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे से राजकीय इण्टर कालेज, बरेली के सभागार में की जायेगी। इच्छुक ठेकेदार/व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि वे खुली नीलामी/बोली में प्रतिभाग कर सकते है। नीलामी हेतु शर्ते निम्नवत् है :-

01. न्यूनतम बोली अनुमानित लो.नि.वि. की धनराशि से कम पर नहीं होगी।
02. नीलामी में भाग लेने वाले क्रेता के पास आधार और PAN होना अनिवार्य है।
03. नीलामी में भाग लेने वाले क्रेता को जमानत के रूप में न्यूनतम रू. 26757/- नीलामी शुरू होने से पहले जमा करना होगा तभी नीलामी में भाग ले सकेगे।
04. नीलामी की अधिकतम बोलने वाले को क्रेता के रूप में अधिकृत माना जायेगा।
05. नीलामी के बाद अन्तिम नीलामी की धनराशि को क्रेता के द्वारा नगद उसी दिन कार्यालय में जमा करना होगा एवं मलबे को विद्यालय परिसर से उठा लेना होगा।
06. नीलामी के समय जो टैक्स, आयकर, स्टाम्प या अन्य जो भी हो क्रेता के द्वारा वहन किया जायेगा।
07. नीलामी के बाद जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण शासकीय भवन/मुख्य सड़क को ध्यान में रखते हुये सुरक्षा की दृष्टि से किया जायेगा। जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण छः दिन के अन्दर पूर्ण करना होगा। यदि किसी प्रकार क्षति होती है तो उसकी भरपाई क्रेता को करनी होगी।

प्रधानाचार्य
पी.एम. श्री राजकीय इन्टर कालेज
बरेली।

तस्करी

बरेली से भगाए जाने के बाद ड्रग सिंडिकेट ने बहेड़ी को बनाया अड्डा, यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर बसा है बहेड़ी

पहाड़ की फिजा में घुला बहेड़ी का नशा, गांव-गांव में अरबों का धंधा

सर्वेश तिवारी, हल्द्वानी

अमृत विचार : एक वक्त था, जब बरेली से देश के कई राज्यों तक स्मैक की तस्करी होती थी, लेकिन योगी सरकार में तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई और इन्हें बरेली से भाग कर बहेड़ी में छिपना पड़ा।

कुछ समय तक शांत रहे और इसी दरम्यान ड्रग सिंडिकेट ने नया नेटवर्क खड़ा कर दिया। हालांकि नया सिंडिकेट पहले की तरह दूर तक नहीं फैल सका। ऐसे में नए सिंडिकेट ने कुमाऊं को निशाने पर लिया, लेकिन अपने बिल में दुबक कर। अब ये सिंडिकेट स्मैक के साथ नशीले इंजेक्शन, कैप्सूल और टेबलेट्स भी सप्लाई कर रहा है।

बरेली में मीरगंज, फतेहगंज

पूर्वी, फरीदपुर, फतेहगंज पश्चिमी और सिरौली, ये वो इलाके हैं जहां से कभी स्मैक की तस्करी हरियाणा, दिल्ली और मुम्बई तक की जाती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में वर्ष 2021 में इन पर सख्ती शुरू हुई। बरेली पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्ति खंगालनी शुरू की तो शिकंजे में बरेली के पढ़ेरा गांव का तत्कालीन प्रधान छोटे खां और उसका भतीजा राजू फंसा। इनके पास से 20 किलो स्मैक बरामद की गई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रधान छोटे खां नशे का के तार दिल्ली के दो लाख के इनामी तैमूर उर्फ भोला से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस तैमूर की तलाश में है। तैमूर के जरिए छोटे खां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मुंबई और दिल्ली में ड्रग सप्लायर के तौर पर बड़ा नाम था। ऐसे कई लोगों का नेटवर्क ध्वस्त हुआ, लेकिन इन लोगों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बहेड़ी में कारोबार जमा लिया है। पुलिस का कहना है कि बहेड़ी में बसा ड्रग सिंडिकेट अब गांव-गांव में स्मैक या फिर कैप्सूल, इंजेक्शन और टेबलेट्स बेचता है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल का कहना है कि इन्हें जड़ से मिटाने के लिए यूपी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की योजना बताई जा रही है।

ये हैं वो ड्रग माफिया, जो बिगाड़ रहे फिजा

कुमाऊ में ड्रग्स सप्लाई करने वालों में बरेली के पूर्व प्रधान शहीद, तैमूर उर्फ भोला, नन्हे उर्फ लंगड़ा, उस्मान, इस्लाम, इरफान, फैय्याज, छोटे प्रधान और रिफाकत का नाम हमेशा चर्चा में रहा है। बताया तो यह भी जाता है कि इनमें से कुछ की मौत हो चुकी है और कुछ यूपी से बाहर जाकर धंधा कर रहे हैं, लेकिन निशाने पर अब भी उत्तराखंड है। बड़ी बात यह है कि गैर राज्य में बैठे होने की वजह से उत्तराखंड पुलिस इन पर शिकंजा नहीं कस पा रही।

तीसरी बार चखा तो फिर नहीं छूटता नशा

स्मैक की लत एक बार में नहीं लगती और लग जाए तो फिर छूटती नहीं। स्मैक के काले कारोबार से जुड़े कारोबारियों की मानें तो अगर स्मैक की तीन डोज किसी को दे दी जाए तो फिर लत लग जाती है और फिर छूटती नहीं। ये तीन डोज तीन दिन तक लगातार दी जाती है। इसके बाद लोग स्मैक के आदी हो जाते हैं।

पैडलर बनाने के लिए देते हैं मुफ्त में दिये जाते है डोज

उत्तराखंड और इसके प्रवेश द्वार हल्द्वानी को स्मैक माफिया ने अपना डिपो बना लिया है। यहां स्मैक की सप्लाई को आसान बनाने के लिए ये माफिया युवाओं को स्मैक की लत लगा रहे हैं। पहले इन्हें स्मैक के मुफ्त डोज दिए जाते हैं और जब युवाओं को इसकी लत लग जाती है तो ये माफिया इन्हीं युवाओं को पैडलर बनाकर स्मैक तस्करी कराते हैं।

स्मैक से कहीं मुफीद हुआ नशीले इंजेक्शन का धंधा

स्मैक की तस्करी में गिरावट हुई है, लेकिन इसकी जगह नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल ने ले ली है। इनकी तस्करी स्मैक की अपेक्षा आसान है। पुलिस का कहना है कि स्मैक का लती आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इंजेक्शन लेने वाले आसानी से समझ नहीं आते। इंजेक्शन, स्मैक से सस्ता भी है। इसी वजह से इसका बाजार तेजी से पनप रहा है।

अमृत विचार

सोमवार, 2 फरवरी 2026

सपने को साकार होने से रोकने वाली एकमात्र चीज है- असफलता का भय।

-पाउलो कोएल्हो, ब्राजीलियन लेखक

संप्रभुता पर सख्त

देश के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा यह स्पष्ट कहना कि तथाकथित 'चिकन नेक' भारत की भूमि है और इस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक गंभीर रणनीतिक संकेत है। बयान बताता है कि केंद्र सरकार 22 किलोमीटर चौड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर अत्यंत सतर्क और इसकी रक्षा के लिS आक्रामक रुख रखती है। 'चिकन नेक' पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से जोड़ने वाली एकमात्र स्थलीय कड़ी है। इसके पश्चिम में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश और उत्तर में भूटान तथा चीन का प्रभाव क्षेत्र है। यदि इस संकरी पट्टी की सुरक्षा में कोई व्यवधान आता है, तो आठ पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक और सामरिक निरंतरता पर प्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। इस दृष्टि से इसे रणनीतिक संप्रभुता का मामला माना जाना चाहिए।

गृहमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि दिल्ली में कुछ तत्वों ने इस कॉरिडोर को 'काट देने' जैसे नारे लगाए थे। उनके बयान पर केंद्र की कड़ी प्रतिक्रिया यह संदेश देती है कि राष्ट्रीय एकता और भौगोलिक अखंडता पर कोई भी सार्वजनिक उकसावा अब सहन नहीं किया जाएगा और राजनीतिक विमर्श की आड़ में सामरिक संवेदनशीलता को हल्के में लेने वालों के साथ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा भी इसी व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा है। जहां भूमि संबंधी विवाद हैं, वहां केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, हलांकि केवल भूमि का मुद्दा ही बाधा नहीं है; तकनीकी सर्वेक्षण, सीमा निर्धारण के अंतर्राष्ट्रीय समझौते और स्थानीय विरोध भी प्रक्रिया को धीमा करते हैं। असल में सीमा प्रबंधन में भूमि अधिग्रहण, स्थानीय प्रशासन का सहयोग, पर्यावरणीय स्वीकृतियां तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रोटोकॉल जैसे जटिल पहलू शामिल होते हैं। कई स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में देरी एक व्यावहारिक बाधा रही है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। नदियां, आबादी का घनत्व, तस्करी की चुनौतियां और सीमा पर रहने वाले नागरिकों के आजीविका संबंधी प्रश्न भी बाड़बंदी को जटिल बनाते हैं। इसलिए दूसरी सीमाओं, विशेषकर कुछ हिस्सों में भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमा पर भी पूर्ण बाड़बंदी अभी बाकी है।

भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आती तो भी बाड़ तो लगेगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी एक दल के शासन पर निर्भर नहीं हो सकती। संवैधानिक ढांचे के भीतर केंद्र सरकार के पास सीमा सुरक्षा के पर्याप्त अधिकार हैं। किंतु प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार का सहयोग अनिवार्य होता है। बेहतर समाधान यह होगा कि इसे चुनावी मुद्दा बनाने के बजाय सर्वदलीय सहमति और केंद्र–राज्य समन्वय के जरिए आगे बढ़ाया जाए। गृहमंत्री का बयान केवल चुनावी आरोप-प्रत्यारोप नहीं माना जाना चाहिए। यह उस बदलते सुरक्षा वातावरण की स्वीकृति है, जिसमें हाइब्रिड युद्ध, सूचना युद्ध और आंतरिक अस्थिरता के प्रयास समान रूप से गंभीर खतरे हैं। 'चिकन नेक' केवल एक भूगोल नहीं, भारत की पूर्वोत्तर नीति, 'एक्ट ईस्ट' रणनीति और सामरिक आत्मविश्वास का प्रतीक है, इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक शोर से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के ठोस, संस्थागत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना समय की मांग है।

आम बजट 2026
विकास व अनुशासन का संतुलन

रजत मेहरोत्रा

वित्तीय एवं आर्थिक विशेषज्ञ

केंद्रीय बजट 2026-27 केवल सरकार का हिसाब-किताब नहीं, बल्कि यह बताता है कि आने वाले समय में देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। दुनिया में व्यापार तनाव, तकनीकी बदलाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच सरकार ने इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है। सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये किया है और यह लक्ष्य रखा है कि देश का कुल कर्ज (Debt/GDP) अनुपात को बजट अनुमान 2026-27 में GDP के 55.6 % के रूप में आंका गया है, जबकि संशोधित अनुमान 2025-26 में यह 56.1% था। Debt-to-GDP अनुपात में गिरावट का अर्थ है कि समय के साथ सरकार को ब्याज भुगतान पर कम खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सरकार खर्च भी करेगी और कर्ज को भी नियंत्रण में रखेगी।

बजट में राजकोषीय घाटा लगभग 4.3% ऑफ जीडीपी के स्तर पर रखने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि इससे देश की आर्थिक सेहत मजबूत होती है। जब सरकार का घाटा घटता है, तो उसे कम उधार लेना पड़ता है और ब्याज पर होने वाला खर्च भी कम होता है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। घाटा कम होने से महंगाई पर भी दबाव घटता है। इसके अलावा, जब फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में रहता है, तो विदेशी निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है, जिससे देश में निवेश आता है और रुपया भी मजबूत रहता है। कुल मिलाकर, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट घटाने का उद्देश्य केवल हिसाब संतुलित करना नहीं है, बल्कि भविष्य में विकास के लिए स्थायी और भरोसेमंद आर्थिक आधार तैयार करना है।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट को आय स्थिरता व जोखिम प्रबंधन का बजट कहा जा सकता है। सिंचाई परियोजनाओं, कृषि अवसंरचना और वेयर हाउसिंग नेटवर्क के विस्तार से फसल नुकसान कम होगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी। एग्री-लॉजिस्टिक्स और कोल्ड-चेन पर निवेश बढ़ाकर कृषि उत्पादों की बर्बादी घटाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म और फसल बीमा कवरेज के विस्तार से किसानों की आय में स्थिरता आएगी। कृषि-आधारित एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्धन और रोजगार दोनों बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है।

छात्रों और युवा शक्ति के लिए यह बजट 'शिक्षा से रोजगार' की कड़ी को मजबूत करता है। डिजिटल शिक्षा अवसंरचना, स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक लैब तथा उद्योग से जुड़े कौशल कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। शिक्षा और मेडिकल शिक्षा से जुड़े टीसीएस प्रावधानों को घटाकर 2% किए जाने से विदेश में अध्ययन करने वाले मध्यम वर्गीय छात्रों को सीधी राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल डिग्री उत्पादन नहीं, बल्कि रोजगार योग्य युवा तैयार करना है, ताकि जनसंख्या लाभांश वास्तविक आर्थिक शक्ति बन सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बजट में केंद्रीय स्थान मिला है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण, बीमा और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने से महिलाओं की भागीदारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2026 संजीवनी जैसा है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का एमएसएमई ग्रोथ फंड घोषित किया है, जिससे छोटे उद्योगों को सस्ता ऋण और विस्तार का अवसर मिलेगा। यह क्षेत्र देश में 11 करोड़ से अधिक रोजगार देता है, इसलिए इसमें निवेश सीधे रोजगार सृजन से जुड़ा है। एमएसएमई के डिजिटलीकरण और निर्यात क्षमता बढ़ाने से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेगा। कपड़ा और टेक्सटाइल उद्योग के लिए बजट ने पूरी वैल्यू चेन- फाइबर से फैशन तक को मजबूत करने का रोडमैप दिया है। नई नेशनल फाइबर स्कीम से उत्पादन लागत घटेगी और गुणवत्ता बढ़ेगी। भारत का टेक्सटाइल निर्यात पहले ही लगभग 40 अरब डॉलर के स्तर पर है और इस नीति से इसमें और वृद्धि की संभावना बनेगी। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। इससे पलायन कम होगा।

सरकार ने सात नए रेल कॉरिडोर और टियर-2 शहरों पर फोकस की घोषणा की है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी। उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। रेलवे में निवेश का गुणक प्रभाव स्टील, सीमेंट और निर्माण उद्योग पर पड़ता है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव है। आईटी, एआई और डेटा सेंटर नीति बजट 2026 की सबसे रणनीतिक घोषणाओं में से एक है। सरकार ने एआई के लिए 'पिक एंड शोवेल' अप्रोच अपनाई है यानी सीधे एप्लिकेशन पर नहीं, बल्कि अवसंरचना पर निवेश। विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने की घोषणा की गई है, बशर्ते वे भारतीय रीसेलर्स का उपयोग करें। इससे भारत ग्लोबल डेटा हब बनने की दिशा में बढ़ेगा और आईटी सेक्टर में उच्च-मूल्य रोजगार सृजित होंगे।

स्वास्थ्य और बायो-फार्मा सेक्टर को बजट में नई ऊर्जा मिली है। अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये की 'बायोफार्मा शक्ति' पहल से अनुसंधान, विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म, आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक सेवाओं और पोस्ट-केयर सुविधाओं के विस्तार से भारत वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभर सकता है। वर्तमान में मेडिकल टूरिज्म बाजार लगभग 9-10 अरब डॉलर का है, जिसे कई गुना बढ़ाने की क्षमता इस नीति में है। रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर रणनीति बजट 2026 का सबसे भू-रणनीतिक पक्ष है। सरकार ने रेयर अर्थ खनिजों के घरेलू उत्पादन, प्रोसेसिंग और वैल्यू-चेन विकास के लिए विशेष आवंटन किया है।

दुनिया में व्यापार तनाव, तकनीकी बदलाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच सरकार ने इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है।

आमने

खुद के ऊपर 14-14 मुकदमे हैं। उनमें जमानत करा लें। उनको सेटल करा लें सरकार से हाथ-जोड़ी करके। पौने तीन साल बाद में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मदन दिलावर जी से मिलने जेल में मैं जाऊंगा। गोविंद डोटासरा तो यहीं रहेगा। कहीं नहीं जाएगा।

-गोविंद सिंह डोटासरा
कांग्रेस नेता, राजस्थान

कांग्रेस सरकार के दौरान मिड-डे मील योजना में करीब दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। जांच की आंच उन 'मगरमच्छों' तक पहुंचेगी, जिन्होंने जनता की कमाई पर डाका डाला। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का जाल बिछ चुका है।

-मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री
राजस्थान सरकार

सामने

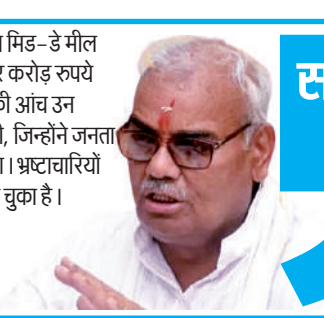

प्रसंगवश

एक संन्यासी ने हजारों आंखों में भर दी रोशनी

पंजाब के एक छोटे से गांव से निकले एक साधारण युवक ने संन्यास का मार्ग चुना और राजस्थान में पहुंच कर भक्ति के साथ जन सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने अपने तप, त्याग व करुणा से हजारों लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया। वह युवक संत स्वामी ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है। गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने उन्हें पदमश्री प्रदान देने की घोषणा की है। उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि उस विचारधारा पर मुहर है, जिसमें सेवा को साधना और मानवता को धर्म माना जाता है।

पंजाब के मोगा जिले की निहाल सिंह वाला तहसील में एक छोटा सा गांव है- रौंता। इस गांव से एक दिन एक युवक निकला, लेकिन उसने दुनिया से कुछ पाने का नहीं बल्कि दुनिया को कुछ लौटाने का रास्ता चुना। यह युवक आगे चलकर स्वामी ब्रह्मदेव के नाम से विख्यात हुआ। स्वामी ब्रह्मदेव ने संन्यास लिया, लेकिन समाज से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने पीड़ित मानवता की पीड़ा को देखा। उन्होंने 1963 में जब अमृतसर में श्री दुर्ग्याना मंदिर में अंध विद्यालय को देखा तो ऐसा ही कोई काम करने का संकल्प किया।

अमरपाल सिंह वर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

अपनी शिक्षा पूर्ण कर वह 1978 में राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक मंदिर में आए। यहीं से शुरू हुई श्री जगदंबा अंध विद्यालय की कहानी। शुरुआत बहुत साधारण थी। कोई बड़ी इमारत नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं। थे तो बस कुछ अच्छे लोग और स्वामी जी का अटूट भरोसा। जन सहयोग से रोपा गया एक छोटा सा पौधा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही पौधा एक दिन वटवृक्ष बन जाएगा।

वर्ष 1980 में उन्होंने जगदंबा अंध विद्यालय की आधारशिला रखी। जगदंबा अंध विद्यालय की शुरुआत केवल एक बच्चे और एक शिक्षक के साथ हुई थी, लेकिन आज वह वटवृक्ष बन चुका है। बीते साढ़े चार दशकों में उन्होंने सात हजार से ज्यादा दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षित किया है। मूक-बधिर बच्चों के लिए चार दशक से स्कूल भी चल रहा है। स्वामी ब्रह्मदेव ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें जीना भी सिखाया। नेत्रहीन और मूक-बधिर बच्चों के हाथ में हुनर दिया, साथ में आत्म विश्वास भी दिया। आज उस विद्यालय से पढ़े अनेक बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं।

स्वामी जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो जन्म से अंधे नहीं हैं, बस आर्थिक संकट के कारण इलाज नहीं करा पाए। यहीं से शुरू हुआ मोतियाबिंद ऑपरेशन का काम। वर्ष 1993 में स्थापित श्री जगदंबा आई हॉस्पीटल में अब तक साढ़े चार लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर उनकी आंखों की रोशनी बचाई जा चुकी है। साढ़े चार लाख का यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं है। यह साढ़े चार लाख घरों में लौटी उम्मीद है। स्वामी ब्रह्मदेव ने समाज को एक और गहरी बात सिखाई है, वह है मरणोपरांत नेत्रदान। उन्होंने लोगों को समझाया कि मौत के बाद भी किसी की जिंदगी रोशन की जा सकती है। धीरे-धीरे यह बात लोगों के दिलों में उतरती गई। सालों से संस्था के जरिए नेत्रदान करा कर जरूरतमंदों को नेत्र प्रत्यारोपित किए जाते हैं।

स्वामी ब्रह्मदेव का जीवन दिखावे से दूर रहा है। वह कथा-कीर्तन करते हैं, चढ़ावे में आया धन सेवा में लगा देते हैं। न कोई शोर, न कोई प्रचार। वही सादा वेश, वही सरल बोलचाल। वे खुद संस्था में मौजूद रहते हैं, काम देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। उनके लिए सेवा कोई परियोजना नहीं है, जीवन का स्वभाव है। पदमश्री मिलने के बाद भी उन्होंने श्रेय खुद नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान प्रभु की कृपा और जनता के निःस्वार्थ सहयोग का प्रतिफल है।

सुप्रीम फैसले से प्राइवेट स्कूलों में बराबरी की बात

रोहित माहेश्वरी

स्वतंत्र पत्रकार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब हर प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी अगर आपके पास साधन नहीं हैं, फिर भी आपका बच्चा महंगे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ाई कर सकता है। हाल ही में शिक्षा के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम और दूरगामी फैसला सामने आया है। अदालत ने साफ कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें। इसी सोच को मजबूत करते हुए शीर्ष अदालत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट और गैर-सरकारी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत मुफ्त सीटें सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना 'एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए।'

आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून, पहली अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके तहत छह से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत यह हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो इसमें कोई भी स्कूल बच्चे को दाखिला देने से मना नही कर सकता है। हर 60 बच्चों पर कम से कम दो प्रशिक्षित अध्यापकों का होना अनिवार्य है। हर तीन किलोमीटर के अंदर स्कूल होना जरूरी हैं। राईट टू एजुकेशन पर होने वाले खर्चों का 55 प्रतिशत केंद्र और 45 प्रतिशत राज्य सरकार उठाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, देश के स्कूल शिक्षा तंत्र में 24.8 करोड़ से अधिक छात्र नामांकित हैं और प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर 96.9 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है।

कोर्ट ने कहा कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला केवल कागज़ी अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को स्पष्ट नियम बनाने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से जुड़े इस मामले में याचिकाकर्ता दिनेश बीवाजी अष्टिकर ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को पड़ोस के निजी स्कूल में 25 फीसदी कोटे के तहत दाखिला नहीं मिला। आरटीआई से सामने आया कि सीटें खाली थीं, फिर भी स्कूल ने जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राहत नहीं दी कि ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वर्षों की देरी के कारण बच्चों को समय पर राहत मिलना संभव नहीं रहा। इसके बावजूद अदालत ने इसे 'नज़ीर तय करने वाला' मामला मानते हुए व्यापक दिशा-निर्देश देने का फैसला किया। कोर्ट ने माना कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, भाषा की बाधा, डिजिटल अशिक्षा और जानकारी की कमी के कारण गरीब परिवारों के लिए 25 फीसदी कोटे तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पड़ोस के स्कूलों में दाखिला केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है।

अदालत ने यह याद दिलाया कि निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना कोई अलग कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) और 39 (एफ) में निहित बाल विकास और बंधुत्व के सिद्धांतों को लागू करने का जरिया है। शीर्ष अदालत का कहना था कि आरटीई कानून सभी बच्चों को जाति, वर्ग, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना एक ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा देने की बात करता है।

अदालत ने कोठारी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम पर जोर दिया गया था, जहां पर समाज के हर वर्ग के बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा मिल सके। संविधान के भाईचारे का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब एक रिक्शा खींचने वाले का बच्चा, एक करोड़पति या सुप्रीम कोर्ट के जज के बच्चे के साथ एक ही स्कूल में पढ़े। शीर्ष अदालत के इस फैसले को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषदों से सलाह लेकर, धारा 12(1)(सी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम और कानून तैयार करें और जारी करें। कोर्ट ने आगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियम और कानून जारी करने की जानकारी इकट्ठा करें और 31 मार्च तक कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें।

सोशल फोरम

जिगर और नातिया मुशायरा

अजमेर में एक नातिया मुशायरा था। आयोजकों के सामने बड़ी मुश्किल थी कि जिगर मुरादाबादी को इस मुशायरे में कैसे बुलाया जाए। वे खुले रिंद (शराब पीने वाले) थे। नातिया मुशायरे में उनकी शिरकत आसान नहीं थी। आयोजकों में कुछ उनके हक़ में थे, कुछ खिलाफ़। आख़िर बहुत सोच-विचार के बाद आयोजकों ने फैसला किया कि जिगर को दावत दी जानी चाहिए। जब जिगर को बुलाया गया तो वे सिर से पांव तक कांप उठे।

हिस्ट्री अनफोल्ड

ब्लॉगर

'मैं गुनहगार, रिंद, सियाहकार, बदनसीब— और नातिया मुशायरा! नहीं साहब, नहीं।'

अब आयोजकों के सामने यह समस्या थी कि जिगर साहब को कैसे तैयार किया जाए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों से इनकार। आख़िरकार असगर गोंडवी ने हुक्म दिया और जिगर ख़ामोश हो गए। सिरहाने बोतल रखी थी, उसे कहीं छिपा दिया। दोस्तों से कह दिया कि कोई उनके सामने शराब का नाम तक न ले। यह मौक़ा मिला है तो मुझे इसे खोना नहीं चाहिए। शायद यह मेरी बख्शीश की शुरुआत हो। एक दिन गुज़रा, दो दिन गुज़र गए। नात के मज़मून सोचते थे और ग़ज़ल कहने लगते थे। सोचते रहे, लिखते रहे, काटते रहे, लिखे हुए को काट-काट कर थकते रहे। आख़िर एक दिन नात का मतला हो गया।

फिर एक शेर हुआ, फिर तो जैसे बारिश-ए-अनवार हो गई। नात मुकम्मल हुई तो उन्होंने सज्द-ए-शुक्र अदा किया। मुशायरे के लिए इस तरह रवाना हुए जैसे हज को जा रहे हों। उन्होंने कई दिनों से शराब नहीं पी थी, लेकिन हलक़ सूखा नहीं था। इधर तो यह हाल था, दूसरी तरफ़ मुशायरा-गाह के बाहर और शहर के चौराहों पर विरोध में पोस्टर लग गए थे कि एक शराबी से नात क्यों पढ़वाई जा रही है। आख़िर मुशायरे की रात आ गई। जिगर को बड़ी सुरक्षा के साथ मुशायरे में पहुंचा दिया गया। मंच से आवाज़ उभरी- 'रईस-उल-मुतग़ज़्ज़लीन हज़रत जिगर मुरादाबादी!'

इस एलान के साथ ही एक शोर उठ खड़ा हुआ। जिगर ने बड़े धैर्य के साथ मजमे की ओर देखा और प्रेम से भरे स्वर में बोले, 'आप लोग मुझे हूट कर रहे हैं, या रसूल पाक की नात को, जिसे पढ़ने की सआदत मुझे मिलने वाली है और जिसे सुनने की सआदत से आप अपने आप को महरूम करना चाहते हैं?'

शोर को जैसे सांप सूंघ गया। बस यही वह विराम था, जब जिगर के टूटे हुए दिल से यह आवाज़ निकली-

एक रिंद है और मद्हत-ए-सुल्तान-ए-मदीना
हां, कोई नज़र-ए-रहमत-ए-सुल्तान-ए-मदीना

-फेसबुक वॉल से

सामयिकी

बेटियों का कागजी कवच और सामाजिक बेड़ियां

बेटियां घर की रौनक होती हैं। समाज की शक्ति होती हैं और राष्ट्र की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर भी देश की बेटियां समान अवसर, सुरक्षा एवं लैंगिक समानता की उपेक्षा का बोझ ढो रही हैं। सरकार ने बेटियों के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और कानून बनाए हैं, जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला आरक्षण विधेयक, पास्को एक्ट, घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाएं, जिनके माध्यम से बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। इन योजनाओं से कुछ सकारात्मक बदलाव भी दिखे हैं।

फिर भी, जमीनी हकीकत आज भी बहुत नहीं बदली है। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में लड़कियों की उन्नति दिखावा मात्र है। जिस समाज में हर रोज कोई लड़की या महिला बलात्कार का शिकार होती हो, उस समाज को प्रगतिशील कहना, दोगलापन है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, देश में प्रतिदिन 81 रेप के पुलिस केस दर्ज होते हैं। ये तो बस आंकड़े हैं, अधिकतर घटनाएं तो लोक-लाज के डर से परिवार और समाज द्वारा छिपा लिए जाते हैं।

अंबिका अंबी

लेखिका

जहां एक तरफ लड़कियों के लिए समान अवसरों की बातें तो बोली जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ घरेलू जिम्मेदारियां लड़कियों पर ही लाद दी जाती हैं। आज भी लड़कियों को खुद के सपने चुनने का अधिकार नहीं है और न ही स्वतंत्रता से कहीं आने-जाने की छूट ही मिलती है। साथ ही, रसोई और घरेलू कामों का बोझ शुरू से ही उनके कंधों पर डाल दिया जाता है।

वास्तविकता में, लड़कियों को स्वतंत्रता और समान अवसर की सुविधाएं केवल मौखिक एवं कागजी स्तर पर ही सीमित रही है। वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कम है। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी है कि शिक्षा में आगे होने के बावजूद कई लड़कियां नौकरी या आगे की पढ़ाई छोड़ देती हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता, लैंगिक भेदभाव, असुरक्षा की भावना और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी चुनौतियां हर कदम पर उन्हें कमजोर करती हैं। आज भी लाखों लड़कियां शिक्षा और नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग का प्राप्त न होना।

डिजिटल युग में साइबर हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न ने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। खुले आम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती हैं और गालियां दी जा रही हैं। यह हिंसा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुंचाती हैं, बल्कि उन्हें ऑनलाइन स्पेस से दूर रहने, अपनी राय व्यक्त न करने या डिजिटल दुनिया से कट जाने पर मजबूर करने की साजिश है। यह क्रूर सच्चाई है कि जहां इंटरनेट ने महिलाओं को आवाज दी, शिक्षा दी और अवसर दिए, वहीं इस प्लेटफॉर्म का उनके खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बचपन से ही शिक्षा और घर-समुदाय स्तर पर हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। सही मायने में, देश की बेटियों की वास्तविक प्रगति तब होगी, जब कानून और योजनाएं सिर्फ घोषणाएं न रहें, बल्कि समाज की सोच बदलने, जमीनी सुरक्षा सुनिश्चित करने, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बांटने और हर बेटी को बराबरी का हक दिलाने में सक्षम बनें। हमारे देश को 'बेटी बचाव, बेटी पढ़ाओ' नारे की अपेक्षा 'समाज और परिवार में बेटियों के प्रति भेदभाव मिटाओ' नारे की ज्यादा ही जरूरत है।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक हरि ओम गुप्ता द्वारा अमृत विचार प्रकाशन, नवादा जोगियान, चक रोड, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने, बरेली (उ.प्र.), पिन कोड-243006 से मुद्रित एवं 932 कटरा चांद खां, भारत पेट्रोल पंप के सामने पीलीभीत बाईपास रोड बरेली (उ.प्र.) पिन कोड-243005 से प्रकाशित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, स्थानीय संपादक- नवीन गुप्ता*** 0581-4000222 (कार्यालय), ईमेल- editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-UPHIN/2019/78502, *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्यायक्षेत्र बरेली होगा)।

कार खरीदना कुछ लोगों के लिए बुनियादी जरूरत है, तो कुछ लोगों के लिए शानो-शौकत और रुतबे का प्रतीक, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों के लिए यह हमेशा से एक सपने के सच होने जैसा है। कार आज हम सभी के घरों का एक जरूरी और अहम हिस्सा बन चुकी है। इस मांग की वजह से ही हाल के वर्षों में पुरानी कारें खरीदने का चलन तेजी से बढ़ा है और देश में पुरानी कारों का बाजार एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। यह तब हुआ है, जब लोगों को भरोसा हुआ है कि पुरानी कारें भी नई कारों जितनी ही अच्छी हो सकती हैं। एक और वजह यह भी है कि पसंदीदा नई कारें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, ऐसे में कम बजट में बेहतर ब्रांड, शानदार फीचर्स की उपलब्धता भी पुरानी कारों की मांग को शहरों से लेकर कस्बों तक आगे बढ़ा रही है। हालांकि काफी सारे लोग पुरानी कार खरीदने में जोखिम और धोखाधड़ी के कारण बचते हैं, लेकिन पुरानी कारों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने के बाद से चीजें काफी आसान भी हो गई हैं।

-मनोज त्रिपाठी, कानपुर

नई कार स्टेटस देती पुरानी कार समझदारी

पुरानी कारों की बिक्री नई कारों से ज्यादा

भारत में पुरानी कारों की बिक्री नई कारों की तुलना में 8 से 10 फीसदी सालाना वृद्धि दर से बढ़ रही है। वर्तमान में प्रत्येक नई कार की बिक्री पर लगभग 1.4 पुरानी कारें बेची जा रही हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार साल 2026 के अंत तक भारत में इस्तेमाल की गई कारों की बिक्री 75 लाख यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है। यही नहीं इस साल देश में पुरानी कारों का बाजार 3.4 लाख करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि पुरानी कारों के बाजार में हिस्सेदारी की बात करें, तो अभी भी सिक्का स्थानीय डीलरों और ब्रोकर का चलता है, जो बाजार के लगभग 68 फीसदी हिस्से पर काबिज हैं, लेकिन ग्राहकों का भरोसा अब वारंटी और सर्टिफाइड कारों के कारण तेजी से संगठित क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो रहा है। इस बदलाव से डिजिटल माध्यमों से होने वाली पुरानी कारों की बिक्री की हिस्सेदारी इस साल के अंत तक करीब 30 फीसदी पहुंचने की उम्मीद है।

मारुति, टाटा, महिंद्रा के साथ ऑनलाइन स्टार्टअप्स ने जीता यूज्ड कार का भरोसा

पुरानी कारों के संगठित कारोबार में मारुति सुजुकी True Value, महिंद्रा First Choice और टाटा मोटर्स Assured जैसे निर्माताओं के साथ Cars24, Spinny, CarDekho और Droom जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ और भी अनेक ऑनलाइन स्टार्टअप्स शामिल हैं। ये सभी सर्टिफाइड गाड़ियां खोजने, टेस्ट ड्राइव बुक करने और पूरी लेनदेन प्रक्रिया में मदद के अलावा अधिकतर कार के मूल्यांकन और कागजी कार्रवाई में भी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे पुरानी कार खरीदना आसान हो जाता है। इनमें Cars24 को पुरानी कारों की खरीद-बिक्री के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आप कार का मूल्यांकन, टेस्ट ड्राइव और पूरी कागजी कार्रवाई जैसे आरसी ट्रांसफर, लोन आदि में मदद पा सकते हैं। Spinny भी एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, जो सर्टिफाइड और अच्छी क्वॉलिटी वाली पुरानी कारों को आसान और सुरक्षित तरीके से खरीदने का बेहतर अनुभव प्रदान कर रहा है। CarDekho पुरानी और नई दोनों तरह की कारों की पूरी जानकारी जैसे मॉडल, कीमत और माइलेज जैसी डिटेल्स प्रदान करता है। इसके मुकाबले Droom ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहां आप विभिन्न कारों की तुलना कर सकते हैं और कई विकल्प देख सकते हैं। इसी कड़ी में CarWale भी एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, जहां आपको पुरानी और नई कारों के ढेर सारे विकल्प मिलते हैं। इनके अतिरिक्त OLX भी पुरानी कारें खरीदने और बेचने के लिए लोकप्रिय ऐप है, जिसमें आप सीधे विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं।

इसलिए बढ़ रहा है पुरानी कारों का बाजार

देश में हर साल लाखों लोग पहली बार कार खरीदते हैं और उनमें से बड़ी संख्या सेकेंड हैंड या यूज्ड कार को प्राथमिकता देती है। इसके पीछे कारण हैं-

- नई कारों की बढ़ती कीमतें
- कम डाउन पेमेंट और आसान फाइनेंस
- डेप्रिसिएशन का कम झटका
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती विश्वसनीयता
- सर्टिफाइड प्री-ओन्ड कार प्रोग्राम्स

इन कारों की मांग सबसे अधिक

बाजार के ट्रेंड पर नजर डालें, तो हैचबैक मारुति स्विफ्ट, वैगनआर, ग्रैंड आई-10 और सेडान में होंडा सिटी, मारुति सियाज, इसी तरह एसयूवी में क्रेटा, ब्रेजा, डस्टर आदि 5 से 7 साल पुरानी, कम चली और अच्छी तरह मेंटेंड कारें सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं।

खरीदने से पहले जरूरी बातें

- सबसे पहले अपना बजट बनाएं,फिर यह देखें कि पुरानी कार फर्स्ट हैंड है या फिर उसके पहले भी कई ऑनर रह चुके हैं। ऐसी कार लेना हमेशा बेहतर होता है, जो कम किलोमीटर चली हो। भारत में, एक कार औसतन सालाना 6 हजार से 12 हजार किलोमीटर चलती है। यह जरूरी है कि आप सर्विस रिकॉर्ड और गाड़ी की पूरी स्थिति के अनुसार चलाए गए किलोमीटर की जांच करें।
- आरसी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच करें। ओडोमीटर रीडिंग और सर्विस हिस्ट्री मिलाएं। कार को दिन की रोशनी में ध्यान से देखें।
- टेस्ट ड्राइव जरूर लें, आवाज, ब्रेक, गियर पर ध्यान दें। किसी अच्छे मैकेनिक से पूरा इंस्पेक्शन करवा लें। इंश्योरेंस ट्रांसफर की प्रक्रिया ठीक से समझें।

ऑनलाइन या ऑफलाइन कहां से खरीदें

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म : ज्यादा विकल्प, पारदर्शी कीमत
- डीलरशिप : भरोसेमंद लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा
- डायरेक्ट ऑनर : सस्ता सौदा, पर जोखिम ज्यादा

Hero Vida Dirt.E K3 : बच्चों के रोमांच को मिली इलेक्ट्रिक उड़ान

बदलते समय के साथ बच्चों की दुनिया भी स्मार्ट और टेक-फ्रेंडली हो रही है। इसी कड़ी में Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने भारत में बच्चों के लिए एक अनोखी और सुरक्षित इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक Dirt.EK3 पेश की है। यह बाइक न सिर्फ खेल-खेल में राइडिंग का मजा देती है, बल्कि सुरक्षा और सीखने, दोनों का पूरा ध्यान रखती है।

दमदार बैटरी

Dirt.EK3 में 360 Wh की रिमूवेबल बैटरी और 500W मोटर दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा तक सीमित रखी गई है। बैटरी महज 2 घंटे में 20% से 80% तक चार्ज हो जाती है और एक बार चार्ज करने पर 2 से 3 घंटे तक राइड का मजा देती है। तीन राइडिंग मोड- Beginner, Amateur और Pro, बच्चों को धीरे-धीरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर देते हैं।

सुरक्षा और स्मार्ट फीचर्स

Vida ने सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं किया है। बाइक में मैग्नेटिक किल स्विच, चेस्ट पैड, ब्रेक रोटर कवर और रियर ग्रैबरेल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि एक मोबाइल ऐप के जरिए माता-पिता बच्चे की राइडिंग एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं, स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं और अन्य पैरामीटर्स नियंत्रित कर सकते हैं।

इंटरनेशनल पहचान

Dirt.E K3 का डिजाइन सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। इसे Red Dot Award 2025 दिया गया है, जो इसकी क्वालिटी और इनोवेशन का प्रमाण है। कुल मिलाकर, Hero Vida Dirt.EK3 बच्चों के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक राइडिंग अनुभव लेकर आई है, जहां रोमांच, सीख और सुरक्षा तीनों का खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है।

कीमत और उपलब्धता

Vida Dirt.EK3 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 69,990 रखी गई है। पहले 300 यूनिट्स इसी कीमत पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यह बच्चों के लिए एक प्रीमियम, लेकिन समझदारी भरा विकल्प बनती है। इसकी बिक्री 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है।

बच्चे के साथ 'बढ़ने' वाली बाइक

इस बाइक की सबसे खास बात है इसका एडजस्टेबल डिजाइन। व्हीलबेस और सस्पेंशन को तीन लेवल- Small, Medium और High पर सेट किया जा सकता है। यानी जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, बाइक भी उसके कद और उम्र के अनुसार ढलती जाएगी। इससे माता-पिता को हर कुछ साल में नई बाइक खरीदने की चिंता नहीं रहती।

मॉय फर्स्ट राइड

सासू मां के साथ मेरी आगे बढ़ने की यात्रा

जीवन में कुछ यात्राएं सड़कों पर तय होती हैं और कुछ हमारे मन और सोच के भीतर। मेरी कार सीखने की यात्रा भी ऐसी ही एक यात्रा रही, जो केवल ड्राइविंग सीखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और बदलाव को अपनाने की कहानी बन गई।

2024 में जब मेरी शादी तय हुई, तब तक मैं कार चलाना नहीं जानती थी। मायके में इसकी कभी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इसलिए यह कौशल मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन शादी के बाद ससुराल का वातावरण अलग था। यहां मेरी सासू मां और ननद दोनों कार चलाती थीं। घर से जुड़ा अधिकांश काम-चाहे फैक्ट्री जाना हो, कच्चा माल लाना हो या बाजार की खरीदारी-कार से ही पूरा होता था। ऐसे में मुझे यह समझ में आने लगा कि अब मुझे भी इस जिम्मेदारी में हाथ बंटाना होगा।

कार सीखने का निर्णय लेना आसान था, लेकिन उसे सीखने की प्रक्रिया उतनी सरल नहीं थी। पहली बार स्टीयरिंग पकड़ते समय हाथ कांप रहे थे। सड़क पर निकलते ही मन में डर और असमंजस बना रहता था। ब्रेक, एक्सेलरेटर और क्लच के बीच तालमेल बैठाने में समय लगा। कई बार छोटी-छोटी गलतियां हुईं, लेकिन हर बार सासू मां ने धैर्य और अपनापन दिखाया। उनका विश्वास और सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ा संबल बना।

धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ा और डर कम होने लगा। सुबह की खाली सड़कों से शुरुआत हुई, फिर मोहल्ले की गलियों से होते हुए मैं मुख्य सड़क तक पहुंच पाई। समय के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। आज मैं अपनी सासू मां के साथ फैक्ट्री के कामों के लिए जाती हूं और बाजार की जिम्मेदारियां भी निभाती हूं। अब कार मेरे लिए केवल एक साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान बन गई है।

इस पूरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। परिस्थितियां जब बदलती हैं, तो हमें भी अपने भीतर बदलाव लाना पड़ता है। परिवार का सहयोग और विश्वास किसी भी नई शुरुआत को आसान बना देता है। सासू मां के साथ मेरा रिश्ता इस दौरान और भी गहरा हुआ, क्योंकि हमने साथ-साथ सीखने और आगे बढ़ने का अनुभव साझा किया।

आज जब मैं कार चलाती हूं, तो मुझे सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती, बल्कि उस सफर का आनंद भी मिलता है, जिसने मुझे आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाया। मेरी कार सीखने की यात्रा वास्तव में मेरे नए जीवन की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा बन चुकी है।

-अपर्णा, कानपुर

काम की बात

सर्दियों में क्यों 'नखरे' दिखाती है बाइक ?

सर्दियों की सुबह बाइक सवारों के लिए अक्सर एक परीक्षा बन जाती है। तापमान गिरते ही कई बाइक्स सेल्फ और किक दोनों पर सुस्त प्रतिक्रिया देने लगती हैं। बार-बार कोशिशों के बाद भी इंजन का स्टार्ट न होना न केवल समय की बर्बादी करता है, बल्कि बाइक की मैकेनिकल सेहत पर भी असर डालता है। ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड में बाइक स्टार्टिंग की समस्या पूरी तरह तकनीकी है और सही समझ के साथ इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

ठंड का बाइक पर असर

कम तापमान में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को घूमने में अधिक प्रतिरोध झेलना पड़ता है। दूसरी ओर, लेड-एसिड बैटरी की केमिकल रिएक्शन क्षमता ठंड में कमजोर हो जाती है, जिससे सेल्फ स्टार्ट का आउटपुट घट जाता है। यही कारण है कि सर्दियों में सुबह के समय बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत करती है, जिससे बाइक सवार को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, खासकर उन वाहनों में जिनका मेंटेनेंस नियमित नहीं होता।

स्टार्टिंग समस्या से निपटने के स्मार्ट तरीके

- **स्पार्क प्लग की भूमिका अहम-** ठंड और नमी के कारण स्पार्क प्लग पर कार्बन डिपॉजिट या नमी जमा हो सकती है, जिससे स्पार्क कमजोर पड़ जाता है। यदि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले स्पार्क प्लग की जांच जरूरी है। प्लग को साफकर दोबारा फिट करने से करंट फ्लो बेहतर होता है और इंजन आसानी से जान पकड़ता है।
- **क्लच ट्रिक से घटेगा लोड-** सर्दियों में गियरबॉक्स ऑयल भी गाढ़ा हो जाता है। बाइक को न्यूट्रल में रखकर क्लच पूरी तरह दबाने से गियरबॉक्स इंजन से अलग हो जाता है। इससे किक मारते समय इंजन पर कम लोड पड़ता है और स्टार्टिंग आसान हो जाती है।
- **चोक का सही और सीमित उपयोग-** कार्बोरेटर वाली बाइक्स में चोक ठंडे इंजन के लिए बेहद उपयोगी है। चोक खींचने से एयर-फ्यूल मिक्सचर रिच हो जाता है, जिससे इंजन जल्दी स्टार्ट होता है। हालांकि इंजन चालू होने के 20-30 सेकंड बाद चोक बंद कर देना चाहिए, वरना फ्यूल कंजम्पशन बढ़ सकता है।
- **इग्निशन ऑफ रखकर प्री-किक तकनीक-** ऑटो मैकेनिक्स के अनुसार, इग्निशन बंद रखकर 3-4 बार खाली किक मारने से सिलेंडर के भीतर गाढ़ा ऑयल फैल जाता है। इससे इंजन के मूविंग पार्ट्स लुब्रिकेट हो जाते हैं और स्टार्टिंग के समय कम प्रतिरोध पैदा होता है।
- **लगातार फेल स्टार्टिंग का नुकसान-** बार-बार सेल्फ मारने से बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है और स्टार्ट मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वहीं, ठंडे इंजन को जबरदस्ती स्टार्ट करने से पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट पर अनावश्यक घर्षण बढ़ता है, जिससे लंबे समय में इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है।
- **एक्सपर्ट्स की मेंटेनेंस सलाह-** ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में बाइक को खुले में खड़ा करने से बचना चाहिए। कवर का इस्तेमाल बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नमी से सुरक्षित रखता है। साथ ही मौसम के अनुसार सही ग्रेड का इंजन ऑयल और समय-समय पर बैटरी हेल्थ चेक करना बेहद जरूरी है।
- **आने वाला कल-** ऑटो इंडस्ट्री ठंडे मौसम के लिए बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी और लो-विस्कोसिटी इंजन ऑयल पर काम कर रही है। जब तक ये तकनीकें आम नहीं होतीं, तब तक सही ड्राइविंग हैबिट्स और बेसिक मेंटेनेंस से सर्दियों में बाइक स्टार्टिंग की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

अमृत विचार

बरेली, सोमवार, 2 फरवरी 2026

न्यूज ब्रीफ

जाली नेपाली और भारतीय मुद्रा के साथ 10 लोग गिरफ्तार

मोतिहारी। बिहार के पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी से 25 लाख 18 हजार 5 सौ की जाली नेपाली और भारतीय मुद्रा बरामद की गयी है। इस मामले में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भारत-नेपाल बार्डर क्षेत्र के रक्सौल में जाली मुद्रा के बड़े कारोबारी नेटवर्क का खुलासा किया है। सीमावर्ती क्षेत्र हरैया थाना की पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी कर्रवाई करते हुए 25 लाख की जाली नेपाली मुद्रा और 18,500 की जाली भारतीय मुद्रा के साथ 4 नेपाली नागरिकों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

तस्करों के हमले में कांस्टेबल की मौत

हैदराबाद। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में हाल में कथित रूप से गांजा तस्करों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई 23 वर्षीय महिला आबकारी कांस्टेबल की यहां सरकारी निम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जी सौम्या को 23 जनवरी को गांजा तस्करों ने उस वक्त कार से टक्कर मार दी थी जब सौम्या ने कार को रुकने का इशारा किया था। टक्कर मारे जाने से सौम्या गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। सौम्या को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें ''निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज'' (निम्स) में स्थानांतरित कर दिया गया जहां शनिवार रात को उन्होंने दम तोड़ दिया।

नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म की कोशिश

बालासोर। ओडिशा के बालासोर जिले में ट्यूशन से लौट रही 12वीं कक्षा की छात्रा का कथित तौर पर दो बदमाशों ने अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना शनिवार शाम को जिले के सोरो पुलिस थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने लड़की को जबरन अगवा कर पास के एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की।

वांगचुक की याचिका पर आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय सोमवार को जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो की याचिका पर सुनवाई करेगा। आंगमो ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत वांगचुक की हिरासत के खिलाफ याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ के इस मामले की सुनवाई करने की संभावना है। जोधपुर केंद्रीय कारागार में हिरासत में रखे गए वांगचुक ने 29 जनवरी को उन आरोपों का खंडन किया कि उन्होंने ''अरब स्प्रिंग'' की तरह सरकार को उखाड़ फेंकने का बयान दिया था, और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें आलोचना तथा विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। वांगचुक की पत्नी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि पुलिस ने हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को गुमराह करने के लिए चुनिंदा वीडियो का इस्तेमाल किया है।

गुम हो गया ट्रेन का आरक्षित डिब्बा

भुवनेश्वर। संबलपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस का एक आरक्षित डिब्बा रविवार को ट्रेन में नहीं जोड़ा जा सका, जिससे ओडिशा के संबलपुर रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। जब ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची, तो एसी थ्री-कोच में टिकट बुक कराने वाले 57 यात्री अपना डिब्बा नहीं ढूंढ पाए, जिससे अफरा-तफरी मच गई। रेलवे ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण, एक आरक्षित कोच (बीई2) को ट्रेन से नहीं जोड़ा जा सका।

रांची में अंतर्राज्यीय टर्मिनल पर छह बसें जलकर राख

बस टर्मिनल पर आग बुझाने में जुटीं दमकल की गाड़ियां ● एजेंसी

रांची। रविवार दोपहर रांची के एक अंतरराज्यीय टर्मिनल पर लगी भीषण आग में वहां खड़ी कम से कम छह बसें जलकर नष्ट हो गईं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लोअर बाजार थाना क्षेत्र के खादगढ़ा में हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि आग एक खराब बस में लगी और उसने जल्द बस के अगल बगल खड़ी अन्य गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। खादगढ़ा पुलिस चौकी के प्रभारी सुनील ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है क्योंकि वाहनों में कोई भी मौजूद नहीं था।

बलूचिस्तान हिंसा में भारत का हाथ नहीं, आरोप निराधार

नई दिल्ली, एजेंसी

- **विदेश मंत्रालय ने कहा-ध्यान भटकाने का काम कर रहा पड़ोसी देश पाकिस्तान**

भारत ने बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को हुई हिंसा में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता के पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया और कहा कि ऐसा कहकर पाकिस्तान अपने आंतरिक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाता है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को बेतुके दावे करने की बजाय अपने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं, जो उसकी अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की उसकी सामान्य रणनीति के अलावा और कुछ नहीं है।

हर बार जब कोई हिंसक घटना होती है, तो ऐसे दावों को दोहराने की बजाय पाकिस्तान को अपने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। दमन, क्रूरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन का उसका रिकॉर्ड जगजाहिर है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल।

यह बयान पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी द्वारा हमलों में भारत पर शामिल होने का आरोप लगाने के बाद आया है। भारत ने पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे दमन को उजागर करके पलटवार किया।

बलूचिस्तान में 16 जगहों पर हुए हमले

गौरतलब है कि शनिवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कम से कम 16 जगहों पर हमले हुए। क्वेटा, ग्वादर, कल्लात, खारान, मस्तुंग, पसनी, दलबांदिन, नोशकी, बुलाइदा, टंप, मच और आसपास के इलाकों में विस्फोट और सशस्त्र हमलों की सूचना मिली। बलूचिस्तान में हुई हिंसा की जिम्मेदारी शनिवार को बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने ''ऑपरेशन हेरोफ फेज दो'' के हिस्से के रूप में ली। बीएलए के अनुसार दस घंटे की अवधि में 14 शहरों में हुए हमलों में सैन्य, प्रशासनिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया।

हमलों में मारे गए थे 84 सुरक्षाकर्मी

बलूच समूह ने दावा किया कि हिंसा में 84 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, 18 को जिंदा पकड़ा गया, 30 सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया या जब्त कर लिया गया और 23 दुश्मन वाहनों में आग लगा दी गई। बीएलए ने यह भी कहा कि उसने केंद्रीय सैन्य मुख्यालय सहित कई दुश्मन चौकियों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे कई शहरों में आवाजाही प्रतिबंधित हो गई। कई वीडियो में हमलों की पुष्टि हुई।

विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने को मिशन मोड में काम कर रहा देश

संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि

जालंधर, एजेंसी

पंजाब के जालंधर में गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते संत निरंजन दास (बीच में)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश अब मिशन मोड में काम कर रहा है ताकि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त हो और गुरु रविदास के उस समाज के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके जहां कोई भी वंचित न रहे। मोदी ने रविवार को यहां डेरा सचखंड बल्लां की यात्रा की और समाज सुधारक तथा कवि के रूप में याद किए जाने वाले संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज जी ने भारत के लिए भविष्य की एक संकल्पना भी पेश की थी।

मुझे संतोष है कि आज देश मिशन मोड में इस संकल्पना को साकार करने में जुटा है। इसी मिशन का नाम है - विकसित भारत! प्रधानमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत का अर्थ है ऐसा देश जहां किसी को भी गरीबी में जीने के लिए मजबूर न होना पड़े, जहां सभी का सम्मान हो और सभी को अवसर प्राप्त हों।

संत रविदास के आशीर्वाद से, मुझे पूरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। संप्रदाय के प्रमुख संत निरंजन दास को 25 जनवरी को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसके कुछ दिन बाद मोदी ने यह यात्रा की।

जालंधर के बल्लां में स्थित डेरा सचखंड, राज्य में रविदासिया समुदाय का सबसे बड़ा डेरा है। पिछले साल दिसंबर में, डेरा प्रमुख संत दास ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें एक फरवरी को गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर आने के लिए आमंत्रित किया था।

आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी किया

जालंधर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को संत गुरु रविदास की जयंती के मौके पर आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर उनके नाम पर रख दिया। उन्होंने लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री अपराह्न लगभग तीन बजकर 45 मिनट पर आदमपुर हवाई अड्डे पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह सम्मान और गौरव की बात है कि आज संत रविदास जयंती के पावन अवसर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि आदमपुर हवाई अड्डे को अब श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर मोदी यहां डेरा सचखंड बल्लां भी गए।

पुष्पों के बीच महामहिम...

राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आमजन के अवलोकन के लिए तीन फरवरी को खोला जाएगा। रविवार को शीतकालीन वार्षिक संस्करण के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपस्थित थीं। ● एजेंसी

हादसे में पांच महिलाओं की मौत

दीमापुर। नागालैंड में कोहिमा जिले के 10 माइल रोड पर एक बस के पलट जाने से पांच महिलाओं की मौत हो गयी। कोहिमा पुलिस के सूत्रों ने रविवार को बताया कि घटना शनिवार की देर रात उस समय हुई जब मोकोकचुंग में एक कार्यक्रम के बाद चर्च के 32 सदस्यों को ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में पांच महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गयी। उनके शवों को दुर्घटनाग्रस्त बसे से निकाला गया और सभी जरुरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके परिवारों को सौंप दिया गया।

अमेरिका, कनाडा भेजे जा रहे पार्सल जब्त

लुधियाना। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की लुधियाना जोनल यूनिट ने अमेरिका और कनाडा भेजे जा रहे सात कूरियर पार्सल जब्त किए और उनमें छिपाकर रखे गए अफीम के 30 पैकेट बरामद किए। डीआरआई के अधिकारियों के अनुसार, पैकेटों से 12.1 किलोग्राम से अधिक अफीम बरामद की गई, जिसका अवैध बाजार में मूल्य लगभग 60.59 लाख रुपये है, और बाद में इसे स्वापक औषधि एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, डीआरआई अधिकारियों ने शनिवार को यहां एक कूरियर कार्यालय में पार्सलों को जब्त कर लिया और गहन जांच के बाद बर्तनों और ''एडल्ट डायपर पैड'' के अंदर छिपाए गए प्रतिबंधित सामान के 30 पैकेट बरामद किए गए।

फिल्मकार रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी में 4 संदिग्ध गिरफ्तार

मुंबई, एजेंसी

- **घटना के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ होने का संदेह**

फिल्मकार रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास पर गोलीबारी के मामले में रविवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में इन लोगों के लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य और राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी शुभम लोनकर के साथ जुड़े होने के संकेत मिले हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया है, वे पुणे में इस मामले के सिलसिले में हिरासत में लिए गए पांच संदिग्धों में शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को मुंबई लाया गया, जहां एक अदालत ने उन्हें पांच फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अधिकारी के मुताबिक, गोलीबारी की घटना के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि इस वारदात के पीछे लोनकर का हाथ था। अधिकारियों ने बताया कि जूहू इलाके में स्थित नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर शनिवार देर रात करीब 12:45 बजे कम से कम पांच गोलियां चलाई गईं। उन्होंने बताया कि एक गोली इमारत में स्थित जिम के शीशे में जा लगी। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ और फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि घटना के समय शेट्टी अपने आवास पर मौजूद थे या नहीं।

अधिकारी के अनुसार, गोलीबारी के बाद शेट्टी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा, स्थानीय पुलिस और अपराध शाखा की टीम मामले की जांच कर रही हैं। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटनाक्रम की कड़ी जोड़ने के लिए इमारत के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक विज्ञान और बैलिस्टिक विशेषज्ञों की टीम भी साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचीं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुणे पुलिस के डीसीपी (जोन-3) संभाजी कदम ने बताया कि वारजे मालवाड़ी थाने के पुलिसकर्मियों ने शुरू में पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया थापुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए आरोपियों के संबंध लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य शुभम लोनकर से हैं, जो राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी है।

पलामू में पति-पत्नी और बेटे की हत्या बहु-पोती गंभीर

रांची, एजेंसी: झारखंड के पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसडी गांव में पति-पत्नी और उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान विजय भुइयां, उनकी पत्नी और बेटे के रूप में हुई है।

इस हमले में विजय भुइयां की बहु नीलू देवी और पोती ममता कुमारी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एमएमसीएच) में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। घटनास्थल पांकी थाना से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है। थाना प्रभारी रंजन ने बताया कि ग्रामीणों के माध्यम से पुलिस को तीन लोगों की हत्या की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई।

राकांपा राजग में बनी रहेगी, विलय की अटकलों पर बोले सुनील तटकरे

मुंबई, एजेंसी

- **कहा-संगठन दिवंगत अजित पवार की विचारधारा पर आगे बढ़ेगा**

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी भाजपा नीत राजग का हिस्सा बनी रहेगी और संगठन दिवंगत अजित पवार द्वारा निर्धारित विचारधारा एवं मार्ग पर आगे बढ़ेगा। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब यह दावा किया जा रहा था कि राकांपा और राकांपा (शरदचंद्र पवार) के विलय की घोषणा की तारीख 12 फरवरी तय कर दी गई थी। राकांपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में तटकरे ने कहा कि लोग चाहे कुछ भी कहें, हमारा रुख स्पष्ट है। हम पार्टी और अजित दादा की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हम इस रुख पर अडिग हैं। रायगड के सांसद ने कहा कि हम राजग के साथ हैं और राजग के साथ ही रहेंगे। अजित दादा ने यह निर्णय सोच-समझकर लिया था।

तटकरे ने कहा कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ तालमेल का निर्णय अजित पवार के नेतृत्व में सामूहिक रूप से लिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अजित पवार की सहमति के बिना कभी कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया। अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की जल्दबाजी पर आलोचना का जिक्र करते हुए तटकरे ने कहा कि संविधान सभी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता है।

मैं राकांपा अध्यक्ष नहीं खबरें निराधार : पटेल

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने रविवार को उन खबरों को निराधार बताया, जिनमें उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की बात कही गई थी। पटेल ने एक्स पर कहा कि मैंने राकांपा अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति के संबंध में मीडिया में प्रसारित हो रही कुछ खबरों पर गौर किया है। मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि ये खबरें पूरी तरह निराधार हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पटेल का यह बयान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों के बाद आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक संस्था है। इतना बड़ा फैसला हमारे वरिष्ठ नेतृत्व और विधायकों से परामर्श करने के बाद ही लिया जाना संभव होगा।

तटरक्षक बल राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत स्तंभः राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी

- **भारतीय तटरक्षक बल के 50वें स्थापना दिवस पर बोले रक्षा मंत्री**

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की बहु-स्तरीय समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में उत्कृष्ट अंतर-सेवा समन्वय देखने को मिला। सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के 50वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि संवेदनशील समुद्री परिस्थितियों के दौरान बल ने त्वरित और सशक्त प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिमी तट पर निगरानी बढ़ाई और उच्च सतर्कता बनाए रखी।

रक्षा मंत्री ने तटरक्षक बल को भारत की समुद्री सीमाओं पर विश्वास की दीवार बताते हुए कहा कि आतंकवाद, तस्करी, समुद्री डकैती, नशीले पदार्थों की तस्करी और समुद्री प्रदूषण से निपटने में इसकी भूमिका निर्णायक रही है। उन्होंने कहा कि स्थापना के बाद से बल ने 11,800 से अधिक लोगों की जान बचाई है। सिंह ने तटरक्षक बल को राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बताते हुए अधिकारियों से 2047 तक के लिए स्पष्ट और दूरदर्शी रोडमैप तैयार करने का आह्वान किया।

एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि याचिका में निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत में यह याचिका 28 जनवरी को दायर की गई थी। ममता रविवार को दिल्ली पहुंचीं। सोमवार को शाम चार बजे उनका मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान वह पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा कर सकती हैं। ममता के साथ पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा।

मौसम ने ली करवट | उत्तर भारत में ठंड में आई कुछ कमी, रात के तापमान में दर्ज की गई वृद्धि

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश और बर्फबारी

नई दिल्ली, एजेंसी

हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में ताजा बर्फ से ढके घर और सड़कें ● एजेंसी

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रविवार को बर्फबारी और बारिश हुई। वहीं, उत्तरी राज्यों में रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम और कुलगाम जिले के काजीगुंड क्षेत्र में हिमपात हुआ, जबकि श्रीनगर शहर सहित दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में बारिश हुई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, श्रीनगर शहर में शनिवार रात न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछली रात के 0.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। विभाग के अनुसार, बारामूला जिले का गुलमर्ग स्की रिसॉर्ट जम्मू-कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान शून्य से सात डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात शून्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा था। काजीगुंड में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कोकरनाग में पारा शून्य डिग्री सेल्सियस और कुपवाड़ा में शून्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में रविवार को हल्की बर्फबारी के साथ बारिश हुई। राज्य में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला जिले के शिलारू और कुल्लू जिले के कोठी में पांच सेंटीमीटर हिमपात हुआ, जबकि कुफरी में चार सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। लाहौल और स्पीति के गोंधला गांव में तीन सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। हिमाचल के मध्य और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में दो और तीन फरवरी को हिमपात और बारिश जारी रहने की प्रबल संभावना है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे अन्य उत्तरी राज्यों में सर्दी की मार कम हो गई है।

दिल्ली में माह की शुरुआत ज्यादा ठंडी रही

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में पिछले साल की तुलना में इस वर्ष फरवरी की शुरुआत ज्यादा ठंडी रही और एक फरवरी को अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल एक फरवरी को अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के औसत से लगभग 3.7 डिग्री अधिक है। सफदरजंग में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। शहर में औसत एक्यूआई 265 दर्ज किया गया।

जेफरी एपस्टीन फाइल : ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू से पूछताछ का बढ़ा दबाव

लंदन, एजेंसी

● पूर्व प्रिंस पर महिला ने लगाया है यौन संबंध बनाने का आरोप

ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर पर यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के अपराधों के स्तर की जांच कर रही अमेरिकी समिति के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने का दबाव बढ़ गया है। विंडसर की शाही स्थिति उनके भाई और ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने रद्द कर दी थी।

मामले में एक महिला ने आरोप लगाया है कि एपस्टीन उसे 2010 में तत्कालीन प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए ब्रिटेन ले गया था। महिला का दावा है कि वह विंडसर कैसल एस्टेट स्थित एंड्रयू के शाही निवास में गई थी। ब्रिटिश राजपरिवार के पूर्व सदस्य पर इस तरह का आरोप लगाने वाली यह दूसरी महिला है।

एंड्रयू लगातार आरोपों से इनकार करते रहे हैं। हालांकि, नवीनतम मामले में उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जापान की यात्रा पर गए ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने रविवार को इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि मैंने हमेशा एपस्टीन के कृत्यों से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता देते हुए मामले पर विचार किया है।

एपस्टीन के पत्राचार में मैक्रों का भी जिक्र

वाशिंगटन। जेफरी एपस्टीन ने कथित तौर पर अपने पत्राचार में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का जिक्र किया था, जो एक प्रगतिशील एजेंडा को बढ़ावा देने की संभावनाओं में रुचि रखते थे। नए दस्तावेज़ों में रविवार को यह दावा किया गया। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा प्रकाशित एपस्टीन मामले में एक ई-मेल की कॉपी में यह कहा गया है। यह पत्र सितंबर 2018 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे को एक ऐसी ई-मेल से भेजा गया था।

चिकित्सकों ने तलाश ली घातक सल्फास विषाक्तता की काट

● चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों को मिली बड़ी सफलता

चंडीगढ़, एजेंसी

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा एंव अनुसंधान (पीजीआईएमईआर) के चिकित्सकों ने एल्युमिनियम फॉस्फाइड (जिसे आमतौर पर सल्फास के नाम से जाना जाता है) नामक घातक कीटनाशक से होने वाली विषाक्तता के उपचार में एक बड़ी सफलता हासिल की है।

पीजीआईएमईआर ने एक बयान में बताया कि संस्थान के आंतरिक चिकित्सा विभाग द्वारा किये गए अनुसंधान में पहली बार प्रदर्शित किया गया कि सल्फास की विषाक्तता के इलाज में इंट्रावेनस लिपिड इमल्शन प्रभावी जीवन रक्षक तरीका है। बयान के मुताबिक इन महत्वपूर्ण निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिका यूरोपियन रिव्यू ऑफ मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेज में प्रकाशित किया गया है, जिससे इस अध्ययन को वैश्विक मान्यता मिली है। पीजीआईएमईआर के मुताबिक अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट होता कि इस इलाज पद्धति को तुरंत इस्तेमाल करने से एल्यूमीनियम फॉस्फाइड विषाक्तता के इलाज में अहम बदलाव आ सकता है। इसमें कहा गया कि अध्ययन के परिणाम बेहद उत्साहजनक थे। जिन रोगियों को मानक चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त अंतःशिरा लिपिड इमल्शन दिया गया, उनमें मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई, साथ ही गंभीर चयापचय अम्लता का तेजी से सुधार हुआ, हेमोडायनामिक स्थिरता में सुधार हुआ तथा सदमे और हृदय संबंधी जटिलताओं से पीड़ित रोगियों सहित गंभीर रूप से बीमार रोगियों में बेहतर परिणाम प्राप्त हुए।

कम लागत में अब आसानी से मिलेगा उपचार

चिकित्सकों के मुताबिक इस नवीन उपचार का एक प्रमुख लाभ इसकी व्यावहारिकता है, क्योंकि इंट्रावेनस लिपिड इमल्शन सस्ता है, व्यापक रूप से उपलब्ध है, और पहले से ही भारत भर के अधिकांश अस्पतालों में, जिनमें जिला अस्पताल और परिधीय स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं, स्टॉक में मौजूद है। बयान में कहा गया है कि इसकी कम लागत और आसानी से उपलब्धता के कारण, इस चिकित्सा पद्धति में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फ़ोस विषाक्तता का बोझ सबसे अधिक है और उन्नत गहन देखभाल तक पहुंच अक्सर सीमित होती है। संस्थान ने कहा कि कम लागत और आसानी से उपलब्धता के कारण, इस चिकित्सा पद्धति में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फ़ोस विषाक्तता के मामले सबसे अधिक आते हैं और उन्नत गहन देखभाल तक पहुंच सीमित होती है।

गंभीर जन स्वास्थ्य के लिए था चुनौती

इसमें कहा गया कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड विषाक्तता एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में, जहां अनाज को संरक्षित रखने के लिए इस यौगिक का व्यापक इस्तेमाल होता है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए एक प्रभावी, किफायती और साक्ष्य-आधारित उपचार की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बयान के अनुसार, यह अध्ययन पीजीआईएमईआर के आंतरिक चिकित्सा विभाग के डीन (अकादमिक), प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. संजय जैन के मार्गदर्शन में किया गया था।

वर्ल्ड ब्रीफ

सिंगापुर में हिंदुओं ने मनाया थाईपुसम

सिंगापुर। सिंगापुर के संस्कृति मंत्री दिनेश वासु दास ने यहां श्रद्धालुओं के साथ एक धार्मिक उत्सव में भाग लिया। मंत्री ने रविवार को थाईपुसम उत्सव में भाग लिया। उत्सव के तहत श्रीनिवास पेरुमल मंदिर से श्री थेंदायुथपानी मंदिर तक शोभायात्रा निकाली गई और इस दौरान श्रद्धालुओं ने 3 .2 किलोमीटर तक यात्रा की। श्रद्धालु अपने साथ पालकुडम (दूध के पात्र) लिए हुए थे। हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड (एचईबी) ने बताया कि शोभायात्रा शनिवार देर रात शुरू हुई और रविवार तक जारी रही। शोभायात्रा में सिंगापुर के संस्कृति, समुदाय और युवा एवं श्रमशक्ति मंत्री दिनेश वासु दास और उनकी पत्नी डॉ. रथीगा वेलाइथन भी शामिल थीं।

आइवरी कोस्ट में हादसे में 14 की मौत

अबिजान। आइवरी कोस्ट में शनिवार को एक सड़क हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हादसा सुबह करीब पांच बजे कबाडूगू इलाके में हुआ और इसमें एक ट्रक शामिल था जो अनाज ले जा रहा था और जिसमें अवैध रूप से 69 यात्री सवार थे। परिवहन मंत्री अमादौ कोन ने कबाडूगू क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों को हादसे की शुरुआती जानकारी इकट्ठा करने के लिए तुरंत मौके पर जाने का निर्देश दिया है।

थाईलैंड में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू

बैंकॉक। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए पूर्व मतदान रविवार को शुरू हुआ जिसमें 20 लाख से ज्यादा पात्र मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, जो आठ फरवरी को आधिकारिक मतदान के दिन अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। मतदान शाम 5 बजे समाप्त होगा और आठ फरवरी के बाद सभी मतपत्रों की गिनती की जाएगी। चुनाव में पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 500 सदस्य चुनेंगे।

एयर इंडिया की शंघाई दिल्ली उड़ान शुरू

बीजिंग। एयर इंडिया ने रविवार को शंघाई और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की। इसी के साथ लगभग छह वर्षों के अंतराल के बाद दोनों शहरों के बीच विमानन कंपनी की सेवाएं फिर से बहाल हो गईं। शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के मुताबिक, शंघाई और नई दिल्ली के बीच उड़ान शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई। इस उड़ान में 230 से अधिक यात्री सवार थे। लगभग छह वर्षों के बाद एयर इंडिया की उड़ानों की बहाली, 2020 की शुरुआत में सेवाओं के निलंबन के बाद महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है।

अमेरिका ने युद्ध छेड़ा तो इस बार पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आएगा

ट्रंप की जंग की धमकी पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने दी चेतावनी

● खामेनेई ने दोहराया, ईरान पर हमलावरों को देंगे कड़ा जवाब

दुबई, एजेंसी

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी पर पलटवार करते हुए रविवार को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने हमला किया, तो पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन और इससे जुड़े युद्धपोत फिलहाल अरब सागर में तैनात हैं, जिन्हें ट्रंप ने तेहरान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद भेजा था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप सैन्य ताकत का उपयोग करेंगे या नहीं।

उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हल होते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि, खामेनेई ने राष्ट्रीय स्तर पर जारी विरोध प्रदर्शनों को तख्तापलट जैसा बताया और कहा कि इससे सरकार का रुख और कड़ा हो गया है। विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से लाखों लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ईरान में राजद्रोह के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। इससे यह चिंता फिर से बढ़ गई है कि तेहरान गिरफ्तार लोगों को सामूहिक रूप से फांसी दे सकता है। ईरान ने रविवार और सोमवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य अभ्यास करने की योजना भी बनाई है। होर्मुज जलडमरूमध्य से बड़ी मात्रा में दुनियाभर में तेल की ढुलाई होती है। खामेनेई ने कहा, अमेरिकियों को यह समझ लेना चाहिए कि यदि वे युद्ध शुरू करते हैं, तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामेनेई ने कहा, हम न तो उकसाने वाले हैं और न ही किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरान पर जो कोई भी हमला करेगा उसे ईरानी जनता कड़ा जवाब देगी।

ईयू सेनाओं को आतंकवादी समूह मानता है ईरान

दुबई। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने रविवार को कहा कि इस्लामी गणराज्य अब यूरोपीय संघ की सभी सेनाओं को आतंकवादी संगठन मानता है। उनका यह कड़ा बयान उस फैसले के बाद आया है, जिसमें यूरोपीय संघ ने देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई को लेकर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर क़ालिबाफ द्वारा की गई यह घोषणा मुख्यत: प्रतीकात्मक मानी जा रही है। ईरान 2019 में पारित एक कानून के तहत पहले भी अमेरिका द्वारा रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में अन्य देशों की सेनाओं को आतंकवादी संगठन करार दे चुका है।

हालिया प्रदर्शन तख्तापलट जैसा

दुबई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने देशभर में जारी उन विरोध-प्रदर्शनों की तुलना एक तख्तापलट से की, जिनसे वहां की धार्मिक शासन व्यवस्था को चुनौती मिली है। ईरान के सर्वोच्च नेता 86 वर्षीय खामेनेई की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में कथित तौर पर हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान में राजद्रोह के आरोपों में मौत की सजा तक का प्रावधान है। ईरान में 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। शुरुआत में ईरानी मुद्रा रियाल के पतन के विरोध में हुए थे। जल्द ही ये खामेनेई शासन के लिए चुनौती बन गए।

फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम से पूछताछ

हैदराबाद। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) रविवार को बीआरएस की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान फोन टैपिंग से संबंधित एक मामले में तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष अपने आवास पर पूछताछ के लिए पेश हुए। पूछताछ से कुछ घंटे पहले, राव हैदराबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर येर्रावल्ली स्थित अपने फार्म हाउस से निकले और एसआईटी के सामने पेश होने के लिए नंदी नगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। एसआईटी अधिकारियों का एक दल भी बीआरएस अध्यक्ष के आवास पहुंचा। राव के आवास के पास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और गली को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। केसीआर के नाम से चर्चित राव ने शनिवार को एसआईटी से कहा था कि वह एक फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होंगे। उन्होंने नोटिस जारी करने में जांच अधिकारी पर कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किए जाने का भी आरोप लगाया। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने रविवार को कांग्रेस सरकार द्वारा उनके नेता के राजनीतिक उत्पीड़न के विरोध में तेलंगाना में प्रदर्शन किया।

सरकारों के हाथ से निजी कंपनियों को जा रही सत्ता

● संरा महासचिव ने किया शांति, न्याय, सतत विकास का आह्वान

न्यूयॉर्क, एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच शांति, न्याय और सतत विकास के लिए नए प्रयासों का आह्वान किया है। गुटेरेस ने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि दुनिया शायद हमारे समय के सबसे बड़े सत्ता हस्तांतरण से गुजर रही है। सत्ता सरकारों से निजी तकनीकी कंपनियों के हाथों में जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी, जब व्यवहार, चुनाव, बाजार और यहां तक कि संघर्षों को आकार देने वाली तकनीकें बिना किसी सुरक्षा घेरे के काम करती हैं, तो प्रतिक्रिया नवाचार नहीं, अस्थिरता होती है।

महासचिव ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष यानि 2026 की प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश करते हुए कहा कि 2026 'अभी से निरंतर आश्चर्य और उथल-पुथल वाले वर्ष के रूप में आकार ले रहा है।' उन्होंने कहा कि अत्यधिक बदलाव के समय में वह उन सिद्धांतों की ओर लौटते हैं, जो बताते हैं कि ताकतें कैसे काम करती हैं। इसमें न्यूटन का तीसरा नियम भी है, जो कहता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गुटेरेस ने कहा, इस वर्ष की शुरुआत में, हम ऐसी कार्रवाइयों को चुनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं जो ठोस और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करें। हमारे संकटपूर्ण समय में शांति, न्याय, जिम्मेदारी और प्रगति की प्रतिक्रियाएं। महासचिव ने चैन रिएक्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज दंड न मिलने का भाव संघर्षों को बढ़ावा दे रहा है, अविश्वास गहरा रहा है और हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।

संरचनाएं पुरानी हो सकती हैं, मूल्य नहीं

संयुक्त राष्ट्र की ओर इशारा करते हुए गुटेरेस ने कहा कि संरचनाएं पुरानी हो सकती हैं, लेकिन मूल्य नहीं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर लिखने वाले लोग समझते थे कि हमारे संस्थापक दस्तावेजों में निहित मूल्य केवल ऊंचे विचार नहीं थे बल्कि स्थायी शांति और न्याय के लिए अनिवार्य शर्त थे।

तुर्किये में बस दुर्घटना में आठ लोगों की मौत

इस्तांबुल। तुर्किये के अंताल्या प्रांत में एक यात्री बस के सड़क से फिसलकर पलट जाने से इसमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकारी प्रसारक टीआरटी द्वारा प्रसारित तस्वीरों में बस डोसेमेल्टी जिले में एक राजमार्ग से फिसलकर पलटती दिखती है। प्रांतीय गवर्नर हुलुसी साहिन ने बताया कि इस दुर्घटना में 26 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। समाचार एजेंसी डीएचए के अनुसार, बस के पलटने के बाद कुछ यात्री इसमें से बाहर निकलने में सफल रहे। भूमध्य सागर के किनारे स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल अंताल्या में हाल के दिनों में भारी बारिश हुई है।

धोखाधड़ी में 36 भारतीयों सहित दो हजार गिरफ्तार

नोम पेन्ह, एजेंसी

● कंबोडिया में कैसिनो में छापामारी के दौरान की गई कार्रवाई

कंबोडिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ नवीनतम कार्रवाई के दौरान कुल 2,044 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 36 भारतीय भी शामिल हैं। यह जानकारी कंबोडियाई गृह मंत्रालय ने रविवार को दी। शनिवार को दक्षिणपूर्वी स्वे रींग प्रांत के बावेत शहर में 22 इमारतों वाले एक कैसिनो पर छापेमारी के दौरान आठ अलग-अलग देशों के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार कुल 2,044 विदेशी नागरिकों में 1,792 चीनी, 177 वियतनामी, 179 म्यांमारी, 30 नेपाली, पांच ताइवानी, एक मलेशियाई, दो लाओसी, 36 भारतीय और एक मैक्सिकन नागरिक हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता टच सोखाक ने कहा कि कंबोडियाई सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई में कभी ढील नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कंबोडिया अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं बल्कि नरक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू की है। पिछले सात महीनों में 23 देशों के कुल 5,106 धोखाधड़ी के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

इजराइल ने रफाह सीमा को प्रायोगिक तौर पर खोला

काहिरा। इजराइल ने फलस्तीनियों के सीमित आवागमन के मद्देनजर गाजा की मिस्र के साथ रफाह सीमा क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद रफाह सीमा क्रॉसिंग पर रविवार को चहल-पहल देखी गई। रफाह सीमा क्रॉसिंग को दोबारा खोलना इजराइल-हमास संघर्षविराम के आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल ने रविवार को घोषणा की कि रफाह क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोल दिया गया है। गाजा को मानवीय सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली इज़राइली सैन्य एजेंसी सीओजीएटी ने एक बयान में कहा कि क्रॉसिंग को पूर्ण संचालन के लिए सक्रिय रूप से तैयार किया जा रहा है।

ट्रंप का दावा, भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से खरीदेगा तेल

न्यूयॉर्क, एजेंसी

● अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा तेल के लिए चीन भी कर सकता है सौदा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने शनिवार को फ्लोरिडा के पाम बीच जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी इस सवाल के जवाब में की कि क्या चीन वेनेजुएला को दिए गए कर्ज की भरपाई तेल आपूर्ति के बदले कर पाएगा।

ट्रंप ने कहा कि चीन का स्वागत है और वह तेल के मामले में एक बड़ा सौदा कर सकता है। हम चीन का स्वागत करते हैं। हम पहले ही एक सौदा कर चुके हैं। भारत आ रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। हमने पहले ही यह सौदा कर लिया है, कम से कम इस सौदे की अवधारणा तो तय हो चुकी है। ट्रंप की इन टिप्पणियों पर नई दिल्ली की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत 2019 तक ईरानी तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है, लेकिन तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंध दोबारा लगाए जाने के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात में काफी कटौती कर दी थी।

ट्रंप के ये बयान ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों और इन देशों से कच्चा तेल न खरीदने को लेकर प्रमुख ऊर्जा आयातक देशों पर बनाए जा रहे दबाव की पृष्ठभूमि में आए हैं। हाल के वर्षों में भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिससे रूस भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगाया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद के कारण लगाया गया 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा एवं विस्तृत करने पर सहमति जताई।

आज का भविष्यफल -पं.मनोज कुमार द्विवेदी

आज की ग्रह स्थिति : 2 फरवरी, सोमवार 2026 संवत-2082, शक संवत 1947 मास-फाल्गुन, पक्ष-कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा 3 फरवरी 01 .52 तक तत्पश्चात द्वितीया।

आज का पंचांग

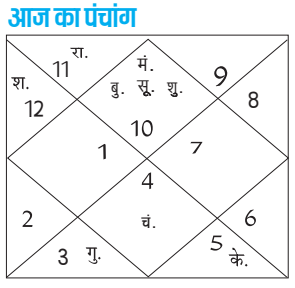

दिशाशूल- पूर्व, **ऋतु**- शिशिर।
चन्द्रबल- वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ।
ताराबल- अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद, रेवती।
नक्षत्र-अश्लेशा 22 .47 तक तत्पश्चात मघा।

मेष — आज आयात-निर्यात के कारोबार में तेजी आएगी। अधिकारी वर्ग आपकी अनदेखी कर सकते हैं। विरोधियों को हल्के में न लें। अपनी जीवनशैली को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। धार्मिक साहित्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है।

वृष — आज तीर्थ यात्रा सुखद रहेगी। व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप अपनी योजनाओं को लेकर थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नए दोस्त बन सकते हैं। परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। धर्म-कर्म के प्रति विश्वास बनाए रखें।

मिथुन — आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को प्रोफेशनल जीवन से अधिक महत्व देंगे। जीवनसाथी से अपने मन की बातें शेयर करने के लिए दिन उत्तम है। प्रेम संबंधों को लेकर परिवार में चर्चा हो सकती है। वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद रहेगा।

कर्क — आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का दबाव रहेगा। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां रहेंगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में उत्तम सफलता मिल सकती है।

सिंह — आज दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। व्यवसाय में आपको कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। धन लाभ के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। विदेश से जॉब के अवसर मिलने की संभावना है। बुद्धिमान लोगों के बीच आपका दायरा मजबूत होगा।

कन्या — आज दिन का शुरुआती भाग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप कुछ नया सीखने को लेकर प्रेरित हो सकते हैं। आपके ऊपर पुराने ऋण को चुकाने का दबाव हो सकता है। संपत्ति के क्रय-विक्रय से बेहतरीन लाभ मिलेगा। शाम को सिरदर्द की शिकायत होगी।

तुला — आज इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का काम बढ़ने वाला है। गुप्त शत्रुओं की वजह से कार्यक्षेत्र में कुछ समस्या हो सकती है। रचनात्मक कार्यों में आप रुचि लेंगे। दूसरों के झगड़ों में मध्यस्थता न करें। ऑनलाइन कारोबार में आपको बड़ा लाभ होगा।

वृश्चिक — आज आय के नए स्रोत विकसित होने के योग बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद लेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा।

धनु — आज आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र की राजनीति के कारण आपको समस्या होगी। जॉब में आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है। अपने खर्चों को नियंत्रित रखने का प्रयास करें।

मकर — आज शाम को आपके कुछ काम बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ अच्छा करें वही आपको महत्व न दें। नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। नजदीकी व्यक्तियों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे।

कुंभ — आज फाइनेंस और लोन से जुड़े हुए अटके काम शुरू हो सकते हैं। नए कारोबार की शुरुआत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपकी इच्छाशक्ति आपके लिए विपरीत परिस्थितियों में ढाल के रूप में काम करेगी।

मीन — आज सहकर्मियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। संपत्ति विवादों का समाधान निकल सकता है। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचें। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जॉब की चिंता हो सकती है। संतान की चिंता हो सकती है।

सुडोकू-49

सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल है, जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। जब आप इस खेल को खेलना सीख जाते हैं तो यह बहुत ही सरलता से खेला जा सकता है। सुडोकू खेल में बॉक्स में 1 नंबर से 9 नंबर तक आने वाले अंक दिए हैं। इसमें कुछ बॉक्स खाली हैं, जिन्हें आपको भरना है। कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन तथा बॉक्स में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए।

			6				8	
	8	9			4			5
3			2			7		
	2			8	9			6
		7				3	9	
9				1			4	
		1			7			8
4			1			9	5	
	9				5			

सुडोकू - 48 का हल

7	6	5	9	3	1	2	4	8
9	4	3	6	2	8	1	5	7
8	2	1	5	7	4	3	9	6
5	9	6	8	1	3	7	2	4
3	7	4	2	5	9	8	6	1
1	8	2	7	4	6	9	3	5
4	3	7	1	6	2	5	8	9
6	1	9	3	8	5	4	7	2
2	5	8	4	9	7	6	1	3

मुझे लगता है कि हमारी टीम को अलग-अलग तरह की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। चेन्नई में हम तीन मैच खेलेंगे और हो सकता है कि वहां की पिच यहां की पिच की तुलना में अलग हो या फिर वैसी ही हो। और अगर ऐसा होता है, तो हमें पता है कि कैसे खेलना है।
-मिचेल सैंटनर

स्टेडियम

बरेली, सोमवार, 2 फरवरी 2026

अमृत विचार

www.amritvichar.com

हाईलाइट

लवलीना, पूजा करेंगी भारतीय मुक्केबाजी टीम की अगुवाई

ला नुसिया (स्पेन)। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और ओलंपियन पूजा रानी मंगलवार को स्पेन के एलिकांटे के ला नुसिया में होने वाले बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 में भारत की 33 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम की अगुवाई करेंगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल के स्वर्ण पदक विजेता हितेश गुलिया और सचिन सिवाच भी इस टीम का हिस्सा हैं। निकहत ज़रीन (51 किग्रा) ने मार्च के आखिर में होने वाली एशियन चैंपियनशिप जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के रास्ते में एक अहम कदम है - की तैयारी पर ध्यान देने के लिए इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है।

गुकेश ने नीमैन को बराबरी पर रोका

विक आन जी (नीदरलैंड्स)। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने टाटा स्टील मास्टर्स के 12वें चरण में रविवार को यहां हांस मोके नीमन के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने मैथियास ब्लूबाउम पर दमदार जीत दर्ज कर एकल बढ़त कायम करते हुए खिताब की ओर कदम बढ़ा दिया। जावोखिर सिंदारोव ने आर प्रज्ञानानंदा के खिलाफ कोई जोखिम नहीं लिया जिससे उन्हें ड्रॉ पर संतोष करना पड़ा। वह 7.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए। वह अपने हमवतन अब्दुसत्तोरोव से आधा अंक पीछे हैं। टूर्नामेंट में अब सिर्फ एक दौर का खेल बचा है और उज्बेकिस्तान के इन दोनों खिलाड़ियों ने शीर्ष दो स्थान के साथ साल के पहले सुपर-टूर्नामेंट में अपने देश का दबदबा कायम किया।

विदर्भ से हारकर यूपी रणजी ट्रॉफी से बाहर

नागपुर। गत चैंपियन विदर्भ ने रविवार को यहां उत्तर प्रदेश को चार विकेट से हराकर ग्रुप ए से आंध्र के साथ एलीट रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विदर्भ की टीम ग्रुप ए में आंध्र के बाद दूसरे स्थान पर रही। दोनों टीम ने सात मैच में समान 31 अंक हासिल किए लेकिन आंध्र की टीम बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर रही। उत्तर प्रदेश के 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विदर्भ की टीम ने चौथे और अंतिम दिन चार विकेट पर 91 रन से आगे खेलते हुए छह विकेट गंवाकर 58.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज अमन मोखाडे 150 गेंद में 83 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके मारे।

देविका सिहाग ने जीता पहला सुपर 300 खिताब

बैंकॉक, एजेंसी

भारत की युवा शटलर देविका सिहाग ने रविवार को यहां 250,000 डॉलर इनामी थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीता।

हरियाणा की रहने वाली 20 वर्षीय खिलाड़ी देविका तब 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी, जब विश्व में 68वें नंबर की खिलाड़ी और दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह ने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इससे भारतीय खिलाड़ी अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने में सफल रही। उन्होंने कहा मैंने शुरुआत से ही अच्छी गति बनाने की योजना बनाई थी और वह कारगर रही। मेरा मानना है कि वह थकी हुई थीं और उन्हें ऐंठन भी थी। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। देविका इस जीत के साथ सुपर 300 महिला एकल खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं। इससे पहले यह उपलब्धि केवल पीवी सिंधू और साइना नेहवाल ने हासिल की थी। विश्व रैंकिंग में 63वें स्थान पर काबिज देविका बेंगलुरु के पादुकोण-द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में कोच उमेंद्र राणा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके साथ ही वह इंडोनेशिया के रहने वाले कोच इरवानस्याह आदि प्रतामा की देखरेख में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू के साथ अपने खेल को निखार रही हैं। भारतीय खिलाड़ी क्रॉस कोर्ट और सीधे स्मैश लगाने की अपनी क्षमता और साथ ही बड़ी कुशलता से ड्रॉप शॉट लगाने से जल्द ही 9-2 से आगे हो गईं। इंटरवल तक उन्होंने 11-4 की बढ़त हासिल कर ली। गोह को देविका ने उन्हें कोर्ट पर खूब दौड़ाया।

प्रतिद्वंद्वी मलेशिया की गोह जिन वेई बीच से हटीं

देविका के लिए फाइनल शानदार रहा लेकिन उनकी प्रतिद्वंदी गोह को पीड़ा झेलनी पड़ी। वह फाइनल से पहले तीन गेम तक चले चार मैच खेलने के बाद थकी हुई लग रही थीं और उन्हें कोर्ट को कवर करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पिछले दो वर्षों से फॉर्म और फिटनेस के लिए संघर्ष कर रही गोह ने शनिवार को भी थकान की शिकायत की थी और उन्हें कोर्ट में चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी। उनका बायां पैर हिल नहीं पा रहा था और वह परेशान दिख रही थीं। देविका ने फाइनल में शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपने दमदार रिटर्न और बेहतरीन स्ट्रोक के दम पर 4-0 की बढ़त बना ली। एक नेट कॉर्ड की बदौलत गोह ने अपना पहला अंक हासिल किया। बाद में उन्होंने मुकाबला बीच में छोड़ दिया।

देविका ने चैंपियन बनने के बाद कहा आज मैं बेहद खुश हूं क्योंकि यह मेरा पहला सुपर 300 खिताब है। मैं भविष्य में और टूर्नामेंट खेलने को लेकर काफी उत्साहित हूं। उन्होंने कहा मैंने यहां बहुत अच्छे मुकाबले खेले। मैंने काफी कुछ सीखा है। यहां मिली सीख को मैं अपने खेल में लागू कर गलतियों को सुधारूंगी। मैच में उतरते समय मैंने जीत या हार के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपना 100 प्रतिशत देने पर ध्यान रखा। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला।
-देविका सिहाग

कार्लोस अल्कारेज ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलियाई ओपन : करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने वाले बने सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी

मेलबर्न, एजेंसी

कार्लोस अल्कारेज रविवार को यहां फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम करके करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम-ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

रिकॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच की मेलबर्न पार्क में फाइनल में यह पहली हार है। इससे पहले उन्होंने यहां अपने सभी 10 फाइनल में जीत दर्ज की थी। शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी अल्कारेज ने रविवार को पहला सेट गंवाया लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की। जीत दर्ज करने के बाद कोर्ट से जाते हुए अल्कारेज ने टीवी कैमरा के लैंस पर हस्ताक्षर करते हुए लिखा, 'काम पूरा हुआ। चार में से चार पूरे हुए।'

बाइस साल के स्पेन के खिलाड़ी ने 38 साल के जोकोविच पर दबाव बनाए रखा। जीत पक्की करने के बाद अल्कारेज ने हाथ से रैकेट छोड़ दिया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर गए और अपने हाथ सिर पर रख लिए। जोकोविच से हाथ मिलाने के लिए नेट पर जाने से पहले वह कुछ सेकेंड वहीं रुके। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ बातें कीं और जोकोविच स्पेन के खिलाड़ी को बधाई देते हुए मुस्कुराए। इसके बाद नया चैंपियन कोर्ट के एकतरफ लगी कुर्सियों पर बैठे अपने कोच को गले लगाने के लिए दौड़ा और बाद में स्टैंड में अपने पिता और टीम के दूसरे सदस्यों को भी गले लगा। पिछले सत्र के आखिर में अल्कारेज अपने पुराने कोच जुआन कार्लोस फरेरो से अलग हो गए थे और सैमुअल लोपेज उनकी कोचिंग टीम के प्रमख बने।

जोकोविच ने मजाक में कहा कि यह मुकाबला अगले 10 वर्षों के लिए अल्कारेज के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत करेगा। उन्होंने हालांकि बाद में कहा कि नए चैंपियन को आगे आने देना ही सही था। दोनों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पांच सेट में कड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों की तलाश में तीन घंटे से अधिक समय तक दोनों ने जबरदस्त फिटनेस, खेल और स्टेमिना का नजारा दिखाया। कोई भी खिलाड़ी बड़े अंकों पर हार मानने को तैयार नहीं था। स्पेन के खिलाड़ी ने 16 ब्रेक प्वाइंट में से पांच का फायदा उठाया जबकि जोकोविच छह ब्रेक प्वाइंट में से सिर्फ दो को ही अंक में बदल सके।

कोई नहीं जानता कि मैं यह ट्रॉफी पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। मैंने इस पल का बहुत पीछा किया। हमने बस सही काम किया, आप मुझे हर दिन सही काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मैं उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं जो अभी मेरे साथ हैं।
-कालोस अल्कारेज

सबसे पहले एक शानदार टूर्नामेंट और शानदार दो हफ्तों के लिए बधाई। आप जो कर रहे हैं उसे बताने के लिए सबसे अच्छा शब्द ऐतिहासिक, दिग्गज है इसलिए बधाई। मैं आपके बाकी करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
-नोवाक जोकोविच

- नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराया

करियर ग्रैंडस्लैम

जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम-ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब का इंतजार बढ़ा

नोवाक जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब जीतने के अभियान पर एक बार फिर अल्कारेज और यानिक सिनर में से एक ने रोक लगाई। इन दोनों ने मिलकर पिछले नौ ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में सिनर को हराया था और ओपन युगल में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनने की राह पर थे लेकिन अल्कारेज ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जोकोविच और स्पेन के रफेल नडाल ने कुछ जबरदस्त मैच खेले जिसमें 2012 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का अब तक का सबसे लंबा मैच भी शामिल है जो पांच सेट का फाइनल था और लगभग छह घंटे तक चला था।

अंडर-19 में शॉट लगाते वेदांत त्रिवेदी। एजेंसी

पाकिस्तान को हराकर भारत सेमीफाइनल में

बुलावायो, एजेंसी

वेदांत त्रिवेदी (68) की अर्धशतकीय पारी और निचलेक्रम के बल्लेबाजों की जुझारू पारियों के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अंडर-19 विश्वकप के 36वें मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है।

भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रनों का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान 33.3 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच सकता था। जिसमें वह विफल रहा। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 के स्कोर पर समेट कर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने समीर मिन्हास (नौ) का विकेट गंवा दिया। खिलन पटेल ने मिन्हास को पगबाधा आउटकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उस्मान खान और हम्जा जहूर ने पारी को संभाला और 88 के स्कोर तक ले गए।

17वें ओवर में आयुष म्हात्र ने उस्मान खान (66) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कप्तान फरहान यूसफ ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को 151 तक ले गये। पाकिस्तान 35.3 ओवरों तक पांच विकेट पर 168 रन ही बना सका।

अंडर-19 विश्वकप

- भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 252 रन
- पाक को सेमीफाइनल के लिए 33.3 ओवर में हासिल करना था लक्ष्य

भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान

कराची, एजेंसी

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने बहुप्रतीक्षित ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की रविवार को औपचारिक घोषणा कर दी, लेकिन सरकार ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा कदम, जिसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है।

सरकार के एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दिए गए इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। विश्व निकाय ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा, क्योंकि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में ''मैदान पर नहीं उतरेगी''। इस फैसले के साथ टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर चल रही अटकलों का दौर समाप्त हो गया है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहे इस टूर्नामेंट के बीच यह फैसला क्षेत्र में बढ़े राजनीतिक तनाव के माहौल में सामने आया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, " पाकिस्तान की सरकार आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी को मंजूरी देती है, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।'' भारत-पाकिस्तान मुकाबला किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बहुप्रतीक्षित मैच माना जाता है, जिसे वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दर्शक, प्रायोजकों की रुचि और प्रसारण राजस्व मिलता है। इस मुकाबले के बहिष्कार से आईसीसी के सामने लॉजिस्टिक और नियामकीय चुनौतियां खड़ी होने की आशंका है, क्योंकि टूर्नामेंट के कार्यक्रम, विपणन और व्यावसायिक रणनीति का बड़ा हिस्सा इसी मुकाबले के इर्द-गिर्द तैयार किया गया है।

वॉकओवर की स्थिति में भारत को पूरे अंक मिल जाएंगे। पाकिस्तान सात फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, इसके बाद 10 फरवरी को अमेरिका और 18 फरवरी को नामीबिया से भिड़ेगा।

- लेकिन टूर्नामेंट में भाग लेगा बांग्लादेश का ले रहा पक्ष

नॉकआउट चरण की स्थित स्पष्ट नहीं

पीसीबी या सरकार ने हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगर प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आते हैं तो क्या रुख अपनाया जाएगा।

यूपी की कप्तान मेग लानिंग का विकेट लेने के बाद जश्न मनातीं शिनेल हेनरी।

यूपी का सफर हार के साथ समाप्त

वडोदरा। मैरीजान कप्प (तीन विकेट), शिनेल हेनरी और श्री चारणी (दो-दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद लॉरा वुलफर्ट (47), जेमिमाह रॉड्रिग्स (नाबाद 34) और शेफाली वर्मा (29) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के 20वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्ज को आठ गेंदे शेष रहते पांच विकेट से हराकर एलिमिनेटर में जगह बना ली है। लगातार तीन सीजन फाइनल खेलने वाली मुंबई की टीम बाहर हो चुकी है। यूपी का सफर भी हार के साथ खत्म हुआ है। दिल्ली ने एलिमिनेटर में जगह बना ली है। उनके पास लगातार चौथी बार फाइनल खेलने का मौका है।

बढ़ा मनोबल | न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखला में सर्वाधिक रन बना बनाकर विश्व कप के लिए जता दिए इरादे

बल्लेबाजी में कुछ बदलाव से फॉर्म में लौटे सूर्यकुमार

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका शृंखला के बाद मिले ब्रेक और बल्लेबाजी में किए गए कुछ बदलाव से उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मदद मिली। सूर्यकुमार ने शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड पर भारत की 4-1 से जीत में आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए कुछ उम्दा पारियां खेली।

सूर्यकुमार पिछले साल रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। वह इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए थे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करके न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखला में सर्वाधिक रन बनाए और उन्हें शृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखला के बाद सूर्यकुमार ने आत्मचिंतन किया और अपने खेल में कुछ बदलाव किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार पारियों में वह केवल 34 रन बनाए थे, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 12 रन था। सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत की 46 रन से जीत के बाद कहा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखला के बाद मुझे ब्रेक मिला। मैंने घर लौटने पर अपना किट बैग एक तरफ रखा और नौ-दस दिन तक आराम किया। उन्होंने कहा नए साल की शुरुआत से ही मैंने फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया और पिछले साल की कमियों पर विचार किया। विशेष रूप से शुरुआती ओवरों में मेरे स्ट्राइक रेट पर मैंने चिंतन किया। सूर्यकुमार ने कहा मैं 2021-23 में शुरुआती पांच-दस गेंदों पर आक्रामक बल्लेबाजी करता था और मेरा स्ट्राइक रेट 200-250 रहता था। अब मैं शुरुआती पांच-सात गेंदों पर संभलकर खेलता हूं और उसके बाद अपना स्ट्राइक रेट दोगुना कर लेता हूं। नागपुर में खेले गए पहले ही मैच से यह रणनीति कारगर साबित हुई, जिससे मुझे लय मिली और मेरी फॉर्म में सुधार हुआ।

भारत के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों में से एक सूर्यकुमार को कप्तानी संभालने के बाद से लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने 2025 में 21 मैचों में केवल 218 रन बनाए। उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पांच मैचों में 80.66 के औसत और 196.74 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए। भारत की निगाहें अब लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने पर हैं।

टीम संयोजन को बनाया गया है बेहतर

सूर्यकुमार ने कहा कि गेंदबाजी से समझौता किए बिना बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए टीम संयोजन को भी बेहतर बनाया गया है। उन्होंने अपने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा हर खिलाड़ी अपनी अनूठी पहचान लेकर आता है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, सभी राज्य और फ्रेंचाइजी स्तर पर अपनी शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं। मैंने उन्हें अपनी शैली पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। सूर्यकुमार ने कहा कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर-बल्लेबाज को लेकर अंतिम फैसला शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ विश्व कप के पहले मैच से पहले लिया जाएगा।